

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

₹io 7]

नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 12, 1983 (माघ 23, 1904)

No. 71

NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 12, 1983 (MAGHA 23, 1904)

इस भाग में भिन्न पूष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके (Separate raging is given to this Part in order that it may be filed as a separate Compilation)

[PART III-SECTION 4]

बिधिक निकामों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय स्टेट बैक

मुचना

नई दिल्ली, दिनाक 12 फरवरी 1983

इसके द्वारा भूचना दो जाती है कि भारतीय स्टेट बैंक का मुख्य रजिस्टार एवं शाखा रजिस्टर, शेयर अन्तरण के लिये गुरुवार, दिनाक 10 मार्च, 1983 से गुरुवार, दिनाक 24 मार्च, 1983 (दोना दिन सम्मिलिन) तक नद रहेगे।

> आर० पी० गोयल, अध्यक्ष

भारतीय चार्टरड प्राप्त लेखाकार सस्थान

नई दिल्ली-110002, दिनाक 10 जनवरी 1983 मं० 5-मी०ए० (17)/82-83- इस सस्थान की जीवस

मं० 5-सी०ए० (17)/82-83- इस गस्थान की अधिसूपना न० 4-मी०ए० (1)/i1/81-82 दिनांक 17-3-1982, 4-सी०ए० (1)/20/77/78 दिनाक 18-2-1978 और 4-मी० ए० (1)/29-80 दिनाक 15-3-1980 के सदर्भ 4म चार्टरड प्राप्त लेखाकार विशेषम 1954 के विशिधन

459GI/82 من

18 के अनुसरण मे एतद्दारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों के विनियम 17 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये भारतीय चार्टरड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद् ने अपने सदस्यता रिजस्टर में निम्निलिखित सदस्यों का नाम पुन: उनके आगे दी गई तिथि से स्थापित कर दिया है।

茶 の代の	सदम् बता संख्या	नाम एव पता	दिनाक
1	2	3	4
1.	6688	श्री मनुभाई, अम्बालाल पटेन ए०मी(०ए० प.० ओ० बोक्स 60049 विवास्टोन	11-12-82
2.	11633	थी रमेश चन्द्रा तामनय, ए०भी०ए०, 5 र्थ०/2, बी० पी०, रेलच रोड, फरीदाबाद−121001	16-12-82

(1349)

1	2 .	31.	4	1	2	3	4
O O	30 15 2.		1-11-82	6.	80027	श्री विगित कपूर, ए०सी०ए०, 107, हरीनगर, ग्राश्रम, नई दिल्ली–110014	1-4-82
		पार्वाह, 6145; भारताह, (यूव्हावई०) दिनाक 21 जनवरी 1983		7.	80648	श्री मुरेश छाबरा, ए०सी०ए०, 10400, गली मन्दिर वार मानक पुरा, नई दिल्ली–110005	1-4-82 नी,
विनिशम के अनु निम्नोंद उनके उ	ा 1964 है सरण में ए खित सदस्ये तमें दी गई	(31)/82-83चार्टर्ड प्राप्त के विनियम 10 (1) खंड तद्द्वारा यह सूचित किया ज ो को जारी किए प्रैक्टिस तिथियों में रह कर दिये गए प्रमाण-पन्न की रखने के इच्छुब	ड (सीन) ाता है कि प्रमाण-पत्न है क्योंकि	8.	80694	श्री मुरेश कुमार मित्तल, 'ए०सी'०ए०, 1/9225, गली चं० 6, वेस्ट रोहतास नगर, शाहदरा, दिल्ली-110032	1-4-82
-, ज्ञ्चं o	सदस्यता संख्या 2	नाम एवं पता 3	दिनांक	9.	80743	श्री राजन जौली, ए०सी०ए०, बी०-2/5 राना प्रताप बाग नई दिल्ली 110007	1-4-82
1.	8480	श्री कस्तूरी लाल कुमार, ए०सी०ए०, रक्काफोर्म लि०, गी० ओ० बोक्स, 434, कृत्डिका रोड, कानो, नाइजिन्धा,	1-4-82	10.	80752	भी प्रेम चन्द जैन, ए०सी०ए० 7109, पहाड़ी धीरज गली पहाड़ वाली, दिल्ली—110006	1-4-82
2.	8549	काता, पाश्राजास्या, श्री बिरेन्द्र कुमार गुप्ता, एफ०मी०ए०, जो०सी०एम० इण्डिया लि० पी० वं (० नं० 34,	1-4-82	11.	80835	श्री विजय सेंठ, ए०सी०ए०, मी०–53, डिफेंस कालोनी, तई दिल्ली–110024	1-4-81
3.	16760	अमृतसर श्री सुशील कुमार, एफ०सी०ए०, 227, सैषटर, 19ए, चण्डीगढ़	1-4-82	12.	80877	श्री नरेण शंकर, ए०सी०ए०, 3, बेला रोड, सिविल लाइन्म, दिल्ली——110054	1-4-81
4	17536	श्री अर्थोक कुमार, ए०मी०ए०, मैसर्स ए० आर० कुमार एंड कम्पनी, बार्टरड एकाउन्टैन्टस, एफ० 105, कीर्ति नगर, नई दिल्ली—110015	1-4-82	13.	81567	श्री चन्दर मोहन, खुराना ए०सी०ए०, सी०एम० खुराना एंड कं० चार्टरड एकाउन्टैन्टम 999, तेलीअन स्ट्रीट, तिलक बाजार, दिल्ली-110006	11-1-83
5.	70373	श्री लॉलन बिहारी सिन्धन, ए०मी०ए० सी/ओं मैसर्स पृगत किशोर काशीराम, ग्रेन मार्केट रोहनक-124001	1-4-82	14.	50016	श्री अरुन कुमार खन्ना, गृफ्किशिक्ष्य, ई०-85, कीर्ति नगर, नई दिल्ली-110015	1-8-82

दिनांक 27 जनवरी 1983

(बार्टरड एकाउन्टैन्टम)

सं० 1-सी०ए० (117) 2/79-- चार्टरड एकाउन्टैण्टस एकट, 1949 (1949 का 38 वॉ) के भाग 30 के उपभाग (1) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये दि काउन्सिल आफ दि इंस्टीट्यूट आफ चार्टरड एकाउन्टैटस आफ इंडिया ने चार्टरड एकाउन्टैन्टस रेगूलेशन्य 1964 में निम्नांकित संशोधन किये हैं, जो उपर्युक्त भाग के उपभाग (3) के अधीन प्रपेक्ति पहले ही प्रकाशित और केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत किये जा चुके हैं।

उपर्युक्त रेगूलेशन्स में वर्तमान वास्तिविक रेगूलेशन 23 के लिये निम्नोकित बदल लें:---

"23 मुल्क की वापसी

- (1) किसी श्रभ्यर्थी द्वारा जिसे परीक्षा में सिम्मिलित किया गया है, जमा किया गया गुल्क, केवल उन मामलों को छोड़कर जिनकी व्यवस्था उप-रेगूलेशन (2) में की गई है, वापस नहीं किया जायेगा।
- (2) जब कि अध्यर्थी परीक्षा के अंतिम दिन से
 15 दिन के अन्दर कौसिल को उसके नियंद्रण
 से बाहर के उन कारणों को जिनके फलस्वरूप
 वह परीक्षा में सम्मिलित होने से रोक दिया
 गया, सूचित कर देता है तो कौसिल अध्यर्थी
 द्वारा अदा कियें गये उचित शुल्क का 50 प्रतिशत
 उसे वापस करने की अनुमति दे सकती है।"

पी० एस० गोपालाकृष्णन् सचिव

कानपुर-208001, दिनांक 13 जनवरी 1983

सं० 4—सी०सी०ए० (3)/82-83—चार्टरेड प्राप्त लेखाकार विनियम 1964 के विनियम 16 के प्रनुसरण में एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि चार्टरेड प्राप्त लेखाकार प्रधिन्यम 1949 की धारा 20 उपधारा 1 (क) द्वारा प्रदत्त प्रधिकारों का प्रयोग करते हुये भारतीय चार्टरेड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद् ने प्रपंने सदस्यता रिजस्टर में से मृत्यु हो जाने के कारण निम्नलिखित सदस्यों का नाम उनके भ्रागे दी गई तिथि से हटा दिया है।

ऋ०सं०	सदस्यता संख्या	नाम एवं पता	दिनांक
1.	1397	श्री श्रीकृष्ण कपूर, 16/98,एल० श्राई०सी०, बिल्डिंग दी माल, कानपुर—208001	7-11-82

दिनांक 19 जनपरी 1983

मं० 4-सी०सी०ए० (4)/82-83--चार्टरङ प्राप्त लेखाकार विनियम 1964 के विनियम 16 के प्रानुसरण में एतदृद्धारा यह सूचित किया जाता है कि चार्टर प्राप्त लेखाकार प्रधि नियम 1949 की धारा 20 उप धारा 1 (क) द्वारा प्रदत्त प्रधिकारों का प्रयोग करते हुये भारतीय धार्टरङ प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद ने अपने सदर्भता रिजम्टर में ने मृत्यु हो जाने के कारण निम्नलिखित सदस्य का नाम उनके ग्राग वी गई तिथि से हटा दिया है।

क्र०सं०	सदस्यता संख्या	नाम एवं पता	दिनांक
1.	9764	श्री पुरुषोत्तम दास गुप्ता, 46, श्रलिमपुरा सी०ए०बी० कालेज के पा मेरठ कैन्ट	9-7-81 स
	\	पी० एस०	 गोपालाक्टण्णन् स चि व

मद्रास-600034, दिनाक 17 जनवरी 1983

मं० 5-एस०सी०ए० (7)/82-83--इस संस्थान की प्रधिसूचना नं० 4-एस० सी० ए० (1)9/79/80 दिनांक 15-3-1980 ग्रीर 4 ई० सी०ए० (1)/12/78-79 दिनांक 28-12-1979 के संदर्भ मे चार्टरङ प्राप्त नेखाकार विक्यम 1964 के विनियम 18 के प्रमुसरण मे एतद्द्वारा यह स्जित क्या जाता है कि उक्त विनियमों के विनियम 17 द्वारा प्रदत्त ग्रिधकारों का प्रयोग करते हुये भारतीय चार्टरङ प्राप्त नेखाकार मंस्थान परिषद् ने ग्रपने सदस्यना रिजस्टर मे से निम्निलिखित रादस्यों का नाम पुन: उनके श्रागे दी गई तिथि से स्थापित कर दिया है।

ऋ०सं०	सदस्यता संख्या	नाम एवं पता	दिनांक
1.	2447	श्री कि वी मुख्या राव, एफ ब्सी ब्ए ब् चार्टरड एका उन्टेन्टम, 1-8-702/19/ए, नल्लाकुन्टा, हैदराबाद-500044	1-8-82
2.	50269	श्री के बे के बढ़ा, ए ब्सी ब्ए ब्रिंग ए – 5, गनेश ग्रपार्ट मेंट्स, 14 डी, सिल्या रोड, मझ्लापुर, मद्राम – 600004	21-12-82

पी० एस० गोपालाकृष्णन सचिव

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 24 जनवरी 1983

16(53)/82-चिकित्सा-3 (गुजरात)---कर्भ-बीमा (सामान्य) विनियम 1950 के राज्य विनियम 105 के तहत मुझे निगम की मक्तियां प्रदान करने के संबंध में पास किये गये संकल्प के श्रनुसरण में, मैं इसके द्वारा डा० जे० बी० लक्कड़ को बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण पत्नों की मत्यता में संदेह . होने पर उन्हें भ्रागे प्रमाण पत्न जारी करने के प्रयोजन के लिए दिनांक 1-1-83 से 30-6-83 तक बड़ौदा केन्द्र के लिये चिकित्सा प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिये प्राधि-कृत करता हूं।

दिनांक 28 जनवरी 1983

सं० यू०-16/53/82-चिकित्सा-3 (पंजाब)-—कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम 1950 के विनियम 105 के तहत मुझे निगम की शक्तियां प्रदान करने के संबंध में पास किये गये संकल्प के श्रनुसरण में, मैं इसके द्वारा सिविल सर्जन सिविल ग्रस्पताल, कपूरथला, को रुपये 75/- प्रतिमाह के पारिश्रमिक पर, बीमाक्रुत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण पत्नों की सत्यता में संदेह होने पर उन्हें प्रमाण पत्न जारी करने के प्रयोजन के लिये जगजीत नगर केन्द्र के लिये चिकित्सा प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिये प्राधिकृत करता हूं। यह नियुक्ति 15-2-1983 (पूर्वाह्म) से उनके देन्द्र में पूर्ण-कालिक चिकित्सा निर्देशों की नियुक्ति किये जाने तक की गई हैं।

> डा० के० एम० सक्सेना, चिकित्सा भ्रायुक्त

भारतीय विधिज्ञ परिषद्

मई दिल्ली, दिनांक 15 जनवरी 1983

भाग IV मे भारतीय विधिज्ञ परिषद् के नियमों का संशोधन निम्नलिखित प्रस्तावों में उपवर्णित रूप में किया गया हैः——

प्रस्ताय सं० 83/1982

यह संकल्प किया गया कि भाग IV के नियम 2 का संगोधन नियम 2 के श्रन्त में श्राने वाले "जिला सरिकट न्यायालय हैं" शब्दों के पश्चात् ''या उससे उतनी दूरी के म्रान्दर श्रवस्थित होगा जितनी दूरी के लिये भारतीय विधिज्ञ परिषद प्रनुज्ञा देती है" शब्दों को जोड़ कर किया जाए ।

यह भी संकल्प किया गया कि यह नियम संशोधन करने के पश्चात् निम्नलिखित रूप में पढ़ा जाएगा :

"विधि महाविद्यालय ऐसे स्थान पर ही श्रवस्थित होगा जहां जिला न्यायालय या जिला सरकिट न्यायालय है या उससे उतनी दूरी के श्रन्दर भ्रवस्थित होगा जितनी दूरी के लिये भारतीय विधिज्ञ परिषद् श्रनुज्ञा देती है।"

यह ग्रीर भी संकल्प किया गया कि यह स्पष्ट कर दिया जाए कि यह नियम भविष्यलक्षी रूप से प्रवृत्त होगा।"

प्रस्ताव सं० 84/1982

यह संकल्प किया गया कि राजनीति शास्त्र के तीन प्रश्नपत्र (राजनीति शास्त्र \mathbf{I} , राजनीति शास्त्र $\mathbf{I}^{\mathbf{I}}$ भ्रौर राजनीति शास्त्र III) होने चाहिये। स्रतः विधिपूर्व पाठ्यऋम में सात प्रनिवार्य विषयों को, जो दस प्रनिवार्य प्रश्न पहों में होंगें, विहित करने के लिये इस नियम का समृचित संशोधन निम्नलिखित रूप में किया जाना चाहिये:---

- 1— साधारण अंग्रेजी (स्नातक स्तर)—दो प्रक्रन पञ्च साधारण श्रंग्रेजी भाग I श्रौर भाग II
- 2-- राजनीति शास्त्र (राजनीति शास्त्र भाग I, भाग II ग्रौर भाग III) ---तीन प्रश्न पत्न
- 3-- ग्रर्थशास्त्र
- --एक प्रश्नपक्ष
- 4-- इतिहास ·—एक प्रश्न पत्न
- 5-- समाजशास्त्र --एक प्रश्न पन्न
- 6— विधि की भाषा जिसमें विधिक लेखन भी है ––एक प्रश्न पत्न
- 7— भारत में न्यायालयों, विधान मण्डलों ग्रीर विधि व्यवसाय का इतिहास ---एक प्रश्न पत्न

भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा 7 मई, 1982को भ्रापने अधिवेशन में पारित प्रस्ताव।

प्रस्ताव सं० 79/1982

यह संकल्प किया गया कि भ्रधिवक्ता भ्रधिनियम की धारा 7 (ज) श्रीर (श) धारा 24 (1) (ग) (iii) ग्रौर $(^{\mathrm{ii}\mathrm{i}}$ क) तथा धारा 49 (1) (कच), (कछ) ग्रौर(घ) के प्रधीन परिषद के नियमों के भाग i में प्रधिवक्ता के रूप मे प्रवेश के लिये विधि शिक्षा के मानकों के संबंध में विद्यमान नियमों के बदले में निम्नलिखित नियम श्रपनाए

यह भी संकरूप किया गया कि ये नियम 7 मई, 1982 से प्रवत्त होंगे।

ऐसे छात्रों के लिये, जो पुराने नियमों के श्रधीन परीक्षा नहीं दे सके हैं समय बढ़ाने के प्रश्न परबाद में विचार किया जाएगा ।

> भारतीय विधिज्ञ परिषद की की मुहर

भारतीय विधिज्ञ परिषद नियम

भाग 17

ग्रधिवक्ता ग्रधिनियम, 1961 की धारा 7 (ज) भीर (स), धारा 24(1) (ग) (iii) श्रीर (iiiक) तथा धारा 49 (1)(कप) (कछ) ग्रीर (ध) ने अधीन तैयार हिए गए विधि शिक्षा के मानक श्रार विधि उपाधियों की मान्यता

भाग IV मे भारतीय विधिक्ष परिषद नियम की उद्दर्शिका

यिधि की शिक्षा में श्रामृत परिवर्तन और सुधार करने की श्रावण्यकता के बारे में देण अर में रागभग पूर्ण रूप से सर्व-सम्मति है,

तमय समय पर किये गये शाशिक परिवर्तनो से बार (श्रिधिवक्ता वर्ग) में नाग प्रवेशकर्नाशा के स्तर ग्रोर उनकी गुणवत्ता म कोई विशेष उन्नति या सुधार नही हम्रा है।

भारतीय विधिन्न परिषद का यह कानूनी दायित्व है कि वह विधि गिक्षा की श्रिभवृद्धि कर श्रीर दाद में प्रवेश के प्रयाजनों के लिये ऐसी शिक्षा के मानक श्रिधकिथत करे,

भारतीय विधिज्ञ परिषद की विधि-शिक्षा समिति ने विश्वविद्यालयो और राज्य विधिज्ञ परिषदो के परामर्श से इस समस्या का गहन श्रध्ययन करके श्रपने प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं,

भारतीय विधिक्ष परिषद ने उक्त प्रस्तावों के प्रशाबी श्रीर गुणदोषों पर विचार कर ालया ह,

प्रर श्रव पारे विश्व में यह ताल मान ली गई है वि विधि के लक्ष्मीका ज्ञान के श्रांतिरित एसी व्यापक शिक्षा श्राव्ययव है जिसमें शिक्षा की श्रन्य पाखाश्री तथा ज्ञान के श्रन्थ क्षता की विशेषकर मानविकी विषयों की जानकारी हो जिससे कि विधि व्यवसायी सामाजिक परिवर्तन श्रीर विकास में उपयोगी योगदान कर सके,

भ्रत यह परिषद श्रधिवयता श्रिविनियम, 1961 की धारा 7 (ज) श्रीर (झ), धारा 24 श्रीर धारा 49 (1) के श्रधीन भ्रपनी शिक्तयो का तथा ऐसी सभी श्रन्य शिक्तयो का, जो उसे ऐसा करने के लिये समर्थ बनाती है, प्रयोग करते हुये निम्नलिखित नियम बनाती है ——

भाग IV

विधि णिक्षा के मानक ग्रौर प्रधियक्ता के रूप मे प्रवेश के लिये विधि उपाधियो की मान्यता

[ग्रिप्रिवक्ता ग्रिप्तिमिम 1961 की धारा 7 (च) ग्रांर (झ) धारा 24 (1) (ग) (111) ग्रोंर (111) तथा धारा 49 (1) (कच) (कछ) ग्रोंर (घ) के ग्रिप्तीन नियम]

- 1. (1) इसमें इसके भ्रागे नियम 23, 24 भ्रीर 25 में जैसा उपबन्धित है उसके सिवाय, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी विश्वविद्यालय से प्राप्त विधि की उपाधि को 1 जून 1982 से श्राधिवक्ता श्राधिनियम, 1961 के भ्राधीन श्राधिवक्ता के रूप में नामाकन के प्रयोजनों के लिये भी तभी मान्यता वी जाएगी जव निम्निखिल शर्त पूरी कर दी जाती है
 - (क) यह कि सम्पृक्त व्यक्ति ने विधि की उपाधि के लिये विधि के शिक्षण--पाठयक्रम में प्रवेश करते

सम्य केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारो के शैक्षणिक प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय पाठ्यक्रम की 10+2 की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है या वह ऐसी शैक्षणिक श्रपर्हताये रखता है जिन्हे भारतीय विधि परिषद 10+2 पाठ्यक्रम के बराबर समझती है।

- (ख) यह कि इन नियमा के अधीन सम्यक् रूप से मान्यता प्राप्त विधि महाविद्यालय में कम-से-कम पाच वर्ष की अविधि तक नियमित पाठ्यक्रम का शध्ययन करके विधि की उपाधि प्राप्त की गई है, ग्रांर इन पाच वर्षों में से प्रथम दो वर्ष विधि पूर्व पाठ्यक्रम का अध्ययन करने में व्यतीत किए गये हैं जो उसके पश्चात् प्रारम्भ होने वाले तीन वर्ष के विधि पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के लिये श्रावश्यक अर्हता के रूप में हैं। तीन वर्ष के विधि पाठ्यक्रम के श्रावित्रम कहा माम में व्यावहारिक प्रशिक्षण का नियमित पाठ्यक्रम सम्मिलत होगा।
- (ग) यह कि विधि पाठ्यक्रम का श्रध्ययन भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा भान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय मे दिए गए व्याख्यानो, ट्यूटोरियला, छान्न न्यायालयो (सूट कोर्ट, मे नियमित रूप से श्रपेक्षित बार उपस्थित होकर श्रोर व्यावहारिक प्रणिक्षण प्राप्त करके किया गया है।
- 2 विधि महाविद्यालय ऐसे स्थान पर ही श्रवस्थित होगा जहा जिला न्यायालय या जिला सरिकट न्यायालय है।
- 3 (1) शैक्षणिक वर्ष 1982-83 से व्यावशायिक विधि शिक्षा केवल पूर्णकालिक दिन के महाविद्यालयो या विश्व-विद्यालयो के विभागो द्वारा ही दी जाएगी

परन्तु ऐसे विश्वविद्यालय, जो 1 जून 1982 से नए नियमों को लागू नहीं कर सकते हैं, भारतीय विधिन्न परिषद को सूचना देकर पुरानी पद्धित को 1982-83 से अधिक से अधिक दो वर्षों को अविधि के लिये जारी रख सकते हैं। ऐसी सूचना के पश्चात् उक्त विश्वविद्यालय नियम 23 की अपेक्षाओं का अनुपालन करेंगे

परन्तु यह श्रौर कि ऐसे छात, जो 1 जून, 1982 से पहले एल० एल० बी० के प्रथम वर्ष मे प्रवेश पा चुके है, यथास्थित, श्रशकालिक प्रात. या साध्य महाविद्यालयों में श्रपनी शिक्षा ग्रहण कर सकते है।

(2) उप नियम (1) के प्रयोजन के लिये किसी महा-विद्यालय को उस दिशा मे पूर्णकालिक दिन का महाविद्यालय ममझा जाएगा जब कि महाविद्यालय या विश्वविद्यालय के विभाग मे कार्य-समय का विस्तार प्रत्येक कार्य दिवस को कम-से-कम निरन्तर साढ़ें पांच घंटे के लिये हो जिसमें कक्षाग्रों में शिक्षा सम्मिलत है ग्रीर इसके ग्रन्तर्गत एक-एक घंटे के कम से-कम चार पीरियड भी होंगे ग्रौर कार्य समय के शेष हेढ़ घंटे महाविद्यालय के परिसर (कैम्पस) में शिक्षकों के साथ सम्पर्क कार्यक्रमों, पुस्तकालय-कार्य ट्यूटोरियल कार्य तथा इसी प्रकार की पाठ्यचर्या ग्रौर पाठ्य विषयतर चर्चा में व्यतीय किए जायेंगे।

- (3) महाविद्यालय या विश्वविद्यालय के विभाग का पुस्तकालय प्रत्येक कार्य दिवस को कम-से-कम ग्राठ घटे के लिये खुला रहेगा।
- (4) श्रंणकालिक शिक्षकों की संख्या शिक्षकों की कुल संख्या के पचास प्रतिणत से श्रधिक नहीं होगी ।
- (5) महाविद्यालय का प्रधानाचार्य साधारणतया महा-विद्यालय का पूर्णकालिक शिक्षक होगा।
- 4. शिक्षा का माध्यम साधारणतया श्रंग्रेजी भाषा होगी। जहां विधिकी शिक्षा ंका माध्यम ग्रंग्रेजी नहीं है या जहां छाल ने विधि परीक्षा के प्रश्नपत्नों का उत्तर वस्तुत: श्रंग्रेजी से भिन्न किसी भाषा में दिया है वहां उसके नामांकन के लिये गर्त के रूप में उससे यह श्रपेक्षा की जायेगी कि वह राज्य विधिज्ञ परिषद द्वारा संचालित ''श्रंग्रेजी में प्रवीणता'' का लिखित परीक्षण उत्तीर्ण करें किन्तु तब नही जबिक वह विधि-शिक्षा के श्रपने पाठ्यक्रम के भाग के रूप में ऐसे परीक्षण में उत्तीर्ण हो चुका है।

स्पष्टीकरण:—-उपर्युक्त परीक्षण में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के स्नातक उपाधि (बैचलर्स डिग्री) के धारक के स्तर का ज्ञान श्रपेक्षित होगा।

5. विधि णिक्षा के पाठ्यक्रम में छात्न को प्रवेश साधारण-तया योग्यता के स्राधार पर होगा । किसी भी छात्न को विधि णिक्षा के पाठ्यक्रम में तभी प्रवेश मिलेगा जब कि उसने स्रन्य बातों के माथ-माथ प्रवेश के लिये स्रहंता परीक्षा में कुल मिलाकर पैतालीस प्रतिशत स्रंक प्राप्त किए हों:

परन्तु श्रनुसूचित जातियों श्रौर श्रनुसूचित जन-जातियों के छात्नों को श्रह्ता-परीक्षा में पांच प्रतिणत तक की छूट दी जा सकेगी ।

- 6. छात्रों से यह अपेक्षा की जायेगी कि प्रत्येक विषय के व्याख्यानों में श्रौर ट्यूटोरियल, विद्यार्थी न्यायालय तथा व्यावहारिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भी उनकी उपस्थिति कम-से-कम 66 प्रतिशत हो ।
- विधि महाविद्यालय श्रौर विश्वविद्यालय विधि विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि :---
 - (क) विहित ग्रौर ग्रनुशसित (सुझाई गई) पठन सामग्री की ग्रनेक प्रतियां पुस्तकालय में उपलब्ध हैं,

- (ख) वाचनालय में छात्रों की कुल संख्या के कम से-कम पन्द्रह प्रतिशत छात्रों के लिये बैठने की व्यवस्था की गई है;
- (ग) शिक्षकों श्रौर छास्नों का परस्पर श्रनुपात कम-से कम 1:40 का है।
- 8. किसी भी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय के विधि विभाग में किसी कक्षा (एल०एल० बी० I, II, III, IV या V) में छात्रों की ग्रधिकतम संख्या 320 से ग्रधिक नहीं होगी ग्रौर ऐसी प्रत्येक कक्षा के किसी ग्रनुभाग (सेक्शन) में छात्रों की संख्या 80 से ग्रधिक नहीं होगी। दूसरे शब्दों में कोई महाविद्यालय या विश्वविद्यालय के विधि विभाग में पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे ग्रौर पांचवें वर्ष में सभी छात्रों की कुल संख्या 1600 से ग्रधिक नहीं होगी।
 - 9. भवन
- (1)(क) महाविद्यालय का भवन महाविद्यालय के कार्य समय के दौरान उसके श्रनन्य उपयोग के लिये उपलम्य होगा।
 - (ख) कक्षाओं, छात्रावास, यदि कोई हो तो, के लिये स्थान श्रौर प्रधानाचार्य तथा उस शिक्षक के लिये जो छात्रावास का, यदि कोई है तो, भारसाधक है, श्रावास श्रलग-श्रलग होंगें।
 - 2. महानिद्यालय के भवनों में निम्नलिखित स्थान होंगें:---
 - (क) कक्षाभ्रों के लिये कमरे :—
 छात्रों के लिये एक कामन रूम
 छात्राओं के लिये एक कामन रूम
 एक पुस्तकालय जिसमें पुस्तकों रखने के लिये फलक
 (बुक गैल्फ)हों।
 भ्रोर पढ़ने के लिये मेजें हों,
 प्रधानाचार्य भीर उसके कार्यालय कर्मचारियृन्द
 के लिये कार्यालय कमरे हों,
 शिक्षकों के लिए एक कामन रूम हो।
 - (ख) प्रधानाचार्य के लिये श्रावास

यदि कोई छान्नावास है तो उसके भारसाधक शिक्षक के लिये छान्नावास के निकट श्रावास हो।

जब कभी विश्वविद्यालय को अन्य स्थायी शिक्षकों के लिये आवास की आवश्यकता हो तो उनके लिये आवास हों।

- 3. (क) सभी भवनों में रोशनी की अच्छी व्यवस्था होगी और वे, हवादार होंगे तथा उनमें सफाई और जल प्रदाय की पर्याप्त व्यवस्था होगी।
 - (ख) सभी भवन ठीक तरह से सज्जित होंगें।
- 4. (क) यदि महाविद्यालय का कोई अपना भवन नहीं है और उसे किंद्राये के भवन में अस्थायी रूप से चलाने का प्रस्ताव है तो महाविद्यालय के प्राधिकारी भवन-निधि सर्जित करेंगे जो अलग रखीं

जाएगी और किसी अनुसूचित बैंक या जिला केन्द्रीय सरकारी बैंक मे जमा की जाएगी।

- (ख) कम से कम दो लाख रुपये की यह भवन निधि निम्निलिखिन किस्तो में सिजित की जाएगी: --
 आरम्भिक 1,00,000.00 रुपये पहली वर्ष 40,000 00 रुपये दूसरा वर्ष 20,000.00 रुपये तीसरा वर्ष 20,000.00 रुपये चौथा वर्ष 20,000.00 रुपये
- (ग) महाविद्यालय के नाम में इस प्रकार जमा रकम तथीं निकाली जाएगी तब कि पहले से स्निमित भवन के किसी भाग की लागत को पूरा करना प्रपेक्षित हो, ग्रन्थणा नहीं।
- (ष) सम्बद्ध विश्वविद्यालय के कुलसचिव को सम्बद्ध किए जाने का अनुमोदन जिस तारीख को संसूचित किया जाता है उस तारीख से चार वर्ष की अविध के भीतर भवनों का सन्निर्माण पूरा कराना होगा।
- (5) खेल-मैदान के लिये भी व्यवस्था की जायेंगी और महाविद्यालय-भवनों के आस पास खेल और क्रीडा के लिये पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध कराई जाएंगी ।

10. पुस्तकालय

- (क) महाविद्यालय में जिन शिक्षा-पाठ्यक्रमों की शिक्षा दी जाती है उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पुस्तकालय में विधि-रिपोर्टें, पुस्तकें-पत्न पत्निकायें और संदर्भ-पुस्तकें पर्याप्त रूप में रखी जायेंगी ।
- (ख) अर्हनाप्राप्त और प्रशिक्षित पुस्तकालयाध्यक्ष पुस्त-कालय का भारसाधक होगा।
- (ग) पुस्तकालय के लिये आरम्भिक न्यूनतम और वार्षिक आवर्ती व्यय निम्नलिखित रूप में होगा :-
 आरम्भिक 50,000.00 रुपये पहला वर्ष 15,000.00 रुपये दूसरा वर्ष 15,000.00 रुपये तीसरा वर्ष 15,000.00 रुपये परवर्ती वर्षों में प्रतिवर्ष 10,000.00 रुपये
- 11- (1) विधि उपाधि पाठ्यक्रम के प्रारम्भिक अध्ययन के लिए शिक्षा-पाठ्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित सात अनिवार्य विषय होंगें:—
 - साधारण अंग्रेजी (स्नातक स्तर) दो प्रश्नपत्न
 राजनीति-शास्त्र एक प्रश्नपत्न
 - अर्थशास्त्र एक प्रश्नपत्न
 - 4. इतिहास एक प्रश्नपन्न
 - समाजशास्त्र एक प्रश्नपत्न

- 6. विश्विकी भाषा जिसमें विश्विक लेखन भी हैं एक प्रश्नपद
- और विधि व्यवसाय का उतिहास एक प्रश्नपत्र स्पष्टीकरण:—भारतीय विधिज्ञ परिषद् ने विशेषज्ञों से परामर्श करके प्रारम्भिक चरण के पाठ्यक्रम को जायोगिक रूप रेखा बनाई है और यह विधि की व्यावसाधिक जिक्षा प्रदान करने वाले विश्वविद्यालयों से उसके लिये सिफारिश

7. भारत में न्यायालयों, विधान मण्डलों

 तीन वर्ष के विधि-अध्ययन के लिये शिक्षा पाठय-क्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित बारह अनिवार्य विषय होंगें :

कर रही है। मूझाए गए पाठ्यक्रम की रूपरेखा इन नियमों

के साथ परिणिष्ट ''क'' से ''छ'' के रूप में संलग्न है।

- 1. (क) संविदा के साधारण सिद्धांत एक प्रश्नपत्न
 - (ख) विशेष संविदा एक प्रश्न पत्न
- दुष्कृति एक प्रश्न पत्न
- 3. कुदुम्ब विधि
 - (क) हिन्दू विधि एक प्रश्नपत्न
 - (ख) मुस्लिम विधि, भारतीय उत्तरा-धिकार अधिनियम और भारतीय

विवाह-विच्छेद अधिनियम एक प्रश्नपत्न

- 4. अपराध विधि और प्रक्रिया दो प्रश्नपत्न
- 5. भारत की सर्वेधानिक विधि एक प्रण्नपत्न
- सम्पत्ति विधि और सुखाचार एक प्रश्तपत्न
- 7. साक्ष्य एक प्रश्नपञ्च
- ৪. विधिक सिद्धांत (विधि-शास्त्र) एक प्रश्नपत्र
- सिविल प्रिक्रयाएं, परिमीमा और

माध्यस्थम् एक प्रश्नपद्म

- 10 प्रशासनिक विधि ,
- एक प्रश्नपत्न
- 11. लोक अन्तर्राष्ट्रीय विधि एक प्रश्नपत्न
- 12. व्यवहारिक प्रशिक्षण:—छह मास की शिक्षा के अन्तर्गत न्यायालयों में जाना, दस्तावेजों, न्यायालयों के नियमों का अध्ययन, अभिवचन के प्रारूपण का अध्याम, वकील के चैम्बर, में कार्य और व्यवसायिक सदाचार विषयक व्याख्यानों में उपस्थित भी है। छात्र से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा संचालित इस पाठ्यकम की परीक्षा में उत्तीर्ण हो।
- 3. कम से कम छह और विषयों का अध्ययन जो नीचे दी गई सूची में से और स्थानीय रूप से सुसंगत ऐसे अन्य विधि-विषयों मे मे चुने जा सकते हैं जो विण्वविद्यालयों द्वारा अपने अपने विकल्पानुसार बिहित किए जाएं —
 - 1. साम्या
 - 2. कम्पनी विधि
 - 3. श्रम विधि
 - 4. कराधान

- अन्तर्राष्ट्रीय मंगठन
- 6. विवाला
- 7 सहकारिता-विधि और कारबार का लोक नियन्नण
- विधायी प्राप्त्पण
- 9 सैनिक विधि
- 10. बीमा
- 11 न्यास और अन्य वैश्वासिक बाध्यताये
- 12 व्यापार चिह्न, प्रतिलिप्यधिकार और पेडेंट
- 13. अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक विधि
- 14. अपराध-विज्ञान और अपराध प्रशासन
- 15. कानूनों का निर्वाचन और निधायन के सिद्धात
- 16 विधिक उपचार
- 17. प्राइवेट अन्तर्राष्ट्रीय विधि
- 18. तुलनात्मक विधि
- 19. विधि और मामाजिक परिवर्तन
- 20. विधि और निर्धनता
- भू-राजस्व, भूमिसुधार और ग्रामीण विकास में संबंधित विधि
- 22. विधि और योजना
- 23. स्थानीय स्वशासन से मंबंधित विधि
- 12. प्रत्येक प्रश्नपत्न के लिये प्रति सप्ताह कम से कम तीन घंटे के व्याख्यान की कक्षाएं और एक घंटे का ट्यूटो-रियल कार्य होगा ।
- 13. साधारणतया प्रस्थेक वर्ष के अन्त में परीक्षा ली जाएगी किन्तु विश्वविद्यालय को इस बात की छूट होगी कि वह प्रत्येक छह मास के अन्त में परीक्षाएं कराए । विश्व-विद्यानय, यथास्थिति, एक वर्ष या छह मास की अवधि के लिए विषयों का समुचित आवंटन करेगा और भारतीय विधिज्ञ परिषद् को इसकी सूचना देगा ।
- 14. प्रत्येक विश्वविद्यालय निर्णयज पद्धति, ट्यूटोरियल भौर विधि-णिक्षा देने की श्राधुनिक तकनीकों द्वारा व्याख्यान पद्धति की श्रनुपूर्ति करने का प्रयास करेगा ।
- 15. विधि के पूर्णकालिक णिक्षक, जिसके श्रन्तर्गत महा-विद्यालय का प्रधानाचार्य भी है, विधि के मास्टर की उपाधि धारण करने वाले होगे और जहा विधि के मास्टर की उपाधिधारण करने वाले व्यक्ति उपाल्य नहीं है वहां ऐमे व्यक्तियों को रखने के बारे में विचार किया जायेगा जिन्हें कम थे कम पाच वर्ष का विधि-णिक्षण का श्रनुभव प्राप्त है। ऐसे श्रण-कालिक णिक्षक, जिन्हें एल०एग० बीठ की उपाधि प्राप्त नहीं है, बार का कम भे कम पांच वर्ष का श्रनुभव रखने काले व्यक्ति होंगे।
- 16. विश्वविद्यालय केवल ऐसे महातिद्यालयों को स्थापित करेगा या उन्हें मान्यता प्रधान करेगा जहां पर दिन मे पूरे

- समय तक्त विधि की कक्षाये लगती है और इन नियमो द्वारा पथा अपक्षित मुविधाये तथा पुरतकालय है।
- 17. पूर्ण कार्तिक श्राण श्रमवािक शिक्षका पर शिक्षण-भार निर्णाबद्यालय धनधान पानाम हुरः सम्ब सभय पर विह्नि मानदण्डो के अनुभार होगाः।
- 13 प्रधानाचार्य पूर्ण कालिक श्रौर श्रंगकाणिक अक्षका को दिया गया बेनन विश्वविद्यानय श्रनुदान श्रायोग द्वारा समय समय पर सिफारिश किए गए बेननगान के श्रनुसार होगा ।

प्रत्य प्रसुविधायें जैसे मंहगाई भत्ता, प्रतिकरात्मक स्थानीय भत्ता, जूह किराया भत्ता, भविष्यनिधि ग्रादि लम्बद्ध विषय-विद्यालयों द्वारा समय समय पर विहित सानदण्डों के ध्रनुसार होगा ।

19. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध विधि-महाविद्यालय, 1 जून, 1982 से स्वतंत्र महाविद्यालय होगा, महाविद्यालय से संलग्न विभाग नहीं रहेगा ।

स्वतंत्र विधि महाविद्यालय से ऐसा पूरे समय का दिन का महाविद्यालय श्रमिप्रेप्त है जिसमें ग्रहेंताप्राप्त नियमिस रूप से पूर्णकालिक प्रधानाचार्य श्रौर श्रपेक्षित कर्मवारिवृत्द हैं तथा जिसमे इन नियमों द्वारा यथाउपबन्धित सुविधायें उप-लब्ध हैं।

- 20. (1) इन नियमों के प्रवृत्त होने के पश्चात प्रारम्भ किया गया कोई महाविद्यालय ग्रिधिवक्ता के रूप में नामांकन के लिये विधि के पाठ्यक्रम की शिक्षा तभी देगा जब भारतीय विधिक्त परिषद् ने उसकी सम्बद्धता का अनुमोदन कर दिया हो।
- (2) यदि भारतीय विधिज्ञ परिषद् ने किसी विद्यमान विधि महाविद्यालय की सम्बद्धता को जारी रखने का ग्रानु-मोदन नही किया है नो वह विधि महाविद्यालय ग्रिधिवक्ता के रूप में नामांकन के लिये विधि-पाठ्यकम की शिक्षा देने के वास्ते सक्षम नहीं होगा ।
- 21. भारतीय विभिन्न परिषद किसी ऐसे विभिन्महा-विद्यालय का, जो किसी विष्वविद्यालय से सम्बद्ध या सम्बद्ध होना चाह्ता है, निरीक्षण ऐसी समिति द्वारा, जिसे बह हस प्रयोजन के लिये नियुक्त करें, तब कराएगी जबकि:---
 - (क) भारतीय थिधिज परिषद् को नए अहाविद्यालय की लम्बद्धता क अनुमोदन के लिए अविद्यन प्राप्त हुआ है, या भारतीय विधिज्ञ परिषद् ने यह सुनि-श्चित करने के लिखे कि उसने विद्या शिक्षा के जो मानक अधिक्षित किए हैं। उनका अनुपातन किया जा रहा है, स्वप्रेरणा से ऐसा अनुकोदन करने का विभिन्नव्य किया है।
 - (ख) नए महाविद्यालय की सम्बद्धता के प्रनुसोदन के लिए प्रविद्यन भारतीय विधिज्ञ परियद के सचिय को

तम्बोबित किया जायेगा श्रीर सम्पृक्त विश्वविद्यालय के कुलसचिव की मार्फत ही कुलसचिव की सिफा-रिश के साथ भेजा जायेगा ।

- (ग) सम्पृक्त महाविश्वालय श्रौर या विश्वविद्यालय, निरीक्षण समिति श्रौर भारतीय विधिज्ञ परिषद् को सभी जानकारी, जब श्रौर जैसे श्रपेक्षा की जाए, भेजेगा श्रौर निरीक्षण किए जाने में उनके साथ सहकार करेगा ।
- (घ) निरीक्षण-ामिति भारतीय विधिन्न परिषद् को एक विस्तृत रिपोर्ट इस स्पष्ट मिफारिण के साथ प्रस्तृत करेगी कि नए महाविद्यालय की सम्बद्धता का अनुमोदन किया जाए या नहीं या किसी विद्यमान महाविद्यालय की सम्बद्धता वापस ली जाए। जारी रखी जाए या विनिधिष्ट की जाने वाली अविधि के भीतर सुधार करने के लिये कुछ निदेश दिए जाएं।

रिपोर्ट में सिफारिशों के लिये कारण भी सम्मिलन किये जायेंगे।

- (ङ) यदि ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होती है जो ग्रानुकूल नहीं है तो भारतीय विधिक्त परिषद् का सचिव उसकी एक प्रति सम्पृक्त विश्वविद्यालय के कुल-सचिव को उसकी टिप्पणी ग्रीर स्पष्टीकरण के लिए, यदि कोई है, भेजेगा । विश्वविद्यालय का कुलसचिव रिपोर्ट के बारे में टिप्पणी ग्रीर स्पष्टी-करण, संसूचना प्राप्त करने की तारीख मे छह मप्ताह की ग्रवधि के भीतर भेजेगा ।
- (च) भारतीय विधिज्ञ परिषद् का सचिव रिपोर्ट ग्रौर सम्बद्ध विश्वविद्यालय के कुल संचिव की टिप्पणी स्पष्टीकरण को भारतीय विधिज्ञ परिषद् की विधि-शिक्षा समिति के ग्रागामी श्रिधिवेशन में रखेगा।
- (छ) यदि विधि णिक्षा मिनित का यह समाधान हो जाता है कि भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा इन नियमों मे उपबन्धिल विधि-णिक्षा के मानदण्डों का भ्रौर/या मम्बद्धता के लिये या मम्बद्धता जारी रखने के लिये नियमों का श्रनुपालन नहीं किया गया है श्रौर/या पाठ्यक्रम, णिक्षण और या परीक्षा ऐमी। नहीं है जिसे कि विधि-णिक्षा ग्रहण करने बाले व्यक्तियों को सक्षम विधि व्यवसाय के लिये भ्रपेक्षित ज्ञान भीर प्रणिक्षण प्राप्त होता है तो विधिक णिक्षा समिति भारतीय विधिज्ञ परिषद से, यथास्थिति, सम्बद्धता के श्रनु-मोधन/अननुयोदन या सम्बद्धता जारी रखने के लिये सिफारिश करेगी।

विधि शिक्षा समिति यह भी सिफारिश कर सकती है कि विनिधिष्ट की जाने वाली

- प्रविध के भीतर किए जाने बाले सुधारों के लिये कुछ निर्देग दिए जाएं।
- (ज) विधि शिक्षा समिति की यह सिफारिश सबंधित कागज-पक्षों के साथ भारतीय विधिन्न परिषद् के समक्ष उसके विनिश्चय के लिये रखी जाएगी।

यदि भारतीय विधिक्त परिषद् विधि-शिक्षा मिनित की सिफारिण में असहमत है या उसमें उपान्तरण करती है तो वह अपने विचार विधिक शिक्षा समिति को इस विषय में अन्तिम विनिष्ण्य करने ने पूर्व उसके विचारार्थ संसूपित करेगी।

- (झ) यदि परिषद् की यह राय है कि किसी महा-विद्यालय की सम्बद्धता का अनुमोदन नहीं किया जाए तो वह महाविद्यालय के प्राधानाचार्य ग्रौर विश्वविद्यालय के कुलमचिव को यह सूचना देगी कि वे सूचना की प्राप्ति के तीम दिन के भीतर कारण बताएं ग्रौर परिषद् भ्रन्तिम ग्रादेश करने से पूर्व प्राप्त उत्तर पर विचार करेगी।
- (ज) भारतीय विधिज परिषद् का विनिश्चय विश्व-विद्यालय के कुलक्षचिव को संसूचित किया जायेगा।

विश्वविद्यालय के कुलसचिव को जिस तारीख को यह विनिष्ट्य प्राप्त होता है उस तारीख के बाद वाले मैक्षणिक वर्ष के प्रारम्भ से वह प्रभावी होगा ।

22. (1) परिषद् ऐसं विण्वविद्यालयों के नाम, जिनकी विधि उपाधियों को इन नियमों के श्रधीन मान्यता प्रदान की जाती है और उक्त विण्वविद्यालयों के श्रधीन विधि-महाविद्यालयों की सूची को, जो इन नियमों में यथा उपबन्धित व्यवसायिक विधिक णिक्षा प्रदान करने के पाल है, श्रधिसूचना द्वारा भारत के राजपत्न तथा भारत के प्रमुख समाचार पत्नों में प्रकाणित करेगी और उपर निर्धिष्ट श्रधिसूचना की एक प्रति विधि-णिक्षा प्रदान करने वाले सभी विश्वविद्यालयों नथा राज्य विधिज्ञ परिपदों को भेजेगी

परन्तु उपर्युक्त उप नियम (1) के प्रयोजन के लिये विद्यमान विश्वविद्यालय के विधि विभागों और विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध विधि महाविद्यालयों के बारे में यह समझा जायेगा कि वे इन नियमों के अधीन व्यावसायिक विधि महाविद्यालय हैं, जब तब पिरपद् इससे भिन्न विनिष्चय न करे।

(2) किसी विष्वविद्यालय की विधि-उपाधि को मान्यता प्रदान न करने या मान्यता वापम लेने की सूचना भारत में ऐसे सभी विष्वविद्यालयों को जो विधि-शिक्षा प्रदान करते हैं. और सभी राज्य विधिज्ञ परिषदों को भी भेजी जाएगी।

- 23.(1) ऐसे विश्वविद्यालय और महाविद्यालय, जो भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा नए नियमों के अधीन व्यवसायिक संस्थानों के रूप में अनुमोदित हैं, शैक्षणिक वर्ष 1982-83 से व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करना प्रारम्भ करेंगे। किन्तु परिषद् ऐसे विश्वविद्यालयों, को, जो अपनी स्कीम बदलकर नई स्कीम अपनाना चाहते हैं, अधिक से अधिक दो शैक्षणिक वर्षों की अवधि के लिये विद्यमान तीन वर्ष का एल०एल० बी० पाठ्यक्रम चलाने की अनुमति दे सकती है। यदि ऐसी अनुमित दी जाती है तो वे विद्यमान एल० एल० बी० पाठ्यक्रम में स्नातकों का प्रवेश शैक्षणिक वर्षे 1983-84 तक उक्त शैक्षणिक वर्ष सहित, जारी रख सकते हैं।
 - (2) ऐसे विश्वविद्यालयों को, जो पुरानी स्कीम बदल कर नई स्कीम अपनाने के लिये समय की मांग करना चाहते हैं, यह घोषणा अवश्य करनी होगी कि उनका आश्रय गैक्षणिक वर्ष 1984-85 तक इन नियमों के अधीन विधि-शिक्षा प्रदान करना है और वे इस प्रयोजन के लिये उठाए गए कदमों के बारे में रिपोर्ट भारतीय विधिज्ञ परिषद् को 1 जून, 1982 से एक वर्ष के अन्दर भेजेंगे।
- 24. (1) ऐसे छात्न, जो 1982-83 में या इससे पहले स्नातक पाठ्यक्रम (बी॰ए०, बी॰एम॰सी॰, बी॰काम॰ आदि) के प्रथम वर्ष में भर्ती हुये हैं, पुराने नियमों के अधीन विधि-शिक्षा ग्रहण करते रहने के पात होंगे । ऐसे छात्रों को पुराने नियमों के अधीन एल॰एल॰ बी॰ पाठ्यक्रम में गैक्षणिक वर्ष 1985-86 के पारम्भ तक प्रवेश करने दिया जा सकता है।
 - (2) ग्रैक्षणिक वर्ष 1985-86 के पश्चात् ऐसे संस्थानों में पुराने नियमों के अधीन एल०एल० बी० पाठ्यक्रम में प्रवेश को पूर्णतया बन्द कर दिया जाएगा;

परन्तु ऐसे विश्वविद्यालय भर्ती किए गए छाह्नों की शिक्षा पूरी करने के लिये एल०एल० बी० पाठ्यक्रम के प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष की परीक्षाओं का संचालन ऐसे समय तक कर सकने हैं जब तक ऐसा करना ठीक समझें।

- 25. (1) यदि ऐसे विष्वविद्यालय, जो उन राज्यो में अवस्थित हैं जहां 10 + 2 की विद्यालय पद्धति अभी प्रचलित नहीं हैं, नए नियमों के अधीन एल० एल०बी० पाठ्यक्रम प्रारम्भ करना चाहते हैं तो ऐसा करने के लिये स्वतंत्र होंगे।
 - (2) उक्त राज्यों में विश्वविद्यालयों को पुराने नियमों के अधीन विद्यमान एल०एल० बी० पाठ्यक्रम 1984-85 तक, उक्त शैक्षणिक वर्ष सहित, जारी रखने की भी अनुज्ञा दी जायेगी।
- टिप्पणी (नोट):--- उपर्युक्त नियम केवल व्यावसायिक विधि-शिक्षा के प्रति निर्दिष्ट हैं जिनके लिये

भारतीय विधिज्ञ परिषद का कानुनी उसरदायित्व अधिवक्ता अधिनियम के अधीन है। परिषद् यह आणा करती है कि देश में विश्वविद्यालय महाविद्यालय विधि की व्यापक शिक्षा प्रदान करना जारी रखेंगे और यदि आवण्यक हो तो विभिन्न व्यवसायों और सार्वजनिक सेवा में लगे हुए व्यक्तियों के फायदे के लिये पत्नाचार कार्यक्रम को विकसित करके जनसाधारण के बड़े बड़े वर्गों के लिये उसका विस्तार करेंगे जिससे कि वे लोग ग्रपने न्यासायिक लक्षीं की श्रभिवृद्धि कर सकें और साथ ही विधि सम्मत शासन तथा संवैधानिक सरकार को सहयोग दे सकें। इसका श्रर्थ यह होगा कि देश को विधि व्यापक शिक्षा प्रदान करने वाले ऐसे विद्यमान केन्द्रों से जिनमें प्रातः या संध्या समय सुविधाजनक समय पर कार्य होता है, देश की आवश्यकता पूरी नहीं होगी बल्क हमारे विशाल देश के सुदूर स्थानों में ऐसी ही और अनेक संस्थाओं की भी आवश्यकता होगी। इस समय जो नियम बनाये व्यावसायिक विधि शिक्षा के बारे में है और ऐसे अन्य महाविधालयों के बारे में नहीं है जो देश में विश्वविद्यालय पद्धति के ढांचे के अन्तर्गत विधि णिक्षा प्रदान करना जारी रखते हैं।

I. भाग IV में भारतीय विधिक्ष परिषद् नियम के नियम II (1) के अधीन 10+2 के पश्चात् 5 वर्षीय विधि शिक्षा की नई योजना के अन्तर्गत दो वर्षीय विधि पूर्व (प्री-ला) अध्ययन के लिए विहित विषयों के पाठ्यक्रम की रूपरेखा परिशिष्ट (क से छ) में दी गई है।

II. विश्विवद्यालय द्वारा अपनाए जाने के लिये भारतीय विधिक्ष परिषद् द्वारा तैयार की गई व्यावहारिक प्रशिक्षण योजना (नियम 11 (2) में कम सं० 12) में दी गई है।

III. विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिये विहित सभी विषयों के लिए सुझाई गई पठन सामग्री प्रायोगिक है, निःशेषकारी नही। प्रत्येक विश्वविद्यालय का अध्ययन मण्डल और विधि संकाय पाठ्यक्रम के लिये समुचित पठन सामग्री की वृद्धि और विकास करेंगे तथा उसे अद्यतन बनाये रखने के लिये उसमें परिवर्तन करेंगे और उसे स्थानीय आवश्यकताओं के लिए सुसंगत. बनाऐंगें।

IV. पुस्तक में दिए गए प्रकाशन वर्ष के बारे में यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि वह उस पुस्तक के नवीनतम संस्करण का ही वर्ष है। किन्तु विश्वविद्यालयों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सम्बद्ध पुस्तक का नवीनतम संस्करण ही विहित करें ।

V. यह ध्यान देने की बात है कि राजनीति शास्त्र का विषय, जो पहले नियम 11(2) में मूल रूप से एक प्रश्नपत्न के रूप में था, अब तीन प्रश्नपत्नों (राजनीतिशास्त्र I, II, और III में बढ़ा दिया गया है।

परिशिष्ट-क

1. साधारण भ्रंग्रेजी

विधि-पूर्व ग्रध्ययन में साधारण अंग्रेजी को ग्रनिवार्य पाठ्यक्रम के रूप में जिस उद्देश्य से सम्मिलित किया गया है वह विधि शिक्षा के मानकों से सम्बन्धित भाग IV के नियम 4 के श्राधार पर है। भारतीय विधिज्ञ परिषद् "श्रंग्रेजी में प्रवीणता" पर जोर देने के साथ साथ विधि-स्नातकों से यह श्राणा करती है कि उन्हें परीक्षण तथा अपीलीय न्यायालयों में कारगर रूप से विधि-श्यवसाय करने के लिए भाषा में न्यूनतमं निपुणता होनी श्रावण्यक है। विधि-श्यवसायी में जो श्रावण्यक निपुणता श्रपेक्षित है वह इस प्रकार है:—विचार संप्रेषण की निपुणता (लिखित श्रोर मौखिक दोनों रूपों में) तथा समझने की निपुणता (पढ़कर श्रौर सुनकर सीखना)।

निपुणता प्राप्त करने के लिए अनेक तरीके और अनेक प्रकार की सामग्री हो सकती है। यह आणा की जाती है कि प्रत्येक विश्वविद्यालय अपने साधनों और उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर सर्वोत्तम पद्धतियां विकसित करेगा और उन्हें अंग्रेजी भाषा के पाठ्य निवरण (अंग्रेजी I ग्रौर अंग्रेजी II) में सम्मिलित करेगा जिससे कि छात्र में उपर्युक्त निपुणता आ जाए। इस पाठ्यक्रम से इतनी आणा तो है ही कि उससे विधिक कामकाज में सम्प्रेषण और समझने के प्रयोजन के लिए भाषा का कामचलाऊ ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। यह तो स्पष्ट ही है कि इसके लिए साधारण अंग्रेजी और विधिक प्रयोजन के लिए अंग्रेजी दोनों के ज्ञान पर जोर देना आवश्यक होगा। किन्तु विधिक कामकाज समझने और उसे करने के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर ही मुख्य रूप से ध्यान देना है।

श्रंग्रेजी भाषा पाठ्यक्रम में दो प्रश्नपत्नों की संकल्पना है---श्रणीत् विधि-पूर्व श्रध्ययन के प्रत्येक वर्ष में एक प्रश्न-पत्न (श्रंग्रेजी I श्रौर श्रंग्रेजी II) विधि श्रौर भाषा के शिक्षकों के परामर्श से तैयार किए गए निम्नलिखित पाठ्य-विवरण का सुझाव विश्वविद्यालयों को दिया जा रहा है ताकि इससे उन्हें इस सम्बन्ध में श्रपना पाठ्यविवरण बनाने में सहायता मिल सके।

भ्रंग्रेजी I

- (क) व्याकरण स्रौर प्रयोग (सम्प्रेषण निपुणता)
 - 1. सरल वाक्य (एक खण्ड) (उनका वाक्यांश गठन)
- (i) काल श्रौर सन्धि

- (ii) संशोधक संज्ञा (श्रवधारक, सम्बन्ध सूचक वाक्य, खण्ड)
- (iii) मूल परिवर्तन
 - (क) कर्माषि प्रयोग
 - (ख) नकारात्मक
 - (ग) प्रश्न वाचक
- 2. जटिल श्रौर यौगिक वाक्य (सम्बन्धसूचक शब्दों का प्रयोग)
- सौपाधिक वाक्यांश (भ्रपेक्षा व्यंअक वाक्यांश)
- 4. प्रतिवेदित कथन·
- 5. प्रश्न-उद्धरण श्रौर संक्षिप्त उत्तर
- 6. कुछ सामान्य गलतियां
- (ख) शब्दावली (सम्प्रेषण निष्णुता)
 - विधिक शब्द (एलएल० बी० के छात्र के विषय-प्रश्न-पत्न से सुसंगत)
 - विधिक शब्दों श्रौर मुहावरेदार पदाविलयों का प्रयोग)
- (ग) समझने की निपुणता
 - 1. पठन की समझ (सिद्धान्त भौर भ्रभ्यास)
 - 2, सुनने की समझ
- (घ) रचना निपुणता
 - 1. पैरा लेखन
 - 2. भ्रौपचारिकः पत्नाचार
 - 3. नोट लेना
 - प्रादेशिक भाषा से अंग्रेजी में और अंग्रेजी से प्रादे-शिक भाषा में अनुवाद

भ्रंग्रेजी

- (क) शब्दावली
 - विदेशी शब्द श्रौर नाक्यांश (लैटिन भौर श्रंग्रेजी के महत्वपूर्ण-प्रत्यय)
 - 2. कुछ बहुप्रयुक्त पदार्वालयां भीर वाक्यांश
 - ग्रनेक गब्दों के स्थान पर एक शब्द
 - 4. वे शब्द जिनके बारे में प्रायः भ्रम उत्पन्न होता है।
- (ख) समझाने की निपुणता
 - 1. सामान्य तर्क दोष
 - 2. विधिक पाठ को समझना
- (ग) रचना निपुणता
 - ा. संसक्ति प्रयोग (विधिक प्रारूपण)
 - 2. संक्षिप्त सारलेखन, संक्षेपण श्रौर वाद संक्षेपण
 - वाद-संक्षेपण भ्रौर रिपोटौ का प्रारूपण
 - 4. विधिक विषयों पर निबंध लिखना
 - 5. विभिन्न प्रकार की वाक्य रचना भीर किया-पञ्चतियां

6. प्रतुत्राद (ग्रंग्रेजी से प्रादेशिक भाषाओं में ग्रीर प्रादेशिक भाषाओं से ग्रंग्रेजी में)

(घ) वाक् प्रशिक्षण

- 1. जोर से पड़ना (समुचित विराम का जात)
- 2. मुख्य ध्वनिया, इनके भेद श्रौर श्राधात
- 3. उच्चारण कोश देखना
- 4 तेज गति से पठन श्रीर वादविवाद के श्रभ्यास

सुझाई गई स्रोत-सामग्री

- 1. प्रसिद्ध निर्णयों से चुनी गई सामग्री।
- एम० के० गांधी → दि ला एण्ड दि लायर्स, नवजीवन प्रकाशन, श्रहमदाबाद, 1962 ।
- 4. विधिक सूचनाम्रों, श्रिजियों, भ्रिपीलों, न्यायालय-ग्रादेशों, कानुनों, विधेयकों, नियमों म्रादि से ली गई सामग्री।
- 5. छात्रों की समझ के स्तर के योग्य अंग्रेजी की रच-नात्मक शली और व्याकरण की कोई मानक पाठ्य-पुस्तक।
- 6. विधि णब्दात्रली, राजभाषा खण्ड, विधि मंत्रालस, नई दिल्ली।
- 7. डैनिंग---इय प्रोसेस श्राफ ला, लन्दन, बटरवर्थस ।
- एम० सी० छागला—-रोजेज इन डिसम्बर, भारतीय विद्या भवन, अम्बई।
- वर्क एडमान्ड—इंमपीचमैन्ट श्राफ वारेन हैसटिग्स, लन्दन, जी० वल ।
- 10. एम०मी० सीतलवाड---कामन ला इन इंडिया, हमलिन लेक्चर्स, स्टेबेन्स एण्ड सन्स ।

परिशिष्ट 'ख'

2. राजनीति गास्त्र

राजनीति णाम्त के तीन पाठ्यक्रमों का उद्देश्य छात्रों को निम्नलिखित विषयों के बारे में श्राधारिक ज्ञान प्रदान करना है: राज्य के सिद्धान्त, सरकार के संगठन और स्वरूप, नैतिक तथा राजनीतिक दायित्व की धारणाएं, राजनीतिक विचारधाराएं, जिसके अन्तर्गत भारतीय राजनीतिक विचार, न्याय-सिद्धान्त तथा अन्तरराष्ट्रीय संगठन और सम्बन्ध भी है। इन पाठ्यक्रमों का लक्ष्य है विधि शास्त्र, श्रपराध और दंड शास्त्र, लोक-विधि (संवैधानिक और प्रशामनिक विधि) तथा अन्तरराष्ट्रीय विधि और संगठन से सुसंगत दृष्टिकोणों और धारणाओं की विस्तृत जानकारी देना। इन पाठ्यक्रमों के नाम इस प्रकार है—राजनीति शास्त्र I, राजनीति शास्त्र II और राजनीति शास्त्र विधि-पूर्व चरण के दो वर्षों में से प्रस्थेक वर्ष में कम से कम एक पाठ्यक्रम का

श्रध्ययन होना चाहिए । द्वितीय वर्ष में राजनीति शास्त्र II श्रौर III का श्रध्ययन करना उत्तम होगा ।

राजनीति शास्त्र I

(क) राजनीतिक सिद्धान्त

- 1. राज्य तथा सरकार के बारे में विचारधाराएं
- 2. पिण्चमी राजनीतिक विचार की मुख्य धाराए, मध्य-युगीन राजनीतिक विचार (नैसर्गिक विधि ग्रौर नैसर्गिक ग्रिधकार)

उदारताबाद, समाजबाद भ्रीर मार्क्सबाद।

- 3. भारतीय राजनीतिक विचार की मुख्य धाराएं— राज्य के बारे में कलासिकी हिन्दू श्रीर मुसलमानी विचारधाराएं, उन्नीसवीं शताब्दी में राजनीतिक विचारधाराएं (उदारताबाद का विकास), गांधी-वाद, सर्वोदय, भारत में मार्क्सवादी विचार।
- 4. राजनीतिक श्रीर विधिक प्रभुत्ता
- सर्वाधिकारवादी राज्य

(ख) राजनीतिक संगठन

- सरकार का संगठन: एकात्मक परिसंघीय/प्रार्द्ध-संघीय: (एकदलीय लोकतंत्र, सैनिक शासन, राष्ट्र-पति तथा मंत्रिमण्डल प्रणाली)।
- विधान मण्डल, कार्यपालिका ग्रौर न्यायपालिका, गिक्त के पृथक्करण के सिद्धान्त, संसदीय प्रभुता ग्रौर न्यायपालिका की स्वतंत्रता।
- प्रतिनिधित्व, जनमत श्रौर जनता द्वारा भाग लेने की विचारधाराएं।

राजनीति शास्त्र II

राजनीतिक दायित्व के भ्राधार

- शक्ति, प्राधिकार भौर विधिमान्यकरण की विधार-घाराएं।
- 2. किस तरह से गिन्त विधि सम्मत गिन्त हो जाती है, या क्यों जनसाधारण को राज्य के ग्रावेशों का पालन करना चाहिए, राजनीतिक वायित्व की धारणा के बारे में क्लासिकी दृष्टिकोण (हाब्स, लाक, रूसो) ग्रीर ग्राधुनिक दृष्टिकोण (मैक्स बेवर, मार्क्स, इसाइल, दुराखंम) की जांच।
- राजनीतिक दायित्व के दृष्टिकोण के रूप में उप-योगिताबाद (नियम श्रौर कार्य दोनों)।
- गांधीवादी भ्रौर नव-गांधीवादी विचारधारा के संदर्भ में सिविल श्रवज्ञा श्रौर राजनीतिक दायित्व की समस्या।
- 5. श्रन्यायी विधियों के पालन की समस्या।
- 6. हमें वचनों और संबिदाश्रों का पालन क्यों करना चाहिए? (वचनाश्राधारित श्रीर संविदाजात दा-यिख के श्राधार)।

- 7. वंड की समस्या: नागरिको के विरुद्ध राज्य द्वारा बल का प्रयोग कब न्यायसंगत थ्रौर न्यायोचित है ? (दांडिक श्रनुशास्ति के श्राघार)।
- 8. समसामधिक वैधता का संकट।

राजनीति शास्त्र 111

श्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध श्रौर संगठन

यह पाठ्यक्रम परिचयात्मक है। इसकी पद्धति वर्ण-नात्मक ग्रौर विश्लेषणात्मक है। यदि चाहे तो एल एल० बी० के पाठ्यक्रम के उच्चतर चरण मे ग्रिधिक जटिल पद्धति पर ग्राधारित पाठ्यक्रम से शिक्षा दी जा सकती है।

यह पाठ्यक्रम दो प्रमुख भागो में बांटा गया है—भाग I श्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध और भाग II श्रन्तर्राष्ट्रीय संगठन।

भाग I—विश्व समुदाय, प्रभुतासम्पन्न राज्य, पार-राष्ट्रीय राजनीतिक दल और पार-राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन जैसे चर्च, बहुराष्ट्रीय निगम, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक और अन्य संगठन। राष्ट्रीय शक्ति के ग्रंग, जनसंख्या, भूगोल संसाधन, ग्रायिक संगठन, प्रौद्योगिकी और सैनिक बल। राष्ट्रीय शक्ति की परिसीमाएं, श्रन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता, जनमत, श्रन्तर्राष्ट्रीय विधि, हिसा और विनाश का भय, परम्परागत और श्राण-विक शस्त्रास्त्रों से युद्ध। संघर्ष के प्रमुख कारण: पूर्व और पश्चिम तथा उत्तर और दक्षिण की प्रतिद्वन्द्विता, राज्य क्षेत्रीय दावे संसाधन, जनसंख्या का प्रग्नजन, श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, संदाय में सन्तुलन श्रौर संरक्षणवाद।

युद्ध से बचाव श्रीर णान्तिपूर्ण परिवर्तन की सुविधाएं, मैती सम्बन्ध श्रीर गक्तिसन्तुलन का वृष्टिकोण, सामूहिक मुरक्षा श्रीर निरस्त्रीकरण, राजनय श्रीर वार्ता द्वारा संघर्षों का भान्तिपूर्ण समाधान, बीच बचाव करना, सुलह श्रीर श्रन्तर्राष्ट्रीय संगठनों का श्रवलम्ब, माध्यस्थम् श्रीर न्यायिक निपटारा, सांस्कृतिक सम्पर्क श्रीर यूनस्को, श्रन्तरराष्ट्रीय सहकार को बढ़ावा देना श्रीर क्रियात्मक वृष्टिकोण, विशिष्ट श्रमिकरण (एजेसियां)। विश्व सरकार के पक्ष श्रीर विपक्ष का विषय।

भाग II—अन्तरसरकारी संगठन श्रौर उनके संघटक विलेख, संगठन के मानक रूप, वार्षिक या नियतकालीन महा-सम्मेलन, महासम्मेलनों के बीच की श्रविध के दौरान समिति या परिषद् द्वारा विनिश्चय करना, सिचवालय श्रन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन श्रौर अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाश्रो के विषेष लक्षण, संयुक्त राष्ट्र संघ श्रौर उसके मुख्य श्रंग, संयुक्त राष्ट्र संघ श्रौर असके मुख्य श्रंग, संयुक्त राष्ट्र संघ श्रौर अन्तर्राष्ट्रीय गिर-सरकारी संगठन।

सुझाई गई स्रोत सामग्री

1. लैसली लिपसन—ग्रेट इसूज भाफ पालिटिक्स। एन इन्द्रोडक्शन टू पालिटिकल साइंस, न्यू यार्क, प्रेनटिस हाल, 1954।

- जी० एन० सिंह—फन्डामेन्टल्श श्राफ पोलिटिकल साइन्स एण्ड आर्गनाइजेशन, इलाहाबाद, किताब महल, 1966।
- के० भ्रार० बाम्बावाला—इंडियन पालिटिक्स एण्ड गवर्नमेन्ट सिन्स 1885, दिल्ली, भ्रात्मा राम एण्ड सन्स 1951।
- 4. हैन्स मारगैनथाऊ—पालिटिक्स एमंग नेशन्स, दि सद्रगल फार पावर एण्ड पीम, द्वितीय संस्करण, न्यू यार्क कनाप्ट, 1955।
- क्वन्सी राइट—स्टडी श्राफ इन्टरनेणनल रिलेणन्स, न्यू यार्क, एप्पलटन, सेन्चुरी क्राफ्ट्स, 1955।
- डी० डब्ल्यू० बोवेट, इन्टरनेशनल इन्स्टीच्यूशन्स, लन्दन, मैथ्यून, 1964।
- 7. परिसिस कोहेन—मार्डर्न सोशल थ्यूरी (धार्नल्ड हैनमैन 1976)।
- 8. डेनिस लायड--दि ग्राडिया ग्राफ ला (पेलिकन, 1964)।
- 9. डी॰ डी॰ रेफैल-प्राबलमस श्राफ पोलिटिकल फिलासफी मैकमीलन, 19-)।
- 10. रासको पाउन्ड—ऐन इन्ट्रोडक्शन टू दि फिलासफी श्राफ ला (येल यूनिवर्सिटी प्रेस, 1954)।
- 11. उपेन्द्र वख्णी—दि फ्राइसिस ग्राफ दि इंडियन विकास, 1982)।
- 12. हैच० एल० ए० हार्ट—एसे ग्रान पनिशमेन्ट एण्ड रेसपान्सबिल्टी (ग्राक्सफोर्ड, 1958)।
- 13. एस० ई० फाइनर—कम्परेटिव गवर्नमेन्ट (पेलिकन, 1970)।
- 14. रजनी कोठारी—डिमोक्रेटिक पालिटी एण्ड सोमल चैन्ज इन इंडिया, काइसिस एण्ड श्रापर्ज्निटीज (एलाइज पब्लिकेमन्स, 1976)।
- 15. आर्ज लिच थीम—ए गार्ट हिस्ट्री श्राफ सोशलिज्म (फानटनाल कालिन्स, 1970)।
- 16. यू० एन० घोषाल—ए हिस्ट्री आफ इंडियन पो-लिटिकल आइडिआज आक्सफोर्ड 59)।
- 17. के॰ पी॰ करुणाकरण---माडर्न इंडियन पोलिटिकल ट्रैंडियन्स (एलाइड, 1962)।
- 18. जी० एच० सैबाहन--ए हिस्ट्री श्राफ पोलिटिकल थ्यूरो (चतुर्थ संस्करण, श्राक्सफोर्ड 1973)।
- 19. जी० सावर- मार्डर्न फेडरिज्म, लन्दन, सी० ए० वाट्स, 1969)।
- 20. एस॰ पी॰ वर्मा—मार्डन पोलिटिकल थ्यूरी, विकास, 1980।

परिशिष्ट-ग

3. ग्रर्थशास्त्र

विधि-पूर्ण पाठ्यक्रम के लिए श्रर्थशास्त्र पाठ्य विषय के दो भाग हो सकते हैं—भाग-क—श्रर्थशास्त्र : साधारण सिद्धान्त । भाग-ख—भारतीय श्रर्थशास्त्र ।

इसका उद्देश्य छाल्लों को न केवल विद्या की एक शाखा के रूप में अर्थशास्त्र की जानकारी देना है श्रपितृ आर्थिक सिद्धान्तों को विधि की प्रक्रियाओं से सम्बद्ध करना, उनके पारस्परिकं सम्बन्धों से इस प्रकार धर्शाना है जिससे कि संविदा, कम्पनी विधि, कराधान, औद्योगिक विधि श्रादि विषयों को अच्छी तरह से समझने में सहायता मिल सके। इसके श्रतिरिक्त न्यायशास्त्र, संवैधानिक विकास श्रीर योजनाबद्ध विकास को समुचित रूप से समझने के लिए श्रर्थशास्त्र का ज्ञान श्रावश्यक है।

भाग-क---साधारण सिद्धान्त

- (क) विज्ञान के रूप मे प्रर्थशास्त्र थ्रौर विधि से उसकी सुसंगति।
- (ख) सामाजिक कल्याण श्रीर सामाजिक न्याय के ग्राधार के रूप में ग्रर्थशास्त्र
- (ग) निर्वाध उद्यम, योजनाबद्ध प्रथं व्यवस्था, ग्रौर मिश्रित ग्रथं व्यवस्था।

श्रर्थशास्त्र के साधारण सिद्धान्त

- (i) मांग श्रौर पूर्ति
- (ii) बाजार, कीमतों का ग्रवधारण, व्यावसायिक संगठन
- (iii) श्रम भौर मजदूरी
- (iv) पुंजी स्रौर धन
- (v) बचन, खापत, विनिधान
- (घ) विकास की ब्यूह रचना ग्रौर ग्रनुभवों की भ्रन्त-र्राष्ट्रीय तुलना—अर्थायक प्रगति के सिद्धान्त ग्रौर विकास की समस्याएं।
- (ङ) एकाधिकार का नियंत्रण श्रौर श्रार्थिक केन्द्रीय-करण का निवारण।
- (च) बैंकिंग भ्रौर वित्तीय नीति
 - (i) संसाधनों का जुटाव तथा वित्तीय संसाधन— कराधान
 - (ii) प्रत्यय की भूमिका श्रौर बैंकिंग पद्धित, ग्रामीण मुद्रा बाजार
 - (iii) भ्रन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं
 - (iv) प्रौद्योगिकी और श्रार्थिक प्रगति

भाग-ख---भारतीय ग्रर्थशास्त्र

Ι

- (क) जनसंख्या-वृद्धि की प्रवृत्तियां
- (ख) भारत में राष्ट्रीय ग्राय के प्राक्लन

- (ग) स्वतंत्रता के पश्चात् भारत की स्राधिक नीति
- निर्धनता श्रौर श्राय का विवरण
 - (क) ग्रामीण निर्धनता की ग्रन्तः क्षेत्रीय भिन्नता
 - (ख) बेरोजगारी की प्रवृत्तियां भ्रौर रोजगार विलाने की योजनाएं (स्कीमें)
 - (ग) श्रम, उत्पादकता ग्रीर मजदूरी
- III. भारत की विकास योजनानीति का तर्क
 - (क) योजना प्रक्रिया
 - (ख) कृषि और उद्योग के बीच प्राथमिकता
 - (ग) प्रौद्योगिकी का चयन
 - (घ) सरकारी, निजी श्रौर संयुक्त क्षेत्रों की भूमिका
 - (ङ) बृहत्, मध्यम और लघु उद्योग।
- IV. भाषिक केन्द्रीकरण के नियंत्रण की समस्या
 - (क) निजी-निगमित क्षेत्र (प्राइवेट कारपोरेट सेक्टर) का विनियमन (नियंत्रण, ध्रनु-ज्ञप्ति, कोटा)।
 - (ख) एकाधिकार विरोधी भौर भवरोधक पद्ध-तियां, विनियमन
 - (ग) घाटे की वित्त नीति
 - (घ) कीमत निर्धारण
 - (इ) श्रम सम्बन्ध
- V. विदेशी विनिधान
 - (क) भ्रन्तर्राष्ट्रीय विनिधान
 - (ख) भ्रन्तर्राष्ट्रीय सहायता
 - (क) अन्तर्राष्ट्रीय निगम
 - (घ) नई म्रार्थिक व्यवस्था की प्रवृत्तियां
- VI. निर्यात और श्रायात नीति: श्रायात प्रतिस्थापन श्रीर निर्यात प्रोन्नयन

VII. कृषि अर्थशास्त्र

- (क) इस श्रर्थशास्त्र के श्राधारिक लक्षण श्रौर स्वतंत्रता के बाद इसमें परिवर्तन।
- (ख) कृषिक सम्बन्धों का ऋमिक विकास। सम-न्यित ग्राम विकास।
- (ग) कृषि का नाणिज्यीकरण
- (घ) फार्म प्रबन्ध का श्रर्थशास्त्र
- (इट) कृषि आरधार।
- VIII. पूंजी संग्रहण, उधार श्रौर वैंकिंग पद्धति सुझाई गई स्रोत सामग्री
 - ग्रलफेड डब्ल्यू० स्टोनियर एण्ड डगलस सी० हेग---दि एसेन्शियल्स ग्राफ एकनामिक्स, लन्दन, लागमैन्स, 1955।

- 2. रुद्रदत्त एण्ड सुन्दरम्—इंडियन एकानमी, दिल्ला, एस० चान्द एण्ड कम्पनी, 1982।
- 3. ए० एन० भ्रम्भवाल-इंडियन एकनामिक्स, नई दिल्ली, विकास 1979।
- 4. पाल सेमुग्रलसन—इकानामिक्स—एन इन्ट्रोडक्टरी एनालिसिस (इंटरनेशनल स्टुडेंट एडिशन, मेकग्रा हिल बुक कम्पनी, सेवंथ एडिशन, 1961।
- 5 फ्रेडरर्थ लेविस—ध्योरी श्राफ एकानामिक ग्रोथ (श्रनविन यूनिवर्सिटी बुक्स, 1954, नवां इन्प्रेशन, 1970)।
- वी० वाई० गुप्ता—विंकग ग्राथ स्टाक एक्सचेन्जेज इन इंडिया, दिल्ली (थामसन प्रेम, 1972)।
- 7. एस० घटक—रूरल मनी मार्कटम इन इंडिया, दिल्ली, मैकमीलन, 1976)।
- 8. सी० एच० हनुमन्त राव एण्ड पी० सी० जोशी— रिफलेक्शन्स श्राफ इकनामिक डेवलपमेट एण्ड सोशल चेन्ज—एसेज इन श्रानर श्राफ दी वी० के० श्रार० वी० राव (एलाइड, 1979)।
- 9. पी० के० चौधरी—दि इंडियन एकानिमी—पावर्टी एण्ड डेवलपमेंट (विकास, 1978)।
- 10. सी० टी० कुरियन—प्लानिंग, पावर्टी एण्ड सोशल ट्रान्सफारमेशन्स (एलाइड, 1976)।
- 11. एम० डिप्टान—व्हाई पूत्रर पीपुल स्टे पूत्रर— ग्रबंन वायस इन वर्ल्ड डेवलपमेंट (हेरिटेज पब्लि-गर्गा, नई दिल्ली, 1980)।
- 12. मार्डेल गुन्नार—दि चैंलेज ग्राफ वर्ल्ड पावर्टी (पेनगुइन, 1971)।
- 13. लक्ष्मी नारायण—प्रित्सपल्स एण्ड प्रैक्टिस ब्राफ पब्लिक इन्टरप्राहज मैनेजमेन्ट (ब्राक्सफोई, 1976)
- 14. महबूब उल हक-वि पावर्टी: सर्टेन चायसेज फार दि थर्ड वर्ल्ड (ग्राक्सफ़ोर्ड, 1976)।
- 15. एच० डब्ल्यू० सिंगर एण्ड जे० एस० अन्सारी-— रिच एण्ड पूअर कन्द्रीज (एलेन एण्ड उन्बीन तृतीय संस्करण, 1982)।
- 16. एल० एन० रंगाराजन—कमोडिटी कन्फिलक्ट— दि पोलिटिक्स एकानमी श्राफ इन्टरनैशनल कमो-डिटी निगोशिएशन्स (श्रूम, हेल्म लिमि० 1978)।
- 17. वी० गौरी शंकर—टेमिंग दि जायन्टस (मल्टी नेशनल कारपोरेशन्स इन इंडिया) (स्टर्लिंग, 1980)।
- 18. म्नाई लिविंगस्टोन (सम्पा०) इकानामिक पालिसी फार डेवलपमेंट (पेनगुइन, 1971)।
- 19. पी० सी० जोशी—लेन्ड रिफार्म इन इंडिया (एला-इड, 1976)।

परिणिष्ट-घ

4. इतिहास

नीचे बताए गए पाठ्यक्रम का उद्देश्य छात्र को भारतीय इतिहास की उन सामाजिक, राजनीतिक, विधिक धौर सांस्कृतिक श्रान्दोलनों की मुख्य धाराश्रो की मोटे तौर पर जानकारी देना है जिनका प्रभाव विधिक पद्धतियों श्रौर संस्थाश्रों पर पड़ा है। यह श्राशा की जाती है कि शिक्षक छात्र को घटनाश्रों का केवल कालक्रम बताने की बजाए उपर्युक्त क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति की विरासत की जानकारी देगा जिससे छात्र भारतीय लोकतंत्र की उन वर्तमान संस्थाश्रों की प्रासंगिकता का मूल्यांकन कर सकें जिनकी शिक्षा विधि-पाठ्यक्रमों में दी जानी है।

- (क) प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक विरासत—सामाजिक, राजनीतिक, विधिक ग्रौर धर्म तथा दर्शनशास्त्र के क्षेत्र में (शिक्षक से यह ग्राशा की जाती है कि वह प्राचीन भारत में ग्राम गणराज्यों, प्राचीन भारत में केन्द्रीय सरकार के संगठन, विकेन्द्रीकरण के प्रयोगात्मक ग्रनुभव, प्राचीन विधि-निर्माताग्रों ग्रौर प्राचीन भारत (इस्लामी काल के पूर्व) में विवादों के निपटारे की पद्धतियों के ग्रध्ययन पर विशेष जोर देगा।); विधि ग्रौर संस्कृति का संबंध।
- (ख) इस्लाम का भ्रागमन—प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक विरासत भ्रौर इस्लामी संस्कृति के बीच भ्रादान-प्रदान भ्रौर समिश्रित भारतीय संस्कृति का प्रादुर्भाव । राजस्व प्रशासन, जिला प्रशासन, न्यायलय पद्धति के क्षेत्र में मध्ययुग के शासकों द्वारा नए प्रयोग।
- (ग) भारतीयों का योरोपीय लोगों के साथ सम्पर्क: भारतीय इतिहास और भारत के राष्ट्रीय ग्रान्दोलन पर योरोपीय संस्कृति का प्रभाव, भारत के राष्ट्रीय ग्रान्दोलन भौर 1947 तक भारत में संवैधानिक विकास पर योरोप की उदारतायादी विचारधारा का प्रभाव। ग्राधुनिक भारत में सामाजिक सुधार ग्रान्दोलनों भौर विधिक संस्कृति पर उसके प्रभाव का श्रध्ययन।
- (घ) ब्रिटिश काल के दौरान भारत का भ्राधिक इतिहास।

मुझाई गई स्रोत सामग्री

- ए० ग्रार० देसाई—सोशल बैकग्राउन्ड ग्राफ इंडियन नेशनिलज्म, पापुलर प्रकाशन, बम्बई (1948)।
- श्चार० सी० मजुमदार—हिस्ट्री श्चाफ दि फीडमं मूवमेन्ट इन इंडिया, कलकत्ता मुखोपाध्याय।
- वी० पी० मैनन-—िद ट्रान्सफर श्राफ पावर इन इंडिया अम्बई, भ्रोरियन्ट लांगमैन्स।
- 4. बी० शिव राव—इंडियाज फीडम मूवमेन्ट्स, नई दिल्ली, श्रोरियन्ट लांगमन्स (1972)।
- वट्टाभि सीतारामय्या—हिस्ट्री भाफ दि इंडियन नेशनल कांग्रेस, बम्बई पद्मा पब्लिकेशन्स।

- 6. ताराचन्द—हिस्ट्री श्राफ दि फीडम मूबमेन्ट इन इंडिया।
- वी० पी० मेनन—िद स्टोरी श्राफ इन्टिग्रेशन श्राफ इंडियन स्टेट्स, कलकत्ता श्रोरियन्ट लांगमैन्स।

परिशिष्ट-ङ

5. समाजशास्त्र

इस पाठ्यक्रम में छात्रों को भारतीय ममाज श्रीर उसकी संस्थाओं के संदर्भ में समाजशास्त्र के साधारण सिद्धान्तों की जानकारी देने हुए यह प्रयास किया जाएगा कि छात्रों को विधि का योगदान सामाजिक इजीनियरी के रूप में प्रकट हो। समाज में विधि के मूल श्राधार के बारे में पता लगाया जाएगा श्रीर सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में विधि की सीमा श्रीर किमयों पर दृष्टान्तों तथा श्रनुभव श्राक्षित श्रध्ययन द्वारा प्रकाश डाला जाएगा।

विधि-पूर्व पाठ्यक्रम के लिए समाजशास्त्र के पाठ्यक्रम का विषय दो भागों में हो सकता है:

भाग क—समाजशास्त्रः साधारण सिद्धान्त। भाग ख—भारत का समाजशास्त्र। भाग कः समाजशास्त्रः साधारण सिद्धान्त

- 1. विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र:
 - (क) डाटा, विचारधाराएं भ्रौर सिद्धान्त
 - (ख) तुलनात्मक प्रणाली
- 2. समाजशास्त्र की मूल धारणा
 - (क) संरचना ग्रौर कृत्य
 - (ख) हैसियत श्रौर भूमिका
 - (ग) म्रादर्श भ्रौर मूल्य
 - (घ) संस्थाएं।
- 3. सामाजिक संस्थाएं
 - (क) विवाह, कुटुम्ब श्रौर रक्त सम्बन्ध
 - (ख) काम श्रौर श्रार्थिक संस्थाएं
 - (ग) शक्ति ग्रौर राजनीतिक संस्थाएं
 - (घ) धार्मिक संस्थाएं
 - (इ) शिक्षा संस्थाएं
- सामाजिक स्तर विन्यास
- सामाजिक नियंत्रण, व्यवस्था, भौर स्थायित्व
- प्रपीड़न, संघर्ष और परिवर्तन
- 7. समाज के गुणदोष विवेचन के रूप में समाजशास्त्र
- विधि श्रीर समाज, विधि का समाजशास्त्र, विधिक व्यवसाय का समाजशास्त्र।

भाग ख: भारत का समाजशास्त्र

- 1. भारतीय समाज का विकास
 - (क) एकता स्रौर म्रनेकता
 - (ख) निरन्तरता भ्रौर परिवर्तन

- 2. बहुल समाज के रूप में भारत--उनके विभिन्न रूप
 - (क) रूढ़ियां भौर जीवन-पद्धतियां
 - (ख) भाषायी, धार्मिक और ग्रन्य समुदाय
- 3. भारतीय समाज की प्रमुख संस्थाएं
 - (क) कुटुम्ब
 - (ख) जाति
 - (ग) ग्राम
- 4 पारम्परिक व्यवस्था में जनजाति ग्रौर जाति
- समकालीन भारत में जाति स्रौर वर्ग
- 6. पिछडे वर्ग
- भारतीय समाज में परिवर्तन की प्रवृक्तियां
- भारतीय संस्कृति के मृत्य ग्रीर विकास

सुझाई गई स्रोत सामग्री

- टी० बी० बाटामोर—सोशियालजी, ए गाइड टू प्राक्लम्स एण्ड लिटरेचर, लन्दन, एलेन एण्ड उनवीन, 1962।
- पीटर वोरसले एट एल०—इन्ट्रोड्यूशिंग सोशियालजी, हार्मण्डसवर्ष: पैनभ्यूइन बुक्स, 1970।
- एम० हरालामबोस—सोशियालजी, थीम्स एण्ड पर्से-पेक्टिय, दिल्ली, ध्रान्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1981।
- एन० के० बोस-दि स्ट्रक्चर श्राफ हिन्दू सोसाइटी, नई दिल्ली, श्रोरियन्ट लांगमैन, 1975।
- डैविड जी० मैडेलमाम—सोसाइटी इन इंडिया, बम्बई, पापुलर प्रकाशन, 1972।
- 6. रमेश थापड़ (सम्पा०)—द्राइब, कास्ट एण्ड रेलिजन इन इंडिया, नई दिल्ली, मैकमिलन, 1977।
- 7. म्रान्द्रे बेतील—इनइक्वलिटी एण्ड सोशल चेंज, दिल्ली, श्राक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1972।
- 8. म्रान्द्रे बेतील—दि बैकवर्ड क्लासेज एण्ड दिन्यू सोणल मार्डर, दिस्सी, म्राक्सफोर्ड यृनिवर्सिटी प्रेस, 1981

परिभिष्ट-च

6. विधि भाषा ि सके अन्तर्गत विधि से दन भी है

यह कहा जाता है कि विधि की अपनी भाषा होती है यद्यपि वह सम्प्रेषण के लिए ऐसी भाषा को माध्यम बनाती है जिसे लोग समझते हैं। अभी तक जो माध्यम अपनाया गया है वह अंग्रेजी है और बहुत हद तक विधायन तथा न्याय प्रशासन अंग्रेजी के जरिए ही हो रहा है। फिर भी कुछ राज्यों में स्थानीय भाषा विधायन तथा निचले न्यायालयों में न्याय-प्रशासन के क्षेत्र में अंग्रेजी का स्थान धीरे-धीरे किन्तु निरंतर गति से ग्रहण कर रही है। ऐसा होना भी चाहिए।

न्नतः वर्तमान स्थिति में विधि व्यवसायी से यह ग्रपेक्षा की जाती है कि वह विधिक कामकाज में श्रंग्रेजी ग्रीर स्था-नीय भाषा का प्रयोग करने में सक्षम हो । भ्रपीलीय न्यायालयों में श्रंग्रेजी में प्रवीणता तो बहुत श्रावश्यक है श्रौर संभवतः यह स्थिति काफी दिनों तक बनी रहेगी।

शिक्षा के माध्यम के बारे में भारतीय विधिज्ञ परिषद् की जो नीति है उसमें उक्त स्थित परिलक्षित होती है। इसके परिणामस्वरूप 10 \div 2\pm 5 के ग्रधीन विधिक शिक्षा की नई स्कीम में भी ऐसी पाठ्यचर्या ग्रपनायी गयी है जो प्रत्येक भावी विधि व्यवसायी को कारगर रूप मे विधि व्य-वसाय करने के लिए श्रंग्रेजी और प्रावेशिक भाषा में प्रवीणता प्रदान करती है। इसी उद्देश्य से परिषद् ने श्रंग्रेजी से स्वतंश्व रूप में विधिक भाषा का ग्रलग पाठ्यक्रम, जिसके भ्रन्तगैत विधिक लेखन भी है, प्रारम्भ किया है। यह ग्राशा की जाती है कि इस पाठ्यक्रम में हिन्दी या ग्रन्य प्रादेशिक भाषा में, जो विधि शिक्षा के लिए माध्यम के रूप में ग्रपनायी जाए, प्रवीणता प्रदान की जाएगी जिससे कि जब कोई व्यक्ति श्रधिवक्ता के रूप में नामांकित किया जाए तब वह भ्रपने व्यवसायिक कार्य के लिए उस माध्यम का प्रयोग करने में सक्षम हो।

यह तो सर्वमान्य है कि हिन्दी या किसी ग्रन्य प्रादेशिक भाषा का ज्ञान माल उस भाषा में विधिक कामकाज करने के लिए ग्रपर्याप्त है। ग्रतएव प्रादेशिक भाषा के माध्यम से विधिक कार्य करने के लिए प्रवीणता बढ़ाने की दृष्टि से प्रादेशिक भाषा की शिक्षा भी विधिक भाषा और विधिक लेखन के पाठ्यकम का ग्रंग होगी।

इस पाठ्यकम के लिए एकसमान पाठ्य विवरण तैयार करना न तो वांछनीय है और न सम्भव ही है। यदि कोई विश्वविद्यालय विधिक शिक्षा के लिए श्रंग्रेजी से भिन्न किसी मन्य भाषा का माध्यम भ्रपनाता है तो उसे ही ऊपर बताए गए उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए इस पाठ्यकम का पाठ्य-विवरण तैयार करना होगा।

इस बात की सिफारिश की जा रही है कि विधिक भाषा ग्रीर विधिक लेखन के बारे में यह पाठ्यक्रम प्रावेणिक भाषा या हिन्दी में पढ़ने की इजाजत दी जाए।

परिणिष्ट-छ

7. भारत में न्यायालयों, विधान मण्डलों श्रौर विधि व्यवसाय का इतिहास।

1. न्यायालय

- पैसिडेन्सी नगरों में न्याय-प्रशासन (1600--1773) ग्रीर ईस्ट इंडिया कम्पनी के ग्रधीन न्यायालयों तथा न्यायिक संस्थाग्रों का विकास।
- 1772 की बारेन हेस्टिंग्स योजना श्रौर न्यायालयो की श्रदालत पद्धति—-1774 की योजना के श्रधीन सुधार श्रौर 1780 का पुनर्गठन।
- 1773 का रेगुलेटिंग ऐक्ट—कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट—उसका गठन, शक्ति भ्रौर कृत्य उसकी 3—459 GI/82

- ग्रसफलता—1781 का श्रिधिनियम—सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले में मुफसिल न्यायालय।
- 4. 1787, 1790, 1793 में कार्नवालिस के न्यायिक ग्रध्युपाय, सर ज्ञान शोर के ग्रधीन ग्रदालत पद्धति की प्रगति।
- 5. दुहरी न्यायिक पद्धति से उत्पन्न संघर्ष—न्यायासयों की दोनों प्रणालियों के समामेलन की प्रवृत्ति— इंडियन हाई कोर्टेस ऐक्ट 1911—गवर्नमेन्ट ग्राफ इंडिया ऐक्ट 1915—गवर्नमेन्ट ग्राफ इंडिया ऐक्ट 1935 के ग्रधीन उच्च र्यायालय ।
- 6. विधि सम्मत शासन का विकास, शक्तियों का पृथक्करण, न्यायालयों की [स्वतंत्रता।
- 7. श्रपील न्यायालय के रूप में प्रिवी कोंसिल की न्यायिक समिति श्रीर भारतीय निर्णयों की [श्रपील सुनने की उसकी श्रिधकारिता—भारतीय |निर्णयों की श्रपील सुनने की प्रिवी कौंसिल की श्रिधिकारिता की [स्रिधिकारिता की [समिति ।
- 8. भारत के संविधान के श्रधीन न्यायालय पद्धति।

2. विधान मण्डल

- 1. महारानी एलिजबेथ के 1601 के चार्टर के स्रधीन ईस्ट इंडिया कम्पनी का विधायी प्राधिकार।
- 2. रेगुलेटिंग ऐक्ट, 1773 के प्रधीन पिरवर्तन—178 का ऐक्ट बिटिश पार्लियामेंट द्वारा विनियम बनाने के लिए गवर्नर श्रीर कींसिल की शिक्सियों की मान्यता।
- 3. 1813 का ऐक्ट और सभी तीन कौन्सिलों को प्रदक्त विधायी शिक्त का विस्तार तथा इस शिक्त पर नियंद्रण बढ़ाना।
- 4. 1833 का ऐक्ट--1834 में मिखल भारतीय स्वरूप के विधान मण्डल की स्थापना।
- 5. इंडियन कौन्सिल्स ऐक्ट, 1861— सेन्ट्रल लेजिस-लेटिव कौंसिल श्रीर इसका गठन, शक्तियां तथा कृत्य, गवर्नर को प्रदत्त शिक्ति।
- 6. गवर्नमेन्ट श्राफ इंडिया ऐक्ट, 1909—गवर्नमेंट श्राफ इंडिया ऐक्ट, 1919—केवल एक सदन की इम्पीरियल कौसिल के स्थान पर केन्द्र में दो सदन अलि विद्यान मण्डल की स्थापना।
- 7. गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट, 1935—परिसंघ विधान सभा और राज्य सभा—इसका गठन, शक्तियां तथा कृत्य—प्रान्तों में विधान सभाएं श्रीर उनकी शक्तियां तथा कृत्य।
- प्रान्तों में विधान परिषदें, उनकी शक्तियां भौर कृत्य।
- 9. विधि में सुधार भ्रौर विधि भायोग।

3. विधि व्यवसाय

- क्रिटिश-पूर्व भारत में विधि व्यवसाय—भृमिका,
 प्रणिक्षण श्रौर कृत्य।
- 1726 के चार्टर के घ्रधीन स्थापित मेयर के न्यायालयों में विधि-व्यवसायी।
- 1774 के चार्टर के ग्राधीन विधि व्यवसाय का गठन।
- 4. कम्पनी के न्यायालयों में विधि व्यवसाय।
- 5. विधि व्यवसायी अधिनियम, 1853 के अधीन अधिवक्ता, वकील और घटर्नी के नामांकन का उपबन्ध।
- 6. 1861 के ऐक्ट के म्रधीन उच्च न्यायालय भ्रीर लेटर्स पेटेन्ट के म्रधीन भ्रधिवक्ताभ्रों के नामांकन के लिए उपबन्ध।
- 7. विधि व्यवसायी श्रिधिनियम, 1879—भारतीय विधिक्त समिति, 1923 की रिपोर्ट।
- 8. भारतीय विधिज्ञ परिषद् श्रिधिनियम, 1926--श्रिखिल भारतीय विधिज्ञ समिति, 1951।
- 9. ग्रधिवक्ता ग्रधिनियम, 1961।
- 10. विधि शिक्षा का विकास।
- 11. भारत में निर्णयों के प्रकाशन का इतिहास।

सुभाई गई स्रोत सामग्री

- 1. हर्बेट कावेल-दि हिस्ट्री एण्ड कन्स्टीच्यूशन श्राफ दि कोर्टस एण्ड लेजिसलेटिव श्रयारिटीज इन इंडिया— छठा संस्करण—पुनरीक्षक—एस० सी० बागची, 'कलकत्ता, यैकर, स्पिन्क, 1936।
- सर कूर्टने इलबर्ट--दि गवर्नमेन्ट ग्राफ इंडिया, [उतीय संस्करण, लन्दन, श्रोयूपी 1907।
- एम० पी० जैन—श्राउटलाइन श्राफ इंडियन लीगल हिस्ट्री, धनवन्तर भेडिकल एण्ड ला बुक हाउस, दिल्ली।
- 4. ए० बी० कीथ—ए कन्स्टीच्यूशनल हिस्ट्री प्राफ इंडिया, 1600—1935, द्वितीय संस्करण, इलाहा-बाव, सेन्ट्रल बुक डिपो, 1961।
- 5. ग्वायर भौर श्रप्पादोराई—स्पीचेज एण्ड डाकुमेन्ट्स श्रान दिइंडियन कन्स्टीच्यूशन 1935-1947 (दो खण्ड) लन्दन श्रा० यु० प्रे० 1957।
- 6. एम० वाई० पाइली—कन्स्टीच्यूशनल हिस्ट्री ग्राफ इंडिया 1967।

परिशिष्ट-ज

व्यावहारिक प्रशिक्षण

(श्रन्तिम वर्ष में स्थावहारिक प्रशिक्षण-पाठ्यकम के मन्तर्गत चार प्रघन्पत्र चार सौ ग्रंकों के होंगे) इस प्रशिक्षण के पाठ्यत्रमों का उद्देश्य विधि-कौणल भीर निपूणता विकस्ति करना होगा, श्रर्थात् :---

- (क) विधि प्रणाली
- (ख) विधि-श्रनुसन्धान
- (ग) श्रभिहस्तान्तरण
- (घ) ग्रभिवचन
- (इ) छाट-न्यायालय
- (च) व्यावसायिक सदाचार
- (छ) विधिक सहायता शाला
- (ज) न्यायालय प्रवलोकन

(क) विधि प्रणाली

छात्र को यह शिक्षा दी जानी चाहिए कि कहां ग्रौर कैसे विधि की खोज की जाए। उसे विशेष रूप से तथ्यों के विश्लेषण की तकनीक की श्रोर विधि के सुसंगत उपबंधों को खोजने के तरीके की श्रोर उसे व्यवहार में लागू करने की जानकारी दी जानी चाहिए। इस पाठ्यक्रम के श्रन्तर्गत मामलों का पठन, उनका विश्लेषण श्रौर विनिश्चय-श्राधार पता लगाना है। इस पाठ्यक्रम के श्रन्तर्गत कानूनों के निर्वेचन के नियमों को भी सुविधानुसार सम्मिलित किया जा सकता है।

(ख) विधिक अनुसन्धान

इस पाठ्यक्रम में छात्र को समस्याएं पता लगाने, परि-योजना प्रस्ताव बनाने, कार्य प्रणाली बनाने, डाटा का विष्केशन करने और छोटे-छोटे विषयों पर प्रनूसंधान िपोर्ट लिखने के लिए प्रावश्यक कौणल प्रदान करना चाहिए । इसमें विधि प्रणालियों से समाज विज्ञान श्रनुसन्धान पद्धतियों की तुलना की जा सकती है तथा छात्र को सामाजिक और प्राकृतिक विज्ञान के डाटा का समझदारी से प्रयोग करने के लिए सक्षम बनाया जा सिकता है।

(ग) अभिहस्तान्सरण

- (i) विऋय-बिलेख
- (ii) बन्धक विलेख
- (iii) पट्टा-विलेख
- (iv) दान-विलेख
- (v) प्रामिसरी नोट
- (vi) मुख्तार नामा
- (v^{ij}) विल (वसीयतनामा)

प्रारूपण के साधारण सिद्धान्तों और सुसंगत अधिष्ठायी नियमों की णिक्षा दी जाएगी और इस बात पर जोर दिया जाएगा कि किए गए कार्य का नियमित अभिलेख रखा जाए।

(घ) अभियचन

- {(i) सिविल
- (ii) बादपत्न
- (^{jji}) लिखित कथन
- (iv) अन्तवर्ती आबेदन
- (v) मूल याणिका

- (vi) शपथपत्र
- (vii) निष्पादन याचिका और
- (viii) अपील तथा पुनरीक्षण का ज्ञापन
- (ix) भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 32 के अधीन याचिका (पिटीशन)

(2) दाण्डिक:

- (i) परिवाद
- (ii) प्रकीर्ण दाण्डिक
- (iji) जमानत आवेदन और
- (iv) अपील और पुनरीक्षण का ज्ञापन

(इ) छात्र न्यायालय

छात्र न्यायालय के प्रयोजन के लिए ग्रुप बनाए जाएंगे और प्रत्यंक ग्रुप को ऐसे मामले दिए जाएंगे जिनमें अनेक विवाद्यक है। छात्र न्यायालय का लक्ष्य न्यायालय की पद्धति का व्यावहारिक प्रशिक्षण देना होगा, अर्थात् पक्षसार (ब्रीफ) को तैयार करना और मामले के मुद्दे पर वास्तव में बहुस करना। न्यायालयों और अधिवक्साओं का सहकार प्राप्त किया जा सकता है, विशेषकर विभिन्न न्यायालयों द्वारा विनिष्चय मामलों की पुस्तिका की प्रतियां पाने के लिए।

इस पाठ्यक्रम में न्यायालय में कार्य करने के लिए आवश्यक गुण और शिष्टाचार की बातों पर जोर दिया जाएगा।

इन छात्र न्यायालयों में उपस्थित अनिवार्य होगी। प्रत्येक से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह छात्र-न्यायालय मे कार्य करने की अपनी तैयारी का नियमित अभिलेख रखें।

(च) व्यावसायिक सदाचार

विधिज्ञ वर्ग के ज्येष्ठ सदस्यों को व्यावसायिक सदाचार विषय पर छह से दस कमबद्ध व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। भारतीय विधिज्ञ परिषद् के आदशों और विनिद्धिट परिस्थितियों में उनके लागू किए जाने पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है।

इन पाठ्यक्रमो में उपस्थित से सम्बन्धित नियमों का कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए और छान्न की प्रबीणता की परीक्षा के लिए समुचित अंक आबंदित किए जाने चाहिए। मूल्यांकन या तो लिखित परीक्षा के आधार पर या व्यावहारिक अभिलेख-पुस्तक में अभिलिखित दैनिक कार्य के आधार पर या मौखिक परीक्षा अथवा मूल्यांकन के इन तकनीकों में से किसी एक या एक में अधिक तकनीक के आधार पर किया जा सकता है। इन परीक्षाओं में या परीक्षणों में उत्तीणें हो जाने पर ही एल० एल० बी० की डिग्री मिल सकेगी।

(छ) विधिक सहायता शाखा

विधि के प्रत्येक व्यावसायिक महाविद्यालय के लिए यह बांछनीय है कि वह विधिक सहायता कार्यान्वयन समिति क्वारा यथा प्रस्तावित एक विधिक सहायताशाला खोले। समिति द्वारा सिफ रिश की गई आवर्ष स्कीम को इस प्रयोजन के लिए अपनाया जा सकता है। विधिक सहायता और विधिक-कल्प सेवाओं में छात्रों के योगदान का सावधानी से मूल्यांकन किया जाए और उसके लिए सम्यक् श्रेय दिया जाए।

ऐसे महाविद्यालयों में, जहां विधिक सहायताशाला कार्य नहीं कर रहीं हैं, छात्रों को समुचित रूप से कार्यक्रम तैयार करके स्थानीय विधिक सहायता समिति के काम में लगाये जा सकता है।

(ज) न्यावासय अवलोकन

ज्येच्ठ विधि-व्यावसायियों और विधि-अधिकारियों के निजी कक्षो (जिनके अन्तर्गत कारागार, पुलिस-याना, स्टाक एक्सचेंज, विधिक सहायता शिविर, अधिकरण आदि भी है) और न्यायालयों में जाकर श्रवलोकन व्यावहारिक प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसे सार्थक बनाने के लिए इनका आयोजन काफी लम्बी अविध तक के लिए करना होगा जिससे कि उनके समुचित सन्दर्भ में होने वाली प्रक्रियाओं को ध्यान से देखा और समझा जा सके। यदि इस कार्यक्रम का आयोजन और पाठ्यचर्या के साथ इसका तालमेल समुचित रूप से किया जाता है तो यह बौद्धिक विकास के लिए प्रेरणादायी होगा और व्यावसायिक चुनौतियों से भरा होगा।

टिप्पण

इस व्यावहारिक प्रामिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत छह मास तक के उपर्युक्त पाठ्यक्रम और सौ सौ अंकों के कम से कम चार प्रश्नपत्न होंगे। इसका गठन सम्बन्धित विधि महाविद्यालय पर निर्भर है। किन्तु यह आशा की जाती है कि विधि की शिक्षा एक व्यावसायिक कार्यक्रम होने के नाते पूर्ववर्ती पैरों में बताई गई न्यूनतम उपचार सम्बन्धी विषयवस्तु को परि-लक्षित करेगी। इस बात की आवश्यकता है कि छात्न प्रत्येक व्यावहारिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के बारे में अपनी अलग अलग अभिलेख पुस्तक रखें और ऐसे शिक्षकों को इन पाठ्य-क्रमों को चलाने का काम सौंपा जाए जिन्हें आवश्यक अनुभव प्राप्त हो। इस कार्यक्रम से छात्रों को व्यावहारिक कौशल तो मिलेगा ही, विधि-विद्यालय को अपनी पाठ्यचर्या समृद्ध करने में और समाज से सम्पर्क बढ़ाने में भी सहायता मिलेगी।

प्रस्थेक विश्वविद्यालय में संकाय इस बात पर ध्यान देगा कि नई पाठ्यचर्या में "विधि और निर्धनता", "विधि और ग्राम विकास" आदि विभिन्न वैकल्पिक पाठ्यकम आरम्भ किए गए हैं जिनके शिक्षण में व्यावहारिक पक्ष की परिकल्पना की गई है। संकाय सैद्धान्तिक पाठ्यकमों के साथ व्यावहारिक प्रशिक्षण का समुचित रूप से तालमेल करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा।

श्याम मोहन श्रीवास्तव सचिव भारतीय विधिज्ञ परिषद

भारतीय खाद्य निगम

नई दिल्लो, दिनांक 22 जनवरी 1983

सं० 22/एफ० सं० 6-1/76-ग्राई० सं ० वाल०-IV--भारतीय खाद्य निगम प्रधिनियम 1964 (1964 का 37) की घारा 45 द्वारा प्रयत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति से भारतीय खाद्य निगम निम्न विनियम बनाकर भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृन्द) विनियम 1971 में इस प्रकार संशोधन करता है:

- (i) ये विनियम भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारी-वृद) (85वां संशोधन) विनियम 1982 कहें जायगे।
- (ii) ये पहली नवम्बर 1977 से प्रभावी होंगे।
- 2. (i) भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृन्द) विनियम 1971 के विनियम 29 के नीचे निम्नलिखित नये विनियम 29-क को जोड़ा जायेगा। 29-क सेवा काल में प्रजित छुट्टी का भुनाना। परिषिट-5 में दिये गये नियमों और शतों के प्रनुसार निगम के नियमित कर्मचारियों को (खाद्य विभाग से स्थानान्तरित कमचारी सहित) वर्ष में एक बार प्रजित छुट्टी को भुनाने की स्वाइति होगी। इस विनियम के ग्रंतर्गन अजित छुट्टी में विनियम 30 के ग्रन्तर्गत कार्यंग्रहण प्रविध के ना लिये उस भाग को जो छुट्टी के खाते में प्रजित छुट्टी की तरह जोड़ा गया है, अ सिम्मलित नहीं किया जाएगा।
- (ii) भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृन्द) विनिधम 1971 में वर्तमान परिशिष्ट-4 के बाद एक नया परिशिष्ट-5 जोड़ा जायेगा:---

परिशिष्ट-- 5

निगम के नियमित कर्मचारियों द्वारा सेवाकाल में (संदर्भ विनियम 29 (क) श्राजित छुट्टियों को नकद भुगतान कराने के लिये नियम श्रीर शर्ते।

निगम के समस्त नियमित कर्मचारी (खाद्य स्थानांतिरत कर्मचारी सहित) को वर्ष में केवल एक बार निम्नलिखित सीमा तक प्रजित छुट्टियों को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति द्वारा भुनाने की इजाजत होगी।

- तिम्नलिखित वर्ग के कमचारियों को ग्राजित छुट्टियों को नगद भुनाने की इजाजत नहीं होगा।
 - (1) वे कर्मचारी जो दनिक मजूरी/ठेके पर काम करते हैं।
 - (2) केन्द्र/राज्य सरकार/श्रन्य उपक्रमों से, प्रतिनियुक्ति पर निगम में कार्य करने के लिये श्राये हुए, कमचारी।
 - (3) प्रशिक्षु/ग्रपरेंटिसी, ग्रौर
 - (4) निलंबित कर्मचारी।

- 3. अविदन के दिन यदि 45 दिन की भाजित सुट्टी कर्मचारों के खाते में नहीं होगी तो उसे भुनाने की स्वीकृति नहीं होगी।
- 4. एक समय में कर्मचारी के खाते मे जितनी भी श्राजित छुट्टी बकाया होगी उसमें से अविदन के दिन एक वर्ष में वेय अजित छुट्टी घटाकर बाकी अधिकतम श्राधी श्राजित छुट्टियों को नक्द "भुताया" जा सकेगा। दूसरे धब्दों मे आवेदन तिथि को यदि खाते मे "एक्स" श्राजित छुट्टी बकाया है और "वाहे" एक वर्ष में देय श्राजित छुट्टी दर्शाती है तो श्रधिकतम श्राजित छुट्टी जो नकद भुगतान की जा सकेगी वह "एक्स-वाई"/7 के बराबर होगी।

(टिप्पणी—कार्यग्रहण ग्रविध के ना लिये भाग को जो ग्रजित छुट्टी के खाते में है, को नकद नहीं भुनाया जा सकेगा।)

- 5. श्रर्जित छुट्टियों के (जिसके नकद भुगतान के लिये स्वीकृति मिली है) नकद भुगतान की राशि के लिये आवेदन के तिथि से पहले दिन तक प्राप्त परिलब्धियां श्राक्षार ोंगी। परिलब्धियों के श्रर्थ में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे।
 - (1) मूल वेतन
 - (2) विशेष वेतन्हें
 - (3) व्यक्तिगत वेतन
 - (4) मंहगाई भत्ता जिसमे श्रितिरक्त मंहगाई भत्ता भी सम्मिलित है।
- 6 परिलब्धियों में चार्ज भत्ता/डिप्लायमेंट भत्ता इसके लिये सम्मिलित नहीं होगा।
- 7. 30 दिन का महीना मानकर नकद भुगतान की राशि निकाली जाएगी।
- 8. खाते में बकाया अजित छुट्टी कमचारी के त्यागपत वेने या सेवा से निकाल देने, बर्खास्तर्गा या अनिवार्य सेवा- निवृत्ति या सेवा समाप्ति यदि भारतीय खाद्य निगम (कर्म- चारीवृन्द) विनियम के अल्पर्गत होगा तो उस स्थिति में उसका नकद भुगतान नही होगा।
- यदि इन नियमों श्रीर णतीं को समझने में कहीं कोई संदेह उठेगा तो उसमें बंध निदेशक का निर्णय श्रांतिम होगा।

व्याख्यात्मक 'ज्ञापन

सेवा काल की श्रविध में पंचांग वर्ष में एक बार श्रिजित छुट्टी का नक्ष भुगतान कराने की योजना निगम में 1 नवस्वर 77 से परिपन्न मं 6-1/76-श्राई० सी० दिनांक 13-12- 1977 जो 28, 29 नवस्वर 1977 निदेशक मंडल की 113वी बठक में अनुमोदन से श्रारम्भ हुई थी। इसकी पूर्व अनुमति वित्त मंद्रालय के श्रवीन लोक उद्यम ब्यूरो से भी प्राप्त कर ली गई था।

2- इस योजना के अनुसार आवेदन के दिन कर्मचारों के खाते में बकाया आर्धा अर्जित छुट्टी जिसमें से एक वर्ष में देम प्रजित छुट्टी कर्मच।री के खाते में रखकर शेष पंचीग वर्ष में एक बार नकद भुगतान किया जा सकता है।

- 3. भारतीय खाद्य निगम अधिनियम 1964 के प्रांतर्गत धारा 12क में क्षेत्रीय खाद्य निदेशालय में स्थानीतिरित कर्म-चारों को जिन्होंने केन्द्रीय मरकार के कर्मचारियों पर लागू निवृत्ति लाभ सामान्य निर्वाह निधि, छुट्टी नियम प्रथनाय हैं, को इस योजना के आरम्भ होने से मिलने वाले लाभ पर सरकारी लेखा परीक्षकों ने एतराज उठाया। लेखा आप-तियों को देखते हुए इस योजना की पुनः समीक्षा की गई तथा कानूनी सलाह लेकर यह निर्णय किया गया कि अजित छुट्टा के नकद भुगतान के मामूला लाभ को सेवाकाल में मामूला लाभ जमा नही दिया जाना चाहिए वरन् इस योजना को पूर्व से ही भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृन्ध) विनियम 1971 में जोड़ देना चाहिए क्योंकि ये ''सेवा धर्त'' है।
- 4. भारतीय राजपन्न मे भारतीय खाध निगम (कर्म-चारीयन्द) विनियम 1971 से संबंधित विनियम (29-क)

- का, इस योजना की प्रकाशन की तिथि से प्रभाव। व र को न् धन करना ठीक नहीं समझा गया बहिक इसका कार्यान्वयन होने को पहले से ही आवश्यकता है क्योंकि इससे धनेक कठिनाइया, श्रीद्योगिक समस्याओं सहित, प्रवासीनक जैसे किये गये भुगतान की बसूची जिस पर श्राजित छुट्टियों के नकद भुगनान लेने पर वर्मचारी श्रायकर भी 1977 श्रीर 1982 के मध्य दे बुके हैं तथा उनमें से कुछ कमचारी सेवा निवृत्त हो चुके हैं, त्यागपत्र दे चुके हैं या मर गये ह श्रादि की, समस्याये श्राती हैं।
- 5. 1-11-77 के बाद से प्रजित छुट्टी हेतु दिये गये नकद भुगतान का नियमन करने के लिये इस योजना को कर्मचारीवृन्द विनियम में "29-क" विनियम के रूप में जोड़ा जाता है श्रौर ये पूर्व में ही 1-11-77 से प्रभावी होंगे।

आर० नारायणस्वामी, सचिव

STATE BANK OF INDIA NOTICE

New Delhi, the 12th February 1983

NOTICE is hereby given that the Principal Register and the Branch Registers of the State Bank of India will be closed for transfer of shares from Thursday, the 10th March, 1983 to Thursday, the 24th March, 1983, both days inclusive.

R. P. GOYAL Chairman

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

New Delhi-110002, the 10th January, 1983

No. 5-CA(17)/82-83—With reference to this Institute's Notification Nos 4-CA(1) 11/81-82 dated 17-3-1982, 4-CA(1)/20/77-78 dated 18-2-1978 and 4-CA(1)/19/79-80 dated 15-3-1980 it is hereby notified in pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1964, that in exercise of the powers conferred by Regulation 17 of the said Regulations, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has restored to the Register of Members with offect from the dates mentioned against their names the names of the following gentlemen:—

	embership Number	Name & Address	Date of Restora- tion
1.	6688	Shri Manubhai Ambalal Patel, A.C.A., P.O. Box 60049, Livingstone.	11-12-82
2.	11633	Shri Ramesh Chandra Varshney, A.C.A., 5E/2, B.P. Railway Road, Faridabad-121001.	16-12-82
3.	30452	Shri Suresh Shankar Sapre, A.C.A., C/o Alexander Grant Mattar & Co., P.O. Box 6145. Sharjah (UAE)	4-11-82

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

The 21st January, 1983

No. 8-CA(31)/82-83—In pursuance of Regulation 10(1)(m of the Chartered Accountants Regulations, 1964, it is hereb notified that the Certificate of Practice Issued to the followin members have been cancelled from the dates mentione dagainst their names as they do not desire to hold the same.

S. Membarhsip No. Number		Name & Address	Date of Cancella- tion	
1	2	3	4	
1.	8480	Shri Kasturi Lal Kumar, A.C.A., Raccaform Limited, P.O. Box 434, Kundila Road, Kano, Nigerin	1-4-82	
2.	8549	Shri Birendra Kumar Gupta, F.C.A., O.C.M. India Ltd., P.B. No. 34, Amritsar.	1-4-82	
3.	16760	Shri Sushil Kumar, FCA, 227, Sector 19-A, Chandigarh.	1-4-82	
4.	17536	Shri Ashok Kumar, A.CA, M/s A.R. Kumar & Co., Chartered Accountants, F-105, Kirti Nagar, New Delhi-110 015.	1-4-82	
5.	70373	Shri Lalit Behari Singhal, A.C.A, C/o M/s Jugal Kishore Kashiram, Grain Market, Rohtak-124001. (Haryana)	1-4-82	
6.	80027	Shri Vipin Kapoor, ACA., 107, Hari Nagar Ashram, New Delhi-110 014.	1-4-82	
7.	80648	Shri Suresh Chhabra, ACA, 10400, Gali Mandir, Wali, Manak Pura, New Delhi-110005.	1-4-82	
8.	80694	Shri Suresh Kumar Mittal, ACA, 1/9225, Gali No. 6, West Rohtas Nagar, Shahdara, Delhi-110 032.	1-4-82	

1	2	3	4
9.	80743	Shri Rajan Jolly, ACA, B-2/5, Rana Pratap Bagh, Delhi-110 007.	1-4-82
10.	80752	Shri Prem Chand Jain, ACA, 7109, Pahari Dhiraj, Gali Pahar Wali, Delhi-110006.	1-4-82
11.	80835	Shri Vijay Seth, ACA, C-53, Defence Colony, New Delhi-110 024.	1-4-81
12.	80877	Shri Naresh Shankar, ACA., 3, Bela Road, Civil Lines, Delhi-1100054.	1-4-81
13.	81567	Shri Chander Mohan Khurana, ACA, C.M. Khurana & Co., Chartered Accountants, 999, Telian Street, Tilak Bazar, Delhi-110006.	11-1-83
14.	50016	Shri Arun Kumar Khanna, FCA, F-85, Kirti Nagar, New Delhi-110015.	1-8-82

The 27th January 1983

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. 1-CA(117)2/79.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 30 of the Chartered Accountants Act, 1949 (XXXVIII of 1949), the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has made the following amendment to the Chartered Accountants Regulations, 1964 the same having been previously published and approved by the Central Government as required under sub-section (3) of the said section.

In the said Regulations, for the existing regulation 23, substitute the following:—

"23. Refund of fees

- (1) The fee paid by a candidate who has been admitted to an examination, shall not, except as otherwise provided in sub-regulation (2), be refunded.
- (2) Where a candidate intimates to the Council within 15 days of the last day of the examination that he was prevented from attending the examination on account of curcumstances beyond his control, the Council may permit 50% of the appropriate fee paid by such candidate to be refunded to him."

P. S. GOPALAKRISHNAN Secretary

Kanpur-208001, the 13th January 1983

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. 4-CCA(3)/82-83—In pursuance of Regulation 16 of the Chartered Accountants Regulations, 1964, it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by Section 20(1)(a) of the Chartered Accountants Act. 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has removed from the Register of Members of this Institute on account of death, the name of the following member with effect from the date mentioned against his hame.

S. Me	mbership No.	Name & Address	Date of Removal	
1.	1379	Shri Siri Krishan Kapoor, 16/98, L.I.C. Building, The Mall, Kanpur-208 001.	7-11-82	

The 19th January 1983

No. 4-CCA(4)/82-83—In pursuance of Regulation 16 of the Chartered Accountants Regulations, 1964, it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by Section 20(1)(a) of the Chartered Accountants Act, 1949 the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has removed from the Register of Members of this Institute on account of death, the name of the following member with effect from the date mentioned against his name:—

S. Me No.	mbership No.	Name & Address	Date
1.	9764	Shri Purushottam Das Gupta, 46, Alimpura, Near, C A B Collage Meerut Cantt.	9-7-81

P.S. GOPALAKRISHNAN Secretary

Madras-600 034, the 17th January, 1983

No. 5SCA(7)/82-83—With reference to this Institute's Notification Nos. 4SCA(1)/9/79-80 dated 15th March, 1980, and 4ECA(1)/12/78-79 dated 28th December, 1979, it is hereby notified in purusance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1964 that in exercise of the powers conferred by Regulations, 1964 that in exercise of the powers conferred by Regulation 17 of the said Regulations, the Council of the Institute of Chartered Accountants, of India has restored to the Register of Members, with effect from the dates mentioned against their names, the names of the following gentlemen:—

S. No.	M. No.	Name & Address	Date of Restoration
1.	2447	Shri K.V. Subba Rao, FCA, Chartered Accountant, 1-8-702/19/A, Nallakunta, Hyderabad 500 044.	16-8-82
2.	50269	Shri K.K. Chadha, ACA, A-5, Ganesh Apartments, 14, D'Silva Road, Mylapor e , Madras 600 004.	21-12-82

P.S. GOPALAKRISHNAN, Secretary.

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 24th January 1983

No. U/16/53/82/Med. III (Gujatat).—In pursuance of the resolution passed by the ESI Corporation at its meeting held on 25th April, 1951, conferring upon me the powers of the Corporation, under Regulation 105 of the ESI (General) Regulations, 1950, I hereby authorise Dr. J. V. Lakkad, to function as medical authority w.e.f. 1-1-83 (FN) to 30-6-83, for Baroda centre, for the purpose of medical examination of the insured persons and grant of further certificates to them when the correctness of original certificates is in doubt.

The 28th January 1983

No. U/16/53/82-Med. III (Punjab).—In pursuance of the resolution passed by the E.S.I. Corporation at its meeting held on 25th April, 1951, conferring upon me the powers of the Corporation, under Regulation 105 of the E.S.I. (General) Regulations, 1950, I hereby authorise the Civil Surgeon, Civil Hospital, Kapurthala, to function as Medical Authority for Jagjit Nagar area, with effect from 15-2-83, on a remuneration of Rs. 75/- P.M., for the purpose of medical examination of the insured persons and grant of further certificates to them when the correctness of original certificate is in doubt, till such time a full-time Medical Referee is appointed for this centre.

DR. K. M. SAXENA Medical Commissioner

THE BAR COUNCIL OF INDIA

New Delhi, the 15th January 1983

Resolution passed by the Bar Council of India at its meeting on 7th May, 1982.

Resolution No. 79 1982

RESOLVED that in heu of the existing Rules in Part IV of the Rules of the Council the following rules be adopted under Sections 7(h) & (i), 24(1)(c)(iii) & (iiia) and 49(1)(af), (ag) and (d) of the Advocates Act regarding standards of Legal Education for admission as Advocate.

RESOLVED FURTHER that these rules will come into force from 7th May, 1982.

The question regarding extension of time for students who have failed to appear under the old Rules will be considered later.

SHYAM MOHAN SRIVASTAVA Secv., Bar Council of India

PREAMBLE OF THE RULES OF THE BAR COUNCIL OF INDIA IN PART IV

Whereas there is almost complete unanimity of opinion in the Country that Legal Education needs to be drastically altered and improved.

And whereas piecemeal changes introduced from time to time have not brought about any significant raising of standards and improvement in the quality of new entrants to the Bar.

And whereas it is the statutory obligation of the Bar Council of India to promote Legal Fducation and to lav down standards of such educaton for purposes of admission to the Bar.

And whereas the Legal Education Committee of the Bar Council of India has examined the problem in great depth in consultation with the Universities and State Bar Councils and made its proposals,

And whereas the Bar Council of India has considered the implications and merits of the said proposals,

And whereas it is now recognised the world over that apart from technical knowledge of law a liberal education involving exposure to other disciplines and fields of knowledge in particular the humanities is essential to enable a lawyer to make a useful contribution to social change and development

This Council in exercise of its powers under Section 7(h), and (i), 24 and 49(1) of the Advocates Act 1961 and all other powers enabling it so to do, make the following rules.

PART-IV

Standards of Legal Education and Recognition of Degrees in Law for admission as Advocate

(Rules under Section 7 (h) and (i), 24(l)(c)(iii), and (iiia), and p9(l)(af), (ag) and (d) of the Act

- 1. (1) Save as provided in Rules 23, 24 and 25 of the rules hereunder a degree in law obtained from any University in the territory of India shall not be recognised for numbers of enrolment as advocate under the Advocates Act. 1961 from line 1, 1982 unless the following conditions are fulfilled:
 - (a) That at the time of joining the course of instruction in low for a degree in law the nerson concerned has passed an examination in 10-L2 course of schooling recognized by the educational authority of the Central or the State Governments or nossesses such academic qualifications which are considered equivalent to such 10 + 2 courses by the Bur Council of In In.

- (2) The law degree has been obtained after undergoing a regular course of study in a duly recognised law college under these rules for a minimum period of five years, out of which the first two years shall be devoted to study of pre-law courses as necessary qualification, for admission to three year course of study in law to be commenced thereafter. The last six months of the three years of the law course shall include a regular course of practical training.
- (c) That the course of study in law has been by regular attendance for the requisite number of lectures, tutorials, moot courts and practical training given by a college affiliated to a University recognised by the Bar Council of India.
- 2. A law college shall only be located at a place where there is a District Court or a Circuit District Court.
- 3. (1) Professional law education shall only be through whole time day colleges or University departments from the academic year 1982-83.

Provided such of the Universities which cannot implement the new rules from June 1, 1982 may continue the old system under intimation to the Bar Council of India for a term not exceeding two years from 1982-83. After such intimation the said Universities shall comply with requirement of Rule 23.

Provided further that the students who have been admitted to the 1st year LLB. before 1st June. 1982 can continue to receive their education through part-time morning/evening colleges as the case may be.

- (2) A College will be deemed to be whole-time day college for the purpose of Sub-Rule (1) if the working time of the college or University department extends to at least 5½ hours continuously on every working day comprising of class room teaching which shall include at least 4 periods of one hour each and the remaining 1½ hours of the working day devoted for contact programmes with teachers, library work, tutorial work and similar curricular and extra-curricular work in the campus of the college.
- (3) The library of the college or University Department shall remain open for at least 8 hours on every working day
- (4) The strength of part-time teachers shall not be more than 50 per cent of the total strength of the teachers.
- (5) The Principal of the College shall oridnarily be full-time teacher in the College.
- 4. The medium of instruction shall ordinarily be English. Where the medium of instruction in law is not English, or where he has in fact answered the papers for the law examination in a language other than English, he shall as a condition of his enrolment be required to pass a written test on 'Profic' nev in English' to be conducted by a State Bar Council except when he has passed such a test as a part of his course of instruction in law.

Explanation: The test above mentioned shall require the standards of a holder of Bachelor's degree of a recognised University.

5. Admission of a student to the course of instruction in law shall ordinarily be on the basis of merit. No student shall be admitted to the course of instruction in law unless he has inter alla, obtained 45 per cent marks in the augmented in the qualifying examination for admission.

Provided that in the case of students of Scheduled Castes and Scheduled Tribes a relaxation of marks upto 5% in the qualifying examination may be given.

- 6. The students shall be required to out in a minimum attendance of 66% of the lectures on each of the subjects as also at tutorials, most courts and practical training course
- 7 Jaw Colleges and University Law Departments shall ensure that :-
 - (a) multiple conjes of prescribed and recommended readings are available in the library:
 - (b) serving arrangements is provided for at least 15% of the students at a time in the reading hall;

- (c) the teacher student ratio is at least 1:40.
- 8. The maximum strength of students in any class (LL.,B. I, II, III, IV or V) shall not exceed 320 in any given College or University Department of Law and the number of students in any section of each of such class shall not exceed 80. In other words no College or University Department of Law shall have on its rolls a total student strength of over 1600 students in all its 1st, 2nd, 3rd 4th and 5th years put together.

9. BUILDING

- (1) (a) The building of a college shall be available for its exclusive use, during the working hours of the college.
 - (b) The accommodation provided for classes, hostel, if any, and the residential quarters for the Principal and the teacher to be in-charge of the hostel, if any, will be separate.
- (2) The college buildings shall consist of the following:---
 - (a) Class rooms:

A common room for men students;

A common room for women students;

A library half with book shelves and reading tables:

Office rooms for the Principal and his office staff; A teachers common room.

(b) Quarters for the Principal;

Quarters for the teacher in-charge of the hostel, if any, located near the hostel.

Quarters for other permanent teachers as and if required by the University.

- (3) (a) All buildings shall be well lighted and ventilated and shall have adequate sanitary arrangements and water supply.
 - (b) All buildings shall be duly furnished.
- (4) (a) If the college has no building of its own and it is proposed to be housed temporarily in a hired building, the college authorities shall create the building fund which shall be set apart and deposited in a Scheduled Bank or a District Central Co-operative Bank.
 - (b) This building fund of at least Rs. 2 lakhs shall be created through instalments as under :--

Initial		Rs.	00.000,00,1
First Year		Rs.	40,000.00
Second Year		Rs.	20,000.00
Third Year		Rs.	20,000.00
Fourth Year		Rs.	20,000,00

- (c) Deposits so made in the name of the college shall be not withdrawn except when required for meeting the cost of the portion of the building already constructed.
- (d) The buildings shall be completed within a period of 4 years from the date of the approval of affiliation is communicated to the Registrar of the University concerned.
- (5) Provision shall also be made for a play-ground and adequate facilities for games and sports shall be made available in the vicinity of the College Buildings.

10 LIBRARY

- (a) The Library shall be adequately equipped with law reports, books, periodicals and reference books to meet the requirements of the courses of instruction taught in the College.
- (b) The library shall be in the charge of a qualified and trained librarian.

(c) The minimum initial and recurring annual expenditure on the library shall be as below:

Initial	Rs. 50,000.00
First Year	Rs. 15,000.00
Second Year	Rs. 15,000.00
Third Year	Rs. 15,000.00
Subsequent Years	Rs. 10,000,00 per ye

11. (1) The courses of instruction for the preparatory for law degree course shall include the following 7 compulsory subject:—

1. Comment Products (Co. Acres Ottom South)

1. General English (Graduate Standard)	Z Papen
2. Political Science	1 Paper
3. Economics	1 Paper
4. History	1 Paper
5. Sociology	1 Paper
6. Legal Language including Legal Writing	1 Paper
7. History of Courts, Legislatures and Legal Profession in India	1 Paper

Explanation: The Bar Council of India in consultation with experts formulated tentative outlines of the courses in he preparatory stage and recommends them to the Universities imparting professional education in law. The suggested course outlines are attached to these rules as Appendices A to G.

(2) The courses of instruction for three years of the study in law shall include the following 12 compulsory subjects:—

1. (a) General principles of contract	1 Paper
(b) Special Contract	1 Paper
2. Torts	1 Paper
3. Family Law	
(a) Hindu Law	1 Paper
(b) Mohammaden Law, Indian Succession and Indian Divorce Act	1 Paper
4. Law of Crime and Procedure	2 Papers
5. Constitutional Law of India	1 Paper
6. Property Law and Essements	1 Paper
7. Evidence	1 Paper
8. Legal Theory (Jurisprudence)	1 Paper
9. Civil Procedures, Limitation and Arbitra-	
tlon	1 Paper
10. Administrative Law	1 Paper
11. Public International Law	1 Paper

- 12. Practical Training.—Six months instruction which shall include court visits, documents, rules of courts, exercise in drafting, pleading, work of Lawyers' Chamber and attendance at Professional Ethics lectures. The student shall be required to pass an examination in this course to be conducted by the University concerned.
- (3) Not less than 6 more subjects which may be chosen from the list hereunder and from amongst such other law subjects locally relevant as may be prescribed by the Universities at their option:
 - 1. Equity
 - 2. Company Law
 - 3. Labour Law
 - 4. Taxation
 - 5. International Organisation
 - 6. Bankruntev
 - 7. Law of Cooperation and Public Control of Business
 - 8. Legislative Drafting
 - 9. Military Law
 - 10. Insurance

- 11. Trusts and other Fiduciary Obligation
- 12. Trade Marks, Copy Rights and Patents
- 13. International Economic Law
- 14. Criminology and Criminal Administration
- 15. Interpretation of Statutes and Principles of Legislation
- 16. Legal Remedies
- 17. Private International Law
- 18. Comparative Law
- 19. Law and Social Change
- 20. Law and Poverty
- 21. Law relating to Land Revenue, Land Reform and Rural Development
- 22. Law and Planning
- 23. Law relating to Local Self Government.
- 12. For each paper there shall be lecture classes for least 3 hours and one hour of intorial work per week.
- 13. The examination shall ordinarily be held at the end of every year. The University shall, however, be at liberty to hold examinations at the end of every 6 months. Suitable allocation of subjects for the period of one year or six months as the case may be shall be made by the University and the same be intimated to the Bar Council of India.
- 14. Every University shall endeavour to supplement the lecture method with the case method, tutorials and other modern techniques of imparting legal education.
- 15. Full-time teachers of law including the Principal of the college shall be holders of a Master's degree in law and where the holders of Master's degree in law are not available, persons with teaching experience for a minimum period of 5 years in law may be considered. Part time teachers other than one with L1.M. Degree shall have a minimum practice of 5 years at the Bar.
- 16. Universities shall establish or recognise only those colleges which have whole time day classes in law and have the requisite facilities and library as required by these rules.
- 17. The teaching load of full-time and part time teachers shall be according to the norms prescribed by the U.G.C. from time to time
- 18. The salaries paid to the Principal, full-time and parttime teachers shall be according to the scales recommended by the U.G.C. from time to time.

Other benefits like D.A., C.L.A. (Compensatory Local Allowance). House Rent Allowance, Provident Fund, etc. shall be according to the norms prescribed by the University concerned from time to time

19. A law college affiliated to a University shall by June 1, 1982 be an Independent I aw College and shall cease to be a department attached to a College.

Independent law college means a full-time day college with a regular qualified full time principal and requisite staff and facilities as provided by these rules.

- 20. (1) No college started after the coming into force of those rules shall impart instruction in a course of study in law for enrolment as an advocate unless is affiliation has been approved by the Bar Council of India.
- (2) An existing law college shall not be competent to impart instruction in a course of study in law for enrolment as an advocate if the continuance of its affiliation is disapproved by the Bar Council of India.
- 21. The Bar Council of India shall cause a law college affiliated or sought to be affiliated to a University to be inspected by a Committe to be appointed by it for the purpose, when:—
 - (a) An application for approval of affiliation of a new college is received by it; or
 - it sug moto decides in order to ensure that the standards of legal education laid down by it are being complied with.

- (b) The application for approved of affiliation of new College shall be addressed to the Secretary Bar Council of India, and shall be sent only through the Registrar of the University concerned with his recommendation.
- (c) The College and/or the University concorned shall furnish all the information to the committee of inspection and the Bar Council of India as and when required, and shall co-operate with them in every possible manner in the conduct of inspection.
- (d) The committee of inspection shall submit a detailed report to the Bar Council with a clear recommendation as to whether the affiliation of new college be approved/disapproved or that of an existing college be withdrawn/continued or that certain directions be given for improvements to be carried out within the period to be specified.

The report shall incorporate the reasons for the recommendations.

- (e) If an unfavourable report is received, the Secretary of the Bar Council of India shal cause a copy of the same to be sent to the Registrar of the University concerned for his comments and explanations, if any. Such comments and explanations on the Report shall be sent by the Registrar of the University within a period of six weeks from the date of the receipt of the communication.
- (f) The Secretary of the Bar Council of India shall cause the Report and the comments/explanation of Registrar of the University concerne to be placed before the next meeting of the Legal Education Committee of the Bar Council of India.
- (g) If the Legal Education Committee is satisfied that the standards of legal education and/or the rules for affiliation or continuance of affiliation provided for in these rules by the Bar Council of India are not complied with and/or that the courses of study, teaching and/or examination are not such as to secure to persons undergoing legal education, the knowledge and training requisite for the competent practice of law, the legal education committee shall recommend to the Bar Council of India the approval/disapproval of affiliation or continuance of affiliation as the case may be.

The legal Education Committee may also recommend that certain directions be given for improvements to be carried out within the period to be specified.

- (h) This recommendation of the Legal Education Committee along with the accommanying papers shall be placed before the Bar Council of India for its decision.
 - In the case the Bar Council of India disagrees with or modifies the recommendation of the Legal Education Committee, it shall communicate its views to the Legal Education Committee for its consideration before arriving at a final decision in the matter.
- (i) If the Council is of the opinion that affiliation of a college be disapproved it shall give notice of the proposed action to the Principal of the college and Registrar of the University to show cause within 30 days of the receipt of the notice and the Council shall take into consideration the reply received before making final orders
- The decision of the Bar Council of India shall be communicated to the Registrar of the University.
 - It shall be effective from the commencement of the next academic veer following the dute on which it is received by the Registrar of the University
- 22. (1) The Council shall publish by notification in the Gezette of India and in prominent newspapers in India, the names of Universities whose degrees in Law are recognised under these rules with a list of Law College under the Universities which are eligible to impart professional Legal Education as provided for under these rules and send a copy of the notification above referred to, to all the Universities imparting Legal Education and State Bar Councils.

Provided that for the purpose of sub-rule (1) above the existing University Law Departments and Law Colleges affiliated to universities shall be deemed to be professional law Colleges under these rules unless otherwise decided by the Council

- (2) Information about the non-recognition of letecognition of the degree in law of any University shall also be sent to all Universities in India imparting Legal Education and to all State Bar Councils.
- 23. (1) Those Universities and Colleges which are approved by the Bar Council of India as professional institutions under the new rules will commence professional legal education according to these rules from the academic year 4982-83. However, Universities, wanting more time for changing over to the new Scheme may be allowed permission by the Council to run the existing three-year I L B. Course for a period not more than two academic years. If such permission is granted they may continue to admit graduates for the existing L B. Course till and inclusive of the academic year 1983-84.
- (2) Such Universities seeking time for the change over must declare their intention to switch over to legal education under these rules lates; by the academic year 1984-85 and send a report within a year from lune 1, 1982 to the Bar Council of In lia on the steps adopted for the purpose.
- 24 (1) Students have joined the first year of the graduate course (B.A. B.Sc., B.Com. etc.) in 1982-83 or earlier will be eligible to pursue legal education under the old rules. The LI B course under the old rules may admit such students till the beginning of the academic year 1985-86
- (2) Admission to the LL.B. Course under the old rules will, however, be totally discontinued in such institutions after the academic year 1985-86.

Provided that such Universities may conduct examinations in 1st, 2nd or 3rd year LLB Courses to clear off the incumbents till such time the Universities may deem fit.

- 25. (1) If Universities located in States where the 10+2 school system is not yet in vogue propose to start the LLB. Course under the new rules they will be free to do so.
- (2) Universities in such States will also be allowed to continue with the existing ILR Course under the old rules until and inclusive of the academic year 1984-85.

NOTE:

The Rules above referred to professional legal education only for which the Bar Council of India has statutory responsibility under the Advocates' Act. It is the expectation of the Council that Universities and Colleges in the Country will continue to impart liberal education in law and expand it to larger sections of people by developing correspondence programmes if necessary for the benefit of persons in different occupations and in public life so as to advance their occupational goals on the one hand and assist the rule of law and Constitutional Government on the other. This would mean that the Country may require not only the existing centres of liberal education in law working at convenient hours in the morning or in the evening, but also several more such institutions in the remote corners of our vest Country. The rules now formulated are directed towards professional legal education and not towards other colleges which may continue within the framework of the University system in the Country.

THE BAR COUNCIL OF INDIA

- I. Outlines of courses for the subjects prescribed for the 2 year Pre-law-Study of the new Scheme of 5 year Law education after 10+2 under Rule 11(1) of the Rules of the Bar Council of India in Part IV are market as appendices (A to G).
- If The Practical Training Scheme (Serial No. 12 in Rule 11(2) prepared by the Bar Council of India for adoption by Universities is set out in Page No. 34—36
- III The recommended condines are tentative and not exhaustive of all the topics prescribed for the various courses. The Board of Studies and Faculties of Jaw of each University will add and develop the appropriate reading materials. for

each course and keep modifying them so as to up-date the materials and make them relevant to the local requirements.

- IV. The year of publication given against the books need not necessarily be of the latest edition. However, Universities are supposed to prescribe the last edition of the book concerned.
- V. It may be noted that the subject of Political Science has been expanded into three papers (Political Science I, II and III) instead of one as originally put in Rule 11 (1).

SHYAM MOHAN SRIVASTAVA Secretary Bar Council of India

APPENDIX-A

1 GENERAL FNGLISH

The object for introducing General English as a compulsory course in pre-law study emerges out of Rule 4 of Part IV on Standards of Legal Education. While insisting on Proficiency in English', the Bar Council of India expects the law graduates to have the minimum language skills necessary for effective legal practice in the trial and appellate Courts. The skills contemplated as essential to a lawyer are: communication skills (both written and oral) as well as skills of comprehension (learning by reading and listening).

There can be many methods and diverse materials in imparting those skills. It is expected that each University depending upon its resources and facilities available will develop the best possible strategies and incorporate them in the syllabit on English I anguage courses (English I and English II) so as to achieve the above skills in the student. The minimum expected by the course is to give a functional knowledge of the language for the purpose of communication and comprehension in legal business. This would require obviously emphasis on both General English as well as English for legal purpose. The main focus, however, is on the use of English language for the purpose of understanding and transacting legal business.

The English Language course is conceived as comprising of two papers one in each year of the pre-law study (English I and English II). The following syllabus evolved in consultation with Law and Language teachers is suggested to the Universities so that it may help them to structure their own syllabil in this regard.

ENGLISH--I

- (A) Grammar and Usage (Communication Skills)
 - 1. Simple Sentences (one clause) (their phrase structure)
 - (i) tense and concord
 - (ii) noun modifiers (determiners, propositional phrases clauses)
 - (iii) basic transformations
 - (a) passives
 - (b) negatives
 - (c) questions
 - 2. Complex and Compound Sentences (use of connectives)
 - 3. Conditionals
 - 4. Reported Speech
 - 5. Question-tags and short responses
 - 6. Some common Errors
- (B) Vocabulary (Communication Skills)
 - 1 Legal Terms (relevant to the subject papers of an LLB Student)
 - 2 Use of Legal Terms and idiomatic expressions
- (C) Comprehension Skills
 - 1. Reading Comprehension (Principles and Practice)
 - 2. Listening Comprehension

(D) Composition Skills

- 1. Paragraph Writing
- 2. Formal Correspondence
- 3. Note-taking
- Translation from regional language into English and vice-versa.

FNGLISH--II

(A) Vocabulary

- 1. Foreign words and phrases (impo.tant Latin and English affixes)
- 2. Certain set expressions and phrases
- 2. One-word substitution
- 4. Words often confused.
- (B) Comprehension Skills
 - 2. Common Logical Fallacies
 - 2. Comprehension of Legal Texts

(C) Composition Skills

- 1. Use of cohesive devices (Legal drafting)
- 2. Precis-writing, summatizing and briefing
- 3. Brief-writing and drafting of reports
- 4. Essay writing on topics of legal inferest
- 5. Varieties of sentence structures and verb patterns
- tenslation (from English to regional languages and from regional languages to l'nglish)

(D) Speech Training

- 1. Reading aloud (knowledge of proper pauses)
- 2. Key sounds, then discrimination and accent
- 3 Consulting a Pronouncing Dictionary.
- 4. Rapid reading and Debating exercices.

RECOMMENDED SOURCE MATERIALS

- 1. Selected materials drawn from renowned Judgmen's
- M.K. Gandhi—The Law and The Lawyers, Navjivan Publications, Ahmedabad, 1962.
- 3. Ishtiaque Abidi---Law and Language, University Publishers, Aligath, 1978.
- 4. Materials drawn from legal notices, petitions, appeals, court orders, statutes, bills, rules etc.
- Any standard Textbook on Structural English and Grammar appropriate to the level of understanding of the students.
- 6 Hindi-English Glossary, Vidhi Sahitya Prakashan, Ministry of Law, New Delhi.
- Denning—Duc Process of Law, London, Battorworths.
- M.C. Chagla-—Roses in December, Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay
- Burke Edmund—Impeachment of Warren Hastings I ondon' G. Well.
- M.C. Setalvad—Common Law in India, Hamiyn Lectures, Stvens and Sons.

APPENDIX-B

2. POLITICAL SCIENCE

The three Political Science courses are designed to give students basic knowledge about theories of state, organisation and forms of government, notions of moral and political obligation, political ideologies, including Indian Political thought, theories of justice and international organisation and relations. The courses aim to give detailed grounding in approaches and notions relevant to the study of juri-prudence, criminology and penology, public law (constitutional and administrative law) and international law and organisation. The courses are designated; Politic

cal Science I, Political Science II and Political Science III At least on, course should be offered in each of the two years in pre-law phase. Political Science II a III are less ouered in the second year.

POLITICAL SCHENCE--1

(A) Political Theory

- 1. Conceptions of State and Government.
- 2 Maia Currents of Western Political Thought; Medieval Political thought (Natural law and natural rights), liberalism, socialism and marxism.
- 3. Main currents of Indian political thought; classical Hindu and Islamic conceptions of state, political ideologies in nineteenth Century (growth of liberalism); Gandhism, Sarvodaya, Marxist thoughts in India.
- 4. Conceptions of Political and Legal Sovereignty
- 5. The Fotalitarian State.

(B) Political Or anisation

- Organisation of government: Unitary/federal/quasifederal, (one-party democracies, military rule, presidential and cabinet forms).
- The legislature, executive and judiciary; the doctrines of separation of power, parliamentary sovereignty, and independence of the Judiciary.
- Conceptions of representation, public opinion and participation.

POLITICAL SCIENCE—II

Loundations of Political Obligation

- 1. Conceptions of power, authority and legitimation.
- 2. How does power become legitimate power or why near to only the state? Examination of clossical (Hobbes Locke, Rousseau) and modern (Max Weber, Mark, Limile Dirkheim) approaches to the notion of political obligation.
- 2 Utilitarianism (both rule and act utilitarianism) as approaches to political obligation.
- 4 The moblem of civil disobedience and political obligation, with particular reference to Gandhian and Neo-Gandhian thought.
- 5. The problem of obediente to unjust laws.
- 6. Why should we honour promises and contracts? (Foundations of promiseory and contractual liability)
- 7. The problem of punishment: when is use of force by state against the citizen just and justifiable?

 (The besis of cruninal sanction.)
- 8. The contemporary crisis of legitimation.

POLITICAL SCIENCE-III

Laternational Relations & Organization :

This course is rather introductory. Its method is descriptive and analytical. A course based on a more complex method may be taught, if so desired, at an advanced stage of the LLB, course.

The course is divisible into two major parts; Part I, International Relations and Part II, International Organization.

Part I. The world community; sovereign states, trans national political parties, and transnational non-official organizations such as the churches, multinational corporations, scientific, cultural and other organizations. Components of national power, population geography, resources, economic organization, technology and military force. Limitations on national power: international morality, public opinion, international law, fear of violence and destruction, were with conventional and nuclear weapons. Major sources of conflict: East and West and North and South rivalries, territorial claims, resources, population migrations, international trade, balance of payments and protectionism.

Avoidance of war and facilitation of peacetul enange. alliances and balance of power approach; conceive security and disarmament; diplomacy and peaceful resolution of condicts by negotiation, mediation, concilation and recourse to international organizations; arburation and judicial settlement; the cultural approach and the UNESCO; promotion or international cooperation and the functional approach, the Specialized Agencies. The case for and against world government.

Part II: Inter-governmental organizations and their constituent instruments; the standard pattern of organization: the annual or periodical plenary conference, the committee or council to take decisions during the period between the plenary conferences, the secretariat. The special features of the L.L.O. and international financial institutions. The United Nations and its principal organs; the relationship between the United Nations and Regional Organisations, Specialized Agencies and international non-governmental organizations.

RECOMMENDED SOURCE MATERIALS

- Leslie Lipson—Great Issues of Politics. An Introduction to Political Science, New York, Prentice Hall, 1954.
- 2. Cr.N. Singh—Fundamentals of Political Science and Organisation. Allahabad, Kitab Mahal, 1966.
- K. R. Bombawall—Indian Politics and Government since 1885. Delhi Atma Ram and Sons 1951.
- Hans Morgenthau—Politics Among Nations. The Struggle for Power and Peace. 2nd Ed. New York knopt 1955.
- Quincy Wright—Study of International Relations. New York, Appleton—Century Crofts 1955.
- D. W. Bowett, International Institutions, London, Methuen 1964.
- Percy Cohen—Modern Social Theory (Arnold Heinman 1976).
- 8. Denis Lloyd-The Idea of Law (Pelican, 1964).
- D. D. Raphel—Problems of Political Philosophy Machmillan, 19).
- Roscoe Pound—An Introduction to the Philosophy of Law (Yale Uni. Press 1954).
- Upendra Baxi—The Crisis of the Indian Legal System (Vikas, 1982).
- H. L. A. Hart—Essay on Punishment & Responsibility (Oxford, 1958).
- S. E. Finer—Comparative Government (Pelican, 1970).
- 14. Rajani Kothari—Democratic Polity and Social Change in India: Crisis and Opportunities (Allied publishers, 1976).
- George Lich Theim—A Short History of Socialism (Fontanal Collins, 1970).
- U. N. Ghoshal—A History of Indian Political Ideas (Oxford 59).
- K. P. Karunakaran—Modern Indian Political Traditions (Allied, 1962).
- G. H. Sabine—A History of Political Theory (Fourth Edn. Oxford 1973).
- G. Sawer—Modern Federalism, London C.A. Watts 1969.
- 20. S. P. Verma-Modern Political Theory, Vikas, 1980.

APPENDIX--C

3. ECONOMICS

The Course content of Economics for the Pre-law course may consist of two part, Part-A—-Economics: General Principles, Part-B:—Indian Economics.

The object is not just to acquaint students with Economics as an academic discipline but to relate economic principles to the processes of law and to project their inter-relationships so that it may help better understanding of the subjects such as Contracts, Company Law, Taxation, Industrial

Law etc Beids knowldgs of conomics is essential to a proper understanding of Jurisprudence, constitutional developments and planned development.

PART-A: GENERAL PRINCIPLES

- (a) Economics as a Science and its relevance to Law;
- (b) Economics as a basis of Social Welfare and Social Justice;
- (c) Free Enterprise, Planned Economies and Mixed Economies

General Principles of Economics

- (i) Demand and Supply;
- (ii) Markets, determination of prices, business organizations;
- (iii) Labour and Wages;
- (iv) Capital and Money;
- (v) Saving, Consumption, Investment.
- (d) International comparisons of developmental strategies and experience—Theories of economic growth and problems of development.
- (e) Control of monopolies and prevention of economic concentration.
- (f) Banking and Fiscal Policy.
 - (i) Resource Mobilisation and fiscal resources Taxation;
 - (ii) The role of credit and banking system: Rural money markets;
 - (iii) International financial institutions;
 - (iv) Technology and Economic growth.

PART-B : INDIAN ECONOMICS

- I. Introduction to Indian Economy
 - (a) Trends in population growth
 - (b) Estimates of National Income in India.
 - (c) Po-t-independence economic policies in India.
- II. Poverty and Income Distribution
 - (a) Trends and inter-regional variations in the incidence of rural poverty.
 - (b) Unemployment trends and employment generation schemes.
 - (c) Labour Productivity and Wages.
- III. The Logic of India's Development strategy
 - (a) Planning process.
 - (b) Priorities between agriculture and industry.
 - (c) Choice of technology.
 - (d) The role of public, private and joint sectors,
 - (e) I arge, medium and small industries.
- IV. Problem of controlling economic concentration
 - (a) Regulation of the Private Corporate Sector (Controls, Licences, Quotas)
 - (b) Anti-monopolies and Restrictive Practices; Regulations:
 - (c) Deficit Financing
 - (d) Pricing
 - (e) Labour Relations
- V. Foreign Investments
 - (a) International Investment
 - (b) International Aid
 - (c) International Corporations
 - (d) Trends in new economic order
- VI. Export and Import Policies: Import substitution and Export promotion

VII. Agricultural Economics

- (a) Basic characteristics of the econmy and its transformation since Independence.
- (b) Evolution of Agrarian Relations. Integrated rural development
- (c) Commercialisation of Agriculture.
- (d) Economics of Farm Management.
- (c) Agricultural credit.

VIII. Role of capitul formation, credit and banking system

RECOMMENDED SCURCE MATERIALS

- Alfred W. Stonier and Douglas C. Hague—The Essentials of Economics, London, Longmans 1955.
- Ruddar Datt and Sundram—Indian Economy, Delhi,
 Chand & Co. 1982.
- A. N. Agrwala—Indian Economics, New Delhi, Vikas 1979.
- Paul Samuelson—Economics—An Introductory Analysis (International Student Edition Mc-Grew-Hill Book Company, Seventh Edition, 1961).
- 5. Fredrithue Lewis—Theory of Economic Growth (Unwin University Books 1954, 9th Impression, 1970).
- V. Y. Gupta—Working of Stock Exchanges in India, Delhi, (Thomson Press, 1972.)
- S. Ghatak—Rural Money Markets in India, Delhi, (Mechmillon 1976.)
- C. H. Hanumanthae Rao & P. C. Joshi—Reflections of Economic Development and Social change Essays in Honour of V. K. R. V. Rao (Allied, 1979).
- P. K. Chaudhri—The Indian Economy—Powerty and Development (Vikas, 1978).
- C. T. Kurien—Planning, Powerty and Social Transformation (Allied 1976).
- M. Dipton—Why Poor People Stay Poor—Urban Bias in World Development (Heritage Publishers, New Delhi 1980).
- 12. Myrdal, Gunnar—The Challenge of World Poverty (Penguin, 1971).
- 13. Lakshmi Narain—Principles and Practice of Public Enterprise Management (S. Chand, 1980).
- Mahbub Ul Haq—The Poverty: Certain Choices for the Third World (Oxford, 1976).
- H. W. Singer & J. S. Ansari—Rich and Poor Countries (Allen & Unwin, Third Edn. 82).
- L. N Rangarajan—Commodity Conflict—The Political Economy of International Commodity Negotiations (Croom, Helm Ltd. 1978).
- 17. V. Gauri Shankar—Taming the Giants. (Multinational Corporations in India) (Sterling, 1980).
- 18. I. Livingstone, (ed)—Economic Policy for Development (Penguin, 1971).
- 19. P. C. Joshi-Land Reforms in India (Allied 1976).

APPFNDIX-D

4. HISTORY

The course detailed below is intended to give broad idea to the student about the main currents of social, political, legal and cultural movements in the course of Indian history which influenced the legal system and its institutions. It is expected that the trucher instead of describing mere chronology of events will acquaint the student with the Indian cultural heritage in the above fields so that he may be able to critically appreciate the relevance of the present institutions of Indian democracy which are to be taught in the law courses.

(a) Ancient Indian cultural heritage; social, political legal and in the area of religion and philosophy. (The teacher is expected to give special emphasis on study of village republics in Ancient India, the organisation of Central Government in Ancient India, experiments in decentralisation, ancient law givers and

- dispute resolution systems in ancient India—Pre Islamic period): Law in relation to culture.
- (b) The advent of Islam: inter-action between Ancient Indian cultural heritage and Islamic culture and the emergence of synthetic Indian culture. Innovation by Rulers of Medieval period in the area of Revenue Administration, District Administration, Court System.
- (c) Indian contact with the Luropeans: Impact of European culture on Indian history and Indian National Movement; impact of European liberal thought on the Indian National Movement and Constitutional Developments in India upto 1947. Study of social reform movements in Modern India and its impact on legal culture.
- (d) Economic history of India during British period.

RI-COMMENDED SOURCE MATERIAL

- A.R.Desai—Social Fackground of Indian Nationalism Popular Bombay (1948).
- R.C. Majumdar—History of the Freedom Movement in India, Calcutta, MukhopaJyaya.
- V.P. Menon—The Trasfer of Power in India Bombov, Orient Longmans.
- B. Shiva Rao—India's Freedom Movements, New Delhi, Orient Longman, (1972).
- Pattabhi Sitaramayya.—History of the Indian National Congress, Bombay, Padma Publications.
- 6. Tara Chand-History of Freedom Movement in Inc.to.
- 7. V. P. Menon-The Story of Integration of Indian States, Calcutta, Orient Longmans.

APPFNDIX---E

5 SOCIOLOGY

While giving an idea of the general principles of Sociology in the context of Indian society and its institutions, the Course shall strive to reveal to the students the role of law as social engineering. The essential moonings of Law in Society will be identified and the limits and limitations of Law as an instrument of social Change will be highlighted through illustrations and empirical studies.

The Course content of Sociology for the Pre-Law Course may consist of two parts.

Part A: Sociology: General Principles

Part B: Socialology of India.

PART A: SOCIOLOGY: GENERAL PRINCIPLES

- 1. Sociology as a Science:
 - (a) data, concepts and theory.
 - (b) the comparative method.
- 2. Basic concepts in Sociology:
 - (a) Structure and function.
 - (b) Status and role.
 - (c) Norms and Values.
 - (d) Institutions.
- 3. Social Institutions
 - (a) marriage, family and kinship.
 - (b) work and economic institutions,
 - (c) power and political institutions.
 - (d) religious institutions.
 - (e) educational institutions.
- 4. Social stratification.
- 5. Social control, order and stability.
- 6. Coersion, conflict and change.
- 7. Sociology as a critique of society.
- Law and Society, Sociology of Law, Sociology of legal profession.

PART-B: SOCIOLOGY OF INDIA

- 1. The development of Indian Society
 - (a) Unity and diversity.
 - (b) continuity and change.
- 2. India as a plural Society: varieties of-
 - (a) customs and ways of life.
 - (b) linguistic, religious and other communities.
- 3. Major institutions of Indian Society
 - (a) family
 - (b) caste
 - (c) village.
- 4. Tribe and caste in the traditional order.
- 5. Caste and class in contemporary India.
- 6. The backward classes.
- 7. Trends of change in Indian Society,
- 8. Indian Cultural Values and Development,

RECOMMENDED SOURCE MATERIALS

- T.B. Bottomore, Sociology, A Guide to Problems and Literature, London: Allen and Unwin, 1962.
 - Peter Worsley et al. Introducing Sociology, Harmondsworth: Penguin Books, 1970.
 - M. Haralambos, Sociology, Themes and Petspectives, Delhi: Oxford University Press, 1981.
 - N.K. Bose, The Structure of Hindu Society, New Delhi: Orient Longman, 1975.
 - David G. Mandelmaum, Society in India, Bombay: Popular Prakashan, 1972.
 - Romesh Thapper (ed), Tribe, Caste and Religion in India, New Delhi: Macmillan, 1977.
 - Andre Beteille, Inequality and Social Change, Delhi: Oxford University Press, 1972.
 - Andre Beteille, The Backward Classes and the New Social Order, Delhi: Oxford University Press, 1981.

APPENDIX-F

6. LEGAL LANGUAGE INCLUDING LEGAL WRITING

It is said that Law has its own language though for communication it uses a medium understood by the people. The medium adopted so far has been English and, to a large extent, legislation and administration of justice continue to be through English. However, in some States the local language is slowly but steadily replacing English in legislation as well as in administration of justice in lower Courts. This is as it should be.

The present situation therefore demands competence from the Lawyer for using English as well as the local language for transacting legal business. In appellate Courts proficiency in English is very essential perhaps for quite some time to come.

The policy of the Bar Council of India in respect of medium of instruction reflects the above situation. The new scheme of Legal Education under 10+2-5 also consequently udopts a curriculum which develops in every prospective Lawyer proficiency in English as well as in the regional language for purposes of effective legal practice. It is with this end in view the Council has introduced a separate Course on Legal Language including Legal Writing independent of English. It is expected that in this course, proficiency in Hindi or other 1 sional medium adopted for Legal Education will be imported so that the person when enrolled will be competent to use that medium for his professional work. Admittedly mere knowledge of Hindi or other regional language is insufficient to transact legal business in that language. Therefore this Course on Legal Language and Legal Writing will include instruction to use the regional medium for developing proficiency with 1 view to transact legal work through that language.

It is not desirable nor possible to structure a uniform syllabus in this Course. It is up to the University which uses a medium other than English for Legal Education to evolve the syllabus for the course keeping in mind the objects spelt out above.

It is recommended that this course on Legal Language and Legal Writing may be offered in the regional language or in Hindi.

APPLNDIX-G

7. HISTORY OF COURTS, LEGISLATURES AND LEGAL PROFESSION IN INDIA

1. Courts

- Administration of Justice in the Presidency Towns (1600-1773) and the development of Courts and judicial institutions under the East India Company.
- 2. Warren Hustings Plan of 1772 and the Adalat system of Courts—Reforms made under the Plan of ---1774 and re-organisation in 1780.
- Regulating Act of 1773—Supreme Court at Calcutta

 —its composition, power and functions—Failure of
 the Court—Act of 1781—Supreme Court vis-a-vis
 Mofussil Courts,
- 4. Judicial measures of Cornwallis 1787, 1790, 1793 progress of Adalet System under Sir John Shore.
- 5. Conflicts arising out of the dual judicial system— 'Iendency for amalgamation of the two system of Courts—The Indian High Courts Act, 1911—The Government of India Act, 1915—High Courts under the Government of India, Act, 1935—High Courts under the Indian Constitution.
- Development of Rule of Law, Separation of Powers, Independence of Judiciary.
- 7. Judicial Committee of Privy Council as a Court of Appeal and its jurisdiction to hear appeals from Indian decisions—Abolition of the jurisdiction of the Privy Council to hear appeals from Indian decisions.
- 8. Court system generally under the Constitution of India.

2 Legislature

- Legislative authority of the East India Company under the Charter of Queen Elizabeth, 1601.
- Changes under Regulating Act, 1773—Act of 1781, Recognition of the powers of the Governor and Council to make Regulations by the British Parliament.
- Act of 1813 and the extension of the legislative power conferred on all the three councils and subjection of the same to greater control.
- Act of 1833—Establishment of a Legislature of an All-India Character in 1834.
- The Indian Councils Act, 1861, Central Legislative Council and its composition, powers and functions; power conferred on the Governor.
- 6. Government of India Act of 1909—Government of India Act, 1919—Setting up of bicamera system of legislature at the centre in place of the Imperial Council consisting of one House.
- Government of India Act, 1935—the Federal Assembly and the Council of States, its composition, powers and functions—Legislative Assemblies in the provinces and the powers and functions of the same.
- Legislative Councils in the provinces, powers and functions of the same.
- 9. Law Reform and the Law Commissions.

3 Legal Profession

- Legal Profession in Pre-British India—Role, Training and Functions.
- 2 Law Practitioners in the Mayor's Courts established under the Charter of 1726.

- Organisation of Legal Profession under the Charter of 1774;
- 4. Legal Profession in Company & Courts.
- Provision for empliment of Advocates, Vakils and Attorneys under Legal Practitioner's Act, 1853.
- High Courts under the Act of 1861 and provision for the enrolment of the advocates, under the Tetters Patent issued
- Legal Practitioners Act, 1879—Report of the Indian Bar Committee, 1923.
- 8. The Indian Bar Councils Act, 1926—The All India Bar Committee, 1951.
- 9. The Advocates Act, 1961.
- 10. Development of legal education.
- 11. History of I aw Reporting in India.

RECOMMENDED SOURCE MATERIALS

- Herbert Cowell. The History and Constitution of the Courts and Legislative Authorities in India—6th Ed Rev. S. C. Bagchi, Calcutta, Macker, Spink, 1936
- Sir Courtenay Ilbert 'The Government of India, 2nd Fd. London, OUP 1907.
- 3. M.P. Jain—Outline of Indian Legal History. Dhan-wantra Mechanical and Yaw Book House, Delhi.
- A.B. Keith—A Constitutional History of India, 1600-1935, 2nd Fd. Allahabad, Central Book Depot. 1961.
- 5 Gwyer and Appudorai—Speeches and Documents on the Indian Constitution 1935—1947 (2 Vols), London, OUP, 1957.
- M. V. Pylee—Constitutional History of India (1600— 1950 Rombay, Asia 1967

APPENDIX-H

8. PRACTICAL TRAINING

(The Practical Training Course in the final year shall comprise of 4 papers carrying 400 marks)

This training shall comprise of course designed to develop legal skills and craftmanship, namely:--

- (a) Legal Method
- (b) Legal Research
- (c) Conveyancing
- (d) Pleadings
- (e) Moot Courts
- (f) Professional Ethics
- (g) Legal Aid Clinic
- (h) Court Visits.

(a) Legal Method :-

A student should be taught how and where to find the law. He should in particular be made familiar with the technique of analysing fact situations locating relevant provision of the law and applying them. The course should include reading of cases, their analysis and finding out ratio decidendi. Rules for interpretation of statutes have conveniently be included in this course

(b) Legal Research

This comes should provide the student with the skills necessary to identify problems, design project proposals, evolve methodologies, analyse data and write research reports on small tonics. Comparison of I gal methods with social science research methods may be made and the student be enabled to become critical consumrs of social and natural sciences data.

(c) Conveyancing:-

(i) Sale Deed, (ii) Mortgage Deed, (iii) Lease Deed, (iv) Gift Deed, (v) Promissory Note. (vi) Power of Attorney, (vii) Will.

General principles of drafting and relevant substantive rules shall be taught and a regular record of work done shall be insisted upon.

(d) Pleadings . --

- (1) Civil: (i) Plaint (ii) Written Statement (iii) Interlocutory Application (iv) Original Petition (v) Affidavit (vi) Execution Petition and (vi) Memorandum of Appeal and Revision (viii) Petition under Article 226 and 32 of the Constitution of India.
- (2) Cririnal: (i) Complaints (ii) Criminal Miscellaneous Petition, (iii) Bail Application and (iv) Memorandum of Appeal and Revision.

(e) Moot Courts:--

For the purpose of Moot Courts, groups shall be formed and cases involving several issues be assigned to each group. The Moot Courts will aim at imparting practical training in Court practice i.e. preparation of a brief and actual argument of the point involved. The cooperation of Courts advocates may be sought specially in the matter of getting copies or the paper books of cases which have been decided by various courts.

The course shall emphasise points of court-draft and decorum.

Attendance at such moot courts shall be compulsory. Fach student shall be required to maintain a regular record of his preparation for the moots.

(f) Professional Ethics:

Senior members of the Bur may be invited to give a course of six to ten lectures on Professional Fthics. Special attention may be devoted to the Bur Council of India norms and its application in specific situations

The rules regarding attendance should be strictly enforced in these courses and appropriate marks be allocated for examining the students' proficiency. Evaluation may be made either on the basis of written examinations or on the basis of day-to-day work as recorded in a practical record book or vivalues examination or any one or more of these techniques of evaluation. Passing in these examinations of tests shall be an essential pre-requisite for the award of the LLB Degree.

(a) Legal Ald Clinic:

It is desirable for every professional college of I aw to have a Legal Aid Clinic by proposed by the Legal Aid Implementation Committee. The model scheme recommended by the Committee may be adopted for the purpose Student participation in Legal aid and para-legal services may be carefully evaluated and due credit given.

In College whe e no Legal Clinics are functioning students may be involved in the work of the Local Legal Aid Committee under appropriately designed programmes.

(h) Court Visits

Visits—to Chambers of Senior Lawyers and I'aw Officers (including Prisons, Police Stations, Stock Exchanges, Legal Aid Camps, Tribunals etc.) and Courts constitute an important aspect of Practical Training. To be meaningful they have to be organised for a continuous neriod sufficiently long to observe and understand the processes taking place in their proper context. The programme can be intellectually stimulating and professionally challenging if properly organised and integrated with the curriculum.

Note:

The specific organisation of the Practical Training programme which shall include the above courses extending to a period of six months and covering not less than four papers of 100 marks each depends on the Lew School concerned. It is however expected that being a professional programme the law education should adequately reflect the minimum clinical content as spelt out in the preceding paragraphs. There is need for separate record books being maintained by students on each of the Practical Training Courses and teachers with necessary experience assigned to handle the Courses Besides giving practical skills to the

students, the programme will help the Law School to enrich its curricular content and community relations

The Faculty in each University will note the introduction of a variety of optional Courses like 'Law and Poverty', I uw and Rural Development' etc. in the new curriculum which envivage a practical component in their teaching and will take necessary steps for integrating practical training appropriately with the theoretical courses.

Secretary,

THE BAR COUNCIL OF INDIA, AB-21, MATHURA ROAD, FACING SUPREME COURT BLOCK, NEW DELHI-7

The Rules of the Bar Council of India in Part IV have been amended as set out in the following Resolutions:—

I. RESOLUTION NO. 83/1982

RESOLUTION that the rule 2 in Part IV be amended by adding the words "or within such distance thereof as the Bar Council of Irdia Permits" after the words "circuit District Court" occurring at the end of Rule 2.

RESOLVED FURTHER that the rule after amendment shall rend as follows:—

"A Law College shall only be located at a place where there is a District Court or a Circuit District Court or within such distance thereof as the Bar Council of India permits."

RESOLVED FURTHER that it may be made clear that the Rule is intended to have prospective operation only.

II. RESOLUTION NO. 84/1982

RESOLVED that Political Science should be of 3 papers (Political Science, I, Political Science II and Political Science III). The rule should therefore be suitably amended to Prescribe 7 compulsory subjects spread out into ten compulsory papers in the pre-law course as follows:—

1.	General	Engilish	(Graduate	Standard)	2 papers	
	General	Engilish	Part I and	Part II		

2. Political Science (Political Science)

2. Political Science (Political Science)	
Part I, Part II and Part III)	3 papers
3. Economics	1 paper
4. History	1 paper
5. Sociology	1 paper
6. Legal I anguage including legal writing	1 paper
7. History of Courts, Legislatures and Legal	
Profession in India	1 paper

SHYAM MOHAN SRIVASTAVA SECRETARY BAR COUNCIL OF INDIA

THE FOOD CORPORATION OF INDIA

New Delhi, the 22nd January 1983

No. 22/F. No 6-1/76-IC Vol. IV.—In exercise of the Powers conferred by Section 45 of the Food Corporation Act, 1964, (37 of 1964) and with the previous sanction of the Central Government, the Food Corporation of India hereby makes the following Regulation to amend the Food Corporation of India (Staff) Regulations, 1971, namely:—

- (i) These regulations shall be called the Food Corporation of India (Staff) (85th amendment) Regulations, 1982.
 - (ii) They shall be deemed to have come into force on the 1st of November, 1977.
- 2 (1) The following new regulation 29-A shall be inserted below the existing regulation 29 of the Food Corporation of India (Staff) Regulations 1971:—

29-A ENCASHMENT OF EARNED LEAVE WHILE IN SERVICE:

Encashment of Earned leave shall be allowed to the regular employees (including Food Transferees) of

- the Corporation once in a Calendar year in accordance with the terms and conditions laid down in Appendix-5. For the purpose of this Regulation, the expression "carned leave" shall not include the unarraled portion of joining time credited to the leave account as carned leave under Regulation 30."
- (ii) A new appendix-5 shall be added after the existing appendix-4 in the Food Corporation of India (Staff) Regulations, 1971 as follows:---

Appendix-5

Terms and conditions governing the encashment of earned leave by the regular employees of the Corporation while in tervice (Ref. Regulation 29(a)

A'll regular employees (including Food transferees) of the Corporation may be allowed to encash earned leave to the extent indicated below only once in a calendar year by the authorities competent to sanction earned leave.

- 2. Encashment of Earned Leave is not permissible to the following classes of employees:—
 - (i) Employees working on daily wages/contract basis;
 - (ii) Deputationists from Central Government/State Government/other Public Undertakings, working in the Corporation;
 - (iii) Trainces/Apprentices; and
 - (iv) Employees under suspension.
- 3. Encashment will not be permissible unless the employee has at least 45 days Earned Leave to his credit on the date of application.
- 4. The maximum number of days of encashable Farned Leave at a time will be half of the Farned Leave at the credit of an employee on the date of application reduced by one year's Farned Leave entitlement. In other words if 'X' represents the balance of Farned Leave at credit on the date of application and 'Y' represents one year's Earned Leave entitlement, then, the maximum Earned Leave that can be encashed will be equal to (X+Y)

(Note:—The unavailed portion of joining time credited to the leave account will not be encashed)

- 5. The amount of encashment for the Earned Leave (sanctioned to be meashed) shall be worked out on the basis of the emoluments admissible on the date preceding the date of the application. Fmoluments shall mean and include the following:—
 - (i) Basic pay.
 - (ii) Special pay.
 - (iii) Personal pay.
 - (iv) Dearness Allowance including Additional Dearness Allowance.
- 6 Fmoluments shall not include charge Allowance/Deployment Allowance for this purpose.
- 7. The amount of encashment shall be worked out treatment its month as of 30 days.
- 8. Farned Leave at credit will not be encached if an employee posigns from service or is dismissed removed from project or compulsorily retired or his services terminated otherwise under the Food Corpo ation of India (Staff) Regulations.
- 9 If any doubt arise requiling the interpretation of these terms and conditions, the decision of the Managine Director shall be final

EXPLANATORY MEMORANDUM

The scheme for encyclment of carned leave once in a calendar very fluring the service was introduced in the Corner flor west 1. November 1977 vide circular No. 6-1/76-IC dated 13-12.77 with the approval of the Board of Directors in its 113th meeting held on 28th & 29th November, 1977.

the crior commence of the Burne of Public Enterprine under Mountry or Empire in Delid, was also obtained.

- 2. According to the scheme, half of the eatned leave at credit of an employee on the date of application iduced by one year's entitlement to be retained at the credit of the employee, can be encashed once in a calendar year.
- 3. The applicability of the above scheme, introduced as a measure of rringe benefit to the employees of the Corporation transferred to the Corporation from the Regional Directorates of the Food under the provision of Section 12A of the Lood Corporations Act, 1964 and who opted to be governed by the leave, Provident Fund, and other retirement benefits of the Central Government as applicable to Central Government employees, was objected to by the Government audit. The scheme has been reviewed in the light of audit observations and Legal advice and it has been decided that the benefit of "incashment of carned leave while in service" should not be allowed as a matter of fringe benefit but the scheme should be incorporated in the FCI (Staff) Regulation. 1971, retrospectively, since it involved 'condition of service'.
- 4. It is found not feasible to give effect to the scheme from the date of publication of the notification, amending the relevant Regulation (29-A) of the Food Corporation of India (Staff) Regulations, 1971, in the Gazette of India but the scheme needs to be implemented with retrospective effect because there will be innumerable difficulties including industrial problems apart from administrative problems involved in the recovery of the payments already made as some employees have paid income-tax on the amounts received by them against encashment of earned leave, between 1977 and 1982, and some employees have retired, resigned or died.
- 5. In order to regulatise the payments already made on account of leave encashment during the period from 1-11-77 onwards, the scheme being incorporated in the Staff Regulations as Regulation 29 A shall take retrospective effect w.e.f. 1-11-77.

R. NARAYANASWAMY, Secretary

UNIT TRUST OF INDIA

Bombay, the 1st February 1983

No. UT./10517/DPD(P&R)77/82-83.—The provisions of the Monthly Income Unit Scheme 1983 formulated under Section 21 of the Unit Trust of India Act, 1963 are published here below for general information.

THE MONTHLY INCOME UNIT SCHEME, 1983

In exercise of the powers conferred by Section 21 of the Unit Trust of India Act, 1963 (52 of 1963), the Board of the Unit Trust of India hereby makes the following unit scheme.

I. Short Thle and Commencement:

- (1) This Scheme shall be called the Monthly Income Unit Scheme, 1983.
- (2) It shall come into force on the 1st day of Maich 1983.
- (3) Units will be on sale only during such period and for such duration as the Board of Trustees of the Unit Trust of India may from time to time decide. Provided, that the Chairman or Executive Trustee may suspend the sale of units under the scheme totally at any time after the commencement of the scheme by giving a week's notice in such newspapers as may be decided.

W. Definitions

- In this Scheme, unless the context otherwise requires :-
 - (a) the "Act" means the Unit Trust of India Act, 1963;
 - (b) "acceptance date" with reference to an application made by an applicant to the Trust for sale or repurchase of units by the Trust means the day on which the Trust, after being satisfied that such application is in order, accepts the same;

- (c) "Applicant": For the purpose of this scheme an inpricant shall in hide the alternate applicant mentioned in the application form when units are sold for the benefit of a mentally handicapped individual
- (d) "clderly person' means any individual who, on the date of application has completed 55 years of age;
- (e) "cligible in titution" means a Charitable or Religious Trust or Endowment which is administered or controlled or supervised by or under the provisions of any Central or State Enactment, which is for the time being in force or a Society registered under the Societies Registration Act, 1860 engaged, as one of its activities in furthering or protecting the welfare and advancement of interest of handicapped persons, elderly persons or widows.
- (f) "handicapped person" means '
 - (i) any individual who suffers from any physical disability of such a nature which prevents him from carrying out normal activities of life without some device or assistance either of a mechanical or manual nature or otherwise and who is so certified by any Registered Medical Practitioner; or
 - (ii) any individual who suffers from mental disability of such a nature which prevents him from carrying out normal activities of life and is so certified by any Registered Medical Practitioner.

Illustration:

Illustration of such physical handicaps would include partial or total blindness, and/or deafness, dumbness or loss of any limb.

- (g) "number of units deemed to be in issue" means the aggregate of the number of units sold and remaining outstanding;
- (h) "person" shall include an eligible institution as defined above.
- (i) "recognised stock exchange" means a stock exchange, which is, for the time being recognised under the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956):
- (j) "regulations" means Unit Trust of India General Regulations, 1964 made under Section 43(1) of the
- (k) "unit" means one undivided share of the face value of Rupees one hundred in the unit capital;
- "unit-holder" used as an expression for the purpose of this scheme shall mean and include the applicant where appropriate.
- (m) 'widow' means any lady who on the date of the applict'on, has lost her husband and who has not married again.
 - (n) all other expressions not defined herein but defined in the Act shall have the respective meanings assigned to them by the Act.

III. Face value of each unit:

The face value of each unit shall be one hundred supees. IV. Application for units:

- (1) Applications for units may be made by:-
 - (a) an individual who is an elderly person or a physically handicapped person or a widow as defined under the scheme;
 - (b) a parent, step parent or other lawful guardian on behalf of a minor who is a mentally handicapped person:
 - (c) an eligible institution as defined under the scheme;
 - (d) a parent/step parent or other lawful guardian on hehalf of a minor who is a physically handicapped person or an individual for the benefit of another individual who is a mentally handicapped person.
- (2) Application shall be made in such form as may be approved by the Chairman of the Trust.
- (3) Application shall be made for multiples of 10 units subject to a minimum of 50 units and a maximum of

1000 units Provided that in the case of an application by an eligible institution the maximum shall be 5000 units

(4) No person shall apply for units under more than one application. In case a person makes multiple applications the Trust shall in its sole discretion, accept only one of the applications which is for the highest number of units subject to the maximum and in the event of all the applications being for the same amounts one of the applications thereof the rest of the applications being rejected. Further, if at any time during the currency of the scheme, the Trust becomes aware that a person is either holding more than one unit certificate (originally issued in his name) under the schape the unit-holder will be allowed to hold only one unit certificate (the one for the highest number of units) and the rest of the unit certificates being repurchased by it at the face value. No interest/Income Distribution will be paid for the excess amount/s invested in units. If any Income Distribution has been wrongly paid in respect of such units, the Trust shall deduct the Income Distribution so paid to the unit-holder from the repurchase value of units.

Explanation

Any applicant who falls within one or more of the elig bility criteria defined under the Scheme may make only application and multiple applications when detected shall be dealt with in the manner stated above

- (5) (1) The payment for the units applied for by an applicant shall be made by him along with the application in cash cheque or draft. Cheques or drafts should be drawn on branches of banks within the city where the office at which the application is tendered is situated.
 - (ii) If the payment is made by cheque the acceptance date will, subject to such cheque being realised be the date on which the cheque is received by the Trust or by a designated branch of authorised bank. If payment is made by draft the acceptance date will subject to such draft provided the application is received by the Trust or a designated branch of authorised bank within such time as may be deemed reasonable by the Trust. If the amount tendered by way of payment for the units applied for is not sufficient to cover the amount payable for the units applied for, the applicant shall be issued such lower number of units as could be issued under the scheme the balance due to him shall be refundacid at his cost in such manner as the Trust may deem fit.
 - (11) A unit certificate will be sent by registered post/ recorded delivery with or to the address given by I will not incure by hability for loss, damage misdelivery or no dddivery of the unit certificate, so sent
 - (iv) A unit cert ficite issued by the Trust to the eligible institution shall be made out in the name of the eligible institution
- (6) Right of Trust to ere nt or reject application

The Trust shill have the right at its sole discretion to accept ind/or i act application for issue of units under the schem. Any decision of the Trust about the climbility or otherwise of a person to make an application unit in the scheme shall be final.

(7) Applicated and to comply with requirements wicer the scheme before being issued units,

Persons applying for units under the scheme shall be bound to satisfy the Trust about their eligibility to make an application and comply with all requirements of the Trust. The compliance or otherwise to the sit sfaction of the Trust of such requirements shall be it the sole discretion of the Trust.

(8) A person who holds units under a false declaration shall be lable to have the unit certificate cancelled and the name deleted from the register of unit-hole.

ders The Trust shall have the right in such an event to repurchase the units at par and recover the Income Distribution wrongly paid from out of the repurchase proceeds and return and balance. The amount shall not carry any interest irrespective of the period it takes the Frust to effect the repurchase and to i mit the repurchase proceeds to the applicant.

V Sale of units

The contract for sale of unus by the Trust shall be deemed to have been concluded on the acceptance date. On such conclusion of the contract for sale the Trust shall, as soon thereafter as possible, issue to the applicant one unit certificate representing the units sold to him

VI Repurchase of units

- (1) The Trust shall not repurchase units before 1st July, 1986
- (2) The Trust shall during the currency of the Scheme on and after 1st July 1986 repurchase at par on receipt by it of the unit certificate/s with the form on the reverse thereof duly filled in provided all the units comprised in the certificate/s are tendered for repurchase. No partial repurchase of units represented by the unit certificate/s shall be permitted. The unit holder while making an application for repurchase shall be bound to surrender all the unpaid Income Distribution warrants remaining outstanding upto and inclusive of the month of repurchase to the Trust. The Trust shall not on accepting the unit certificate for repurchase be bound to pay any Income Distribution on the units for the future months nor shall any interest be payable on the repurchase proceeds. The certificate and the unpaid Income Distribution Warrants if any received shall be retained by the Trust for cancellation.
- (3) Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-clauses the Trust shall be at liberty while repurchasing the units in the event of the failure of the unit holder to surrender the Income Distribution Warrants which a a then outstanding the deduct from the repurchase price such amount representing the amount of the Income Distribution warrant payable in future as have not been surrendered and pay the balance to the unitholder. On the acceptance of the unit certificate/s by the Trust the unitholders right to receive future Income Distribution including the Income Distribution for the month of acceptance will cease and the Trust shall have a claim on the amount/s represented by such outstanding Income Distributions
- (4) A unitholder to be entitled to a full years Income Distribution paid out on a monthly basis should have held the units for a full year. A unitholder who holds the units for a part of the year shall be entitled to receive proportionate Income Distribution for the period of holding which shall always be full English Calendar months of holding part of a month of what ever length being always ignored
- (5) In the event of the death of the unitholder and on surender to the Trist by the legal representative or nom nee of the relative unit certificate and the unpaid Income Distribution Warrants outstanding to the deceased unit holder for the period prior to his death the Trust shall on compliance with the formalities in connection with the recognition of claim repurchase the units at par and pay the outstanding proport onate Income Distribution
 - (6) Payment for units repurchased by the Trust after the deductions if any shall be made as early as possible after the acceptance date in such manner as the applicant may indicate in the application. No interest shall on any account be payable on the amount due to the applicant and the cost of remittance (including post ge) or of realisation of cheque or draft sent by the Trust shall be borne by the applicant

VII Restrictions on sale and repurchese of un

Notwithstanding anything contained in any provision of the scheme the Trust shall not be under an obligation to repurchase units—

(1) on such days as are not working days and

(ii) during the period when the register of unit holders is closed in connection with (as notified by the Trust) the annual closing of the books and accounts.

Lxplanation:

For the purposes of this scheme the term "working day" shall mean a day which has not ben either (1) notified under the Negotiable Instruments Act, 188, to be a public holiday in the State of Maharashtra or such other states where the Trust has its offices; or (ii) notified by the Trust in the Gazette of India as a day on which the office of the Trust will be closed.

VII. Sale and Repurchase prices:

- (1) The sale ond repurchase price of units during the period when units are sold and repurchased shall be at par.
- (2) In the event of a termination of the Scheme in the manner as specified in Clause XXV hereof the Trust shall determine the repurchase price by valuing the assets pertaining to the scheme as at the close of business on the date notified for termination reduced by the liability pertaining to the scheme and dividing them by the number of units outstanding and deducting therefrom such sum as in the opinion of the Trust is adequate to cover brokerage commission, taxes, if any, stamp duties and other charges in relation to realisation of investments by the Trust and other adjustments and the expenditure in connection with the closure and payment of the distribution to the unitholders of the assets in respect of the scheme. In such an event the repurchase prices shall in addition to the par value bear the other distributable component of the asset per unit arrived at by the Trust in a maner satisfactory to its auditors and as the Board may approve.

IX. Publication of final repurchase price:

Upon termination of the scheme in the manner provided in clause XXV hereof the Trust shall as early as possible after determining the repurchase price publish it in such manner as it may deem fit.

X. Valuation of assets pertaining to this scheme:

- (1) For the purposes of valuation of the assets under subclause (2) of clause VIII the assets shall be classified into; (a) cash (b) investments and (c) other assets.
- (2) Investments shall be valued by taking:
 - A. (a) the closing prices on the stock exchange as on the working day on which the valuation is made of the securities held by the Trust pertaining to this Scheme: Provided where security is quoted on more than one stock exchange, the manner of determining the price of such security shall be decided by the Trust.
 - (b) where any investment was not, during the relevant period, dealt in, or quoted or any recognised stock exchange, such value, as the Trust may, in the circumstances consider to be the fair value of such investment; and

B. adding thereto-

- (a) in the case of interest earning deposits, interest accrued but not received;
- (b) in the case of Government Securities and debentures, interest accrued but not received;
- (c) in the case of preference shares and equity shares quoted ex-dividend and dividend declared but not received.
- (3) Other assets shall be valued at their book value.

XI. Form of unit certificate:

Unit Certificates shall be in Form A annexed hereto. Each unit certificate shall bear a distinctive number, the number of units represented by the certificate and the name of the unit-holder.

XII. Manner of preparation of unit certificate:

The unit certificates may be engraved or lithographed or printed as the Board of Trustee may, from time to time, determine and shall be signed on behalf of the Trust by two persons duly authorised by the Trust. Every such signature may either be autographic or may be effected by a mechanical method. No unit certificate shall be valid unless and until it is so signed. Unit certificates so signed shall be valid and binding notwithstanding that, before the issue thereof, any person whose signature appears thereon, may have ceased to be a person authorised to sign unit certificates on behalf of the Trust. Provided that should the unit certificate so prepared contain the signature of an authorised person who however is dead at the time of issue of the certificate, the Trust may by a method considered by it as most suitable, cancel the signature of such a person appearing on the certificate and have the signature of any other authorised person affixed to it. The unit certificate so issued shall also be valid.

XIII. Trusts not to be recognized regarding unit certificates:

- (1) The person who is registered as the holder and in whose name a unit certificate has been issued shall be the only person to be recognized by the Trust as the unitholder and as having any right, title or interest in or to such unit certificate and the units which it represents; and the Trust may recognize such unitholder as absolute owner thereof and shall not be bound by any notice to the contrary or to take notice of the execution of any trust or, save as herein expressly provided or as by some court of competent jurisdiction ordered, to recognize any trust or equity or other interest effecting the title to any unit certificate or the units thereby represented.
- (2) Where an application is made by an individual for the benefit of another individual who is mentally haudicapped and accepted by the Trust, the Trust shall not be deemed to be taking notice of any trust. The Trust shall deal, for all purposes, under the Scheme with the applicant or the persons mentioned as alternate applicant in the application form in the event of the applicant's death.

XIV. Exchange of unit certificates and procedure when certificate is mutilated, defaced, lost, etc.:

- (1) In case any unit certificate shall be mutilitated or worn out or defaced, the Trust in its discretion, may issue to the person entitled a new unit certificate representing the same aggregate number of units as the mutilitated or worn out or defaced unit certificate. In case any unit certificate should be lost, stolen or destroyed, the Trust may, in its discretion, issue to the person entitled a new unit certificate in lieu thereof. No such new unit certificate shall be issued unless the applicant shall previously have
 - furnished to the Trust evidence satisfactory to it of the mutilation, wearing out, defacement, loss, theft or destruction of the original unit certificate;
 - (ii) paid all expenses in connection with the investigation of the facts;
 - (iii) (in case of mutilation or wearing out or defacement) produced and surrendered to the Trust the mutilated or worn out or defaced unit certificates; and
 - (iv) furnished to the Trust such indemnity as it may require.

The Trust shall not incur any liability for issuing such certificate in good faith under the provisions of this clause.

(2) Before issuing any certificate under the provisions of this clause, the Trust may require the applicant for the unit certificate its to pay a free of Rupees two per unit certificate issued by it together with a sum sufficient in the opinion of the Trust to cover stamp duty, if any, or other charges or taxes including postal registration charges that may be payable in connection with the issue and despatch of such certificate.

XV. Register of unltholders:

The following provisions shall have effect with regard to the registration of unitholders—

- (1) Λ register of the unitholder shall be kept by the Trust at its Head Office and there shall be entered in the register,
 - (a) the names and addresses of the unitholders;
 - (b) the distinctive number of the unit certificate and the number of units held by every such person; and
 - (c) the date on which such person become the holder of the units standing in his name.
- (2) Any change of name or address on the part of any unitholder shall be notified to the Trust, which, on being satisfied of such change and on compliance with such formalities as it may require, shall after the register accordingly. Any change pursuant to acath of an applicant who has applied for units for the benefit of another individual who is a mentally handicapped person shall be entered in the register accordingly.
- (3) Except when the register is closed in accordance with the provisions in that behalf heremafter contained, the register shall during business hours (subject to such reasonable restrictions as the Trust may impose but so that not less than two hours on each business day shall be allowed for inspection) be open to inspection by any unitholder without charge.
- (4) The register will be closed at such times and for such periods as the Trust may from time to time determine provided that it shall not be closed for more than 60 days in any one year; the Trust shall give notice of such closure by advertisement in such newspapers as the Board may direct.
- (5) No notice of any trust express, implied or constructive shall be entered on the register in respect of any unit.
- XVI. Application by and registration of eligible institutions, minor, an Applicant for the benefit of a mentally handicapped person:
- (1) An eligible institution may be registered as a unit-holder.
- (2) An adult, being a parent, step-parent or, other lawful guardian of a minor (who is u physically/mentally handscapped person) may hold units and deal with them in accordance with and to the extent provided, in sub-section (2A) of Section 2I of the Act. Such adult if so required shall furnish to the Trust, in such manner as may be specified, proof of the age of the minor and the cupacity to hold and deal with units on behalf of the minor. The Trust shall be entitled to act on the statements made by such adult in the application form without any further proof.
- (3) Where an application is made by an individual for the benefit of another individual who is a mentally handicapped person, the Trust shall act on the statement and certificates furnished and in doing so the Trust shall be deemed to be acting in good faith. The Trust shall be entitled to deal only with the applicant and in the event of his death, the alternate applicant for all practical purposes and any payment in respect of the units by the Trust to the said applicant or the alternate applicant shall be a good discharge to the Trust.
- (4) Applications by eligible institutions shall be accompanied by the relevant documents showing the applicants' competence to invest in units such as Memorandum and Articles, Byc-laws etc. an authorised copy of the resolution by the managing body, and a copy of the requisite power of attorney.
- (5) A firm or other association of persons (not being incorporated) as such, shall not be registered as a unitholder.

XVIII. Nomination by unitholders and agents:

The receipt of the unitholder for any moneys paid to him in respect of the units represented by the certificate shall be a good discharge to the Trust.

XVIII. Nomination by unitholder and agenty;

- (1) Unitholder viz.
 - (i) elderly persons
 - (ii) widows
 - (iii) physically handicapped persons as defined under the scheme may exercise the right to make or cancel a nomination to the extent provided in the Regulations.

(2) A unitholder withe masting a honomorous of the ordesness may nonmaste more that one more that one more than nonmines, off in no case executing 3 individuals and small specify the number of units in respect of which he wished to make each of them a benencary. In the absence of such mention the nominees shall be utility discharged in recognising the craim of the nonminess, in the event of the death of the unitholder, to the eventsion of all others subject to the provisions in the Regulations.

_ _ = -

(3) Unaffolders viz. a parent/lawful guardian on behalt or a minor, an eligible institution, an applicant who has applied for units for the benefit of another malvidual who is a mentally hand(capped person shall have no right to make any nomination.

Alis. Transfer of unus .

No transfer of units issued under this Scheme shall be termissible.

.... Death or bankruptcy of a unitholder.

- (1) in the event of death of a unitholder, the nominee, shall be the person/s recognised by the flust as the person/s entitled to the amount payable by the flust in respect of units under the Regulations.
- (2) In the absence of a valid nonmation by a unitholder, the executor or administrators of the deceased unitholder or a holder of succession certificate issued under Part X of the Indian Succession Act, 1925 (39 of 1925) shall be the only persons who may be recognised by the Trust as having any title to the unit.
- (3) Any person becoming entitled to the units consequent upon the death or bankruptcy of a unitholder may, upon producing such evidence as to his title as the flust trust snall consider sufficient, be paid the repurchase value of all units to the credit of the deceased at par after all the formalities in connection with the claim have been complied with by the claimant.
 - (4) In the event of the sole nominee under the unit certificate being a person eligible to hold units then at desire of the said nominee, the nominee may instead of receiving the repurchase value of all units to the ciedit of the deceased shall be permitted to hold the units as a unitholder and shall be issued a unit certificate in his name in respect of units so desired to be held subject to the conditions regarding minimum holdings.
 - (5) In the event of the death of the applicant who has applied for units for the benefit of a Mentally handicapped person, the Fiust shall deal with the alternate applicant as if he were the applicant. Further, in the event of the death of the applicant or the alternate applicant, as the case may be, the existing applicant shall appoint another individual as his alternate applicant.

XXI. Investment limits:

(1) Investments by the Trust from the funds of the scheme in the securities of any one company shall not exceed 15% of the securities issued and outstanding such companies.

Provided that the aggregate of such investments in the capital initially issued by new industrial undertakings shall not at any time exceed 5% of the total amount of the said funds.

(2) The limits prescribed under sub-clause (1) shall not apply to investments of the Trust in bonds and debentures and deposits of a company whether secured or not.

MXII. Income Distribution:

(1) The Income Distribution under the scheme which shall be at a rate of 12% per amount and made payable on a monthly basis shall be subject to revision by the Trust based upon the income of the scheme.

- (2) The Income Distribution for each month shall be made payable at the beginning of the following month and will be paid by the Trust under such pre-payment arrangements by means of Income Distribution warrants or any instrument encashable at par at the branches of such bank as the Trust may specify.
 - Such of those units as have been sold under an application accepted by the Trust on/or before the 15th day of the month shall alone be eligible for Income Distribution for that month.
- (3) Provided that the Income Distribution for the period ending 30th June, 1983 shall be forwarded to the unitholder along with the post dated Income Distribution Warrants for the full year July-June 1983-84.
- (4) Subject to the provisions of sub-clause (2), the warrants for payment of income distribution on a monthly basis will be sent to the unit holder once a year and the warrants will be so dated that the unitholder shall encash each one of the warrants on becoming mature for payment. Every warrant shall have validity for one month. The Trust shall not be bound to pay interest in the event of any of the warrants not reaching the unitholders before the expiry of the validity period or in the event of their becoming stale.
- (5) In the event of a repurchase which shall always be in full, the unitholder upon non-surrender of unpaid warrants shall be entitled to encash these warrants which are due for the subsequent months and remaining in the custody of the unitholders on the dates of maturity and the amount represented by such Income Distribution warrants shall be deducted from the repurchase proceeds.
- (6) In the event of the death of the unitholder if the sole nominee is eligible to hold units and desires to continue to hold the units then the sole nominee shall be bound to return all the unencashed warrants for the future months for necessary rectification. However, such a nominee desiring to continue to hold the units shall not be entitled to any interest or any compensation during the period it takes the Trust to rectify the warrants already issued in favour of the deceased unitholder to those in favour of the newly admitted unitholder.
- (7) In the event of the death of an applicant where the application is made by an individual for the benefit of another individual who is a mentally handicapped person, the alternate applicant shall be bound to retain all the unencushed Income Distribution warrants for future months for necessary rectification. However such alternate applicant shall not be entitled to any interest or/any compensation during the period it takes the Tuest to rectify the warrants already issued in favour of the deceased applicant to those in favour of the newly admitted applicant.
- (8) Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-clause, the Trust reserves its right to make the Income Distribution on a quarterly, half year or annual basis as the case may be, should the reasons of expediency cost, interest of unitholders and other circumstances make it necessary for the Trust to do so. In such an event the Trust shall notify the unitholders by a publication in two leading English language daily newspapers. No unitholder shall have a right to claim Income Distribution on monthly basis after the Trust makes a notification as above.

XXIII. Publication of Accounts:

The Trust shall as soon as may be after the 30th June of each year cause to be published in such manner as the Board may decide, accounts in the manner specified by the Board showing the working of the scheme during the period ending as of that date. The Trust shall on a request in writing received from a unitholder, furnish him a copy of the accounts so published.

XXIV Additions and Amendments to scheme:

The Board may from time to time add to or otherwise amend this scheme and any amendment addition thereof will be notified in the Official Gazette.

XXV. Termination of the scheme:

The Scheme shall stand terminated as of 1st July, 1988. All unitholders of the scheme as of that date shall be paid the repurchase price fixed for that date arrived at as nearly as practicable in the manner provided in Clause VIII (2) hereoff. Thereafter, no further benefit, whether by way of increase in the repurchase value or by way of Income Distribution for any period subsequent to 30th June 1988 shall accrue to them. The repurchase value will be paid by the Trust as early as possible after the unit certificate with the form on the reverse thereof duly completed has been received by it. The unit certificate shall be retained by the Trust for cancellation.

XXVI. Scheme to be binding on unitholders:

The terms of this scheme, including any amendments/additions thereto from time to time, shall be binding on each unitholder and every other person claiming through him as if he had expressly agreed that they should be so binding.

XXVII. Benefits to the unitholders.

All benefits accuring under the scheme in respect of capital and reserves and surpluses if any at the time of the closure of the scheme shall be available only to the unit-holders who hold the units for the full term of the scheme tall its closure.

XXVIII. Copy of Scheme to be made available:

A copy of this scheme incorporating all amendments thereto shall be made available for inspection at the offices of the Trust at all times during its business hours and may be supplied by the Trust to any person on application and payment of rupees five.

XXIX. Power to construe provisions:

Should any doubt arise as to the interpretation of any of the provisions, Chairman or in his absence the Executive Trustee shall have powers to construct the provisions of the scheme, in so far such construction is not in any manner prejudicial or contrary to the basic structure of the scheme and such decision shall be conclusive.

XXX. Relaxation/variation/modification of provisions:

The Chairman or in his absence the Executive Trustee of the Trust may in order to mitigate hardship or for smooth and easy operation of Scheme, relax vary or modify any of the provisions of the scheme in case of any unitholder or class of unitholders upon such conditions as may be deemed expedient.

FORM A EMBLEM

UNIT TRUST OF INDIA

(Incorporated under the Unit Trust of India Act, 1936)

MONTHLY INCOME UNIT SCHEME 1983

(CLAUSE XI)

UNIT CERTIFICATE NO.

NO. OF UNITS

This is to certify that the person/s named in this Certificate is/are the Registered Holder(s) of

Units, each of the face value of Rupces One Hundred, subject to the provisions of the Unit Trust of India Act, 1963 (52 of 63), the Regulations framed thereunder and the Monthly Income Unit Scheme 1983.

Name /s

for the Unit Trust of India

Chairman

Trustce

Date: NOT TRANSFERABLE

FORM OF APPLICATION FOR REPURCHASE OF ALL UNITS

Date:

n	-		
- 1		U	

Unit Trust of India,

offer to the Trust for repurchase at the repurchase price on the Acceptance date all units comprised in the certificate. I/We

The price of the units may be paid to me/us by* cash/ cheque/bank draft at my/our cost.

	Signature/s of holder(s)
2	
Signature of witness	• •
Name :	
Occupation:	
Address:	
	• •
	• •
	••
Signature of witness	
Name :	
Occupation:	
Address:	
A	cceptance Date

Delete words inapplicable.

R. SRINIVASAN Dy. General Manager (Planning & Development)

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE

THE CI-NTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE (GENERAL) REGULATIONS, 1976

In exercise of the powers conferred by clauses (b) to (g) of section 36 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970), the Central Council of Indian Medicine with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely :-

These regulations may be called the Central Council of Indian Medicine (General) Regulations, 1976.

2. Definitions

In these regulations, unless the context otherwise requires,

- (a) "Act" means the Indian Medicne Central Council Act, 1970 (48 of 1970);
- (b) "Employees" means persons employed by the Central Council under clause (b) of section 12 to carry out the purposes of the Act;
- (c) "Frecutive Committee" means a committee constituted by the Central Council under section 10 of the Act:
- (d) "Member" means a member elected under clause (a) or (b), or nominated under clause c), of sub-section (1) of section 3 of the Act;
- (e) "President" means the President of the Central Council appointed under clause (a) of section 12 of the
- (f) "Registrat" means the Registrar of the Central Councd appointed under clause (a) of section 12 of the Act, who shall also act as the Secretary of the Central Conneil;

- (g) "Standing and Ad-hoc committee" means different committees constituted by the Central Council for general or special purposes under section 10 of the
- (h) "Vice-President" means a Vice-President of the Central Council elected under sub-section (3) of section 3 of the Act.
- 3. Office of the Central Council

The Office of the Central Council shall be situated in Delhi.

PART I

POWERS AND DUTIES OF THE PRESIDENT AND VICE-PRESIDENTS

1. President

The President shall exercise such powers and perform such duties as may be assigned to him by or under the provisions of the Act and the rules and regulations made thereunder.

5. Vice-Presidents

- (1) The Vice-Presidents shall exercise such powers and perform such duties as may be assigned to him by or under the provisions of the Act and the rules and regulations made thereunder.
- (2) If the office of the President is vacant or if the President for any reason is unable to exercise the powers or discharge the functions of his office, the Vice-Presidents, in rotation, for one year at a time shall act in his place and shall exercise the powers and discharge the functions of the President.

The order of the rotation shall be as below:-

(a) Vice-President

—Ayurveda

(b) Vice-President

—Unani

(c) Vice-President

—Siddha.

PART II

6. Leccutive Committee

(1) To carry out the functions of the Central Council, when it is not in session, there shall be Fxecutive Committee consisting of the following, namely:

(i) President

Ex-officio Chalrman

(ii) Vice-President

for Ayurveda

Ex-officio

Vice-President (jii)

for Unani

Ex-officio

(iv) Vice-President

for Siddha

Ex-officio

(v) Member elected from amongst themselves, separately by members representing the three different systems of medicine, Ayurveda, Siddha and Unani on the following basis :-

Where the number of members does not exceed 15

Where the number of members exceeds 30 but does not exceed 30

Where the number of members exceeds 30 but does not exceed 45

Where the number of members exceeds 45

(2) The Registrar, Central Council, shall be the Secretary of the Executive Committee.

7. Functions of the Executive Committee

The Executive Committee shall have powers to discharge the functions of the Central Council within the framework of the Act and the rules and regulations made thereunder in accordance with the general policy and principles laid down by the Central Council.

8. When the matter is so urgent that its decision can not wait till the holding of the next meeting of the Executive Committee the same may be decided by circulation to all the members of the Executive Committee.

When the matter is so emergent that even reference to members of the I recutive Committee by circulation shall defeat ---

ats object, the President may exercise the powers of the Central Council.

Provided that in such cases, the action taken by the President shall be required to be ratified by the Executive Conmittee at its next meeting

- 9. All decisions taken by the Executive Committee shell be placed before the Central Council at its next meeting.
- 10. One-third of the total number of members of the Executive Committee shall form a quorum and all acts of the Committee shall be decided by a majority of the members present and voting
- 11. If at the time appointed for meeting, a quorum is not present, the meeting shall not commence until a quorum is present and if a quorum is not present on the expiration of thirty minutes from the time appointed for the meeting or during the course of any meeting, the meeting shall be adjourned to such further date and time as the President or any other person acting as the Chairman may appoint and at an adjourned meeting no quorum shall be necessary for transacting the business of the meeting so adjourned.
- 12. If the Chairman is absent, the Vice-President for the time being exercising the powers and discharging the functions of the President or in his absence, any other Vice-President in the same order, under regulation 5 shall act as the Chairman of the Executive Committee and in the absence of the President as well as all the Vice-Presidents the members shall elect one amongst themselves to act as the Chairman.
- 13. In the case of any vacancy which may occur during a recess, the Evecutive Committee may co-opt a member of the Central Council, representing the same system as the outgoing member, to fill the vacancy until the next meeting of the Council which shall elect one of its members to a member of the Evecutive Committee.
- 14. The Executive Committee may invite a member of the Central Council not being a member of the Executive Committee to attend any meeting of the Executive Committee, and any member so invited shall be free to participate in the discussions in the Executive Committee but shall not be entitled to vote.
- 15. The Fxecutive Committee shall ordinarily meet within one week before the meeting of the Central Council, and also at such other time and place, as the Chairman may determine.
- 16. Notice and agenda of every such meeting of the Executive Committee shall ordinarily be given 12 days before the meeting.
- 17. The Executive Committee shall consider and report on any subject referred to it by the Central Council or by the President and may with the sanction of the President direct the printing and circulation of such reports among member of the Central Council.
 - 18. (1) A copy of the minutes of each meeting of the Executive Committee shall be submitted to the President within 15 days of the meeting and after having been attested by him shall be sent to each member of the Committee within 30 days of the meeting.
 - (2) If no objection to their correctness is received within 21 days of their despatch, any decisions therein shall be given effect to, provided that the President may, where in his opinion it is necessary or expedient so to do, direct that action be taken on a decision of the Executive Committee before the expity of the period of fifteen days mentioned above.
 - (3) The attested minutes of the Executive Committee shall as soon as possible be sent to the member of the Central Council by the Registrar.

PART III COMMITEES

19. The Central Council may at any time on the adoption of a motion to this effect appoint a committee (other than

- the Executive Committee) consisting of any number of its member or resolve itself into a committee for the consideration of any business.
- 20. A member may at any time without notice move a motion that a Committee of the Central Council be appointed or that the Council may resolve itself into a committee.
 - 21. (1) A motion for the appointment of a committee shall define the functions of the committee and the number of the member to be appointed thereon.
 - (2) Any member may without notice move a amendment to such motion proposing that the functions or the number of members of the committee be enlarged or reduced.
- 22. If a motion for the appointment of a Committee is adopted, any member may name the member to be appointed as members of the Committee and any member may then move amendments proposing any addition or deletion of the name and membership shall be decided on the basis of approval of the majority present
- 23. If the number of persons proposed as members of the Committee does not exceed the total member of members to form the committee, the persons so proposed shall be appointed as member of Committee
 - 24. (1) The quorum for a committee (other than the Executive Committee) appointed by the Central Council shall be determined at the time of the appointment of the committee and shall not be less than one-third of the members appointed.
 - (2) The Chairman of every such committee shall be appointed by the Central Council at the time of the appointment of the committee.
- 25. The Registrar, Central Council, shall be the Secretary of every such committee.
- 26. The proceedings of the Committee shall be conducted in accordance with the regulations contained in this Part.
- 27. A resolution passed by the committee of the whole Council shall be embodied in a report prepared by the Registrar and signed by the President and shall have no effect unless confirmed by the Central Council at a meeting.
- 28. A resolution passed by a committee appointed by the Central Council shall be embodied in a report prepared by the Registrar or by the Chairman at the latter's discretion and when signed by the members of the committee with any notes of dissent shall be presented to the Central Council at its next meeting, subject to the provisions regarding notice.

PART IV

TIME AND PLACE OF AND PREPARATION OF BUSINESS FOR MEPTINGS OF THE CENTRAL COUNCIL

29. The meetings of the Central Council shall ordinarily be held at Delhi or at such other place in India and on such dates as may be fixed by the Executive Committee;

Provided that the President may call a special meeting at any time on 15 days notice—

- (i) to deal with any ureent matter requiring the attention of the Central Council, or
- (ii) on a requisition in writing signed by not less than 24 members and stating the purpose other than that mentioned in the first proviso to clause (b) of regulation 34 and for a purpose within the scope of the Central Council's functions for which they desire the meeting to be called.
- 30 The first meeting of the Central Council held in any financial year shall be the annual meeting of the Council for that year.
- 31. At any meeting referred to in the proviso to regulation 29 only the subject or subjects for the consideration of which the meeting has been called shall be discussed.

32 NOTICE OF MEETINGS:-

Notice of every meeting other than a special meeting called under the proviso to regulation 29 or under the first proviso

to clause (h) of regulation 34 shall be despatched by the Registrar to each member of the Central Council not less than 30 days before the date of the meeting.

33. .1GEND.4 PAPERS :-

- (1) The Registrar shall, with the notice of the meeting, issue preliminary (gend) paper showing the business to be brought before the meeting, the terms of all motions to be moved for which the notice in writing has previously reached him and the names of
- (2) A member who wishes to move any motion not included in the preliminary agenda paper or amendment to any motion so included shall give notice thereof to the Registrar not less than 15 clear days before the date fixed for the meeting.
- (3) The Registrar shall, not less than 15 clear days before the date fixed for the meeting or in the case of a special meeting, with the notice of the meeting, issue a complete agenda paper showing the business to be brought before the meeting.
- (4) A member who wishes to move an amendment to any item included in the complete agenda paper shall give notice thereof to the Registrar not less than 3 clear days before the date fixed for the meeting.
- (5) The Registrar shall if time permits, cause a list of amendments of which notice has been given under clause (4) to be made available for the use of every member:

Provided that the President may if the Central Council agrees allow a motion to be discussed at a meeting notwithstanding the fact that notice received late:

Provided further that nothing in this regulation shall operate to prevent the reference by the Executive Committee of any matter to the Central Council at a meeting following immediately or too soon after the meeting of the Executive Committee to permit of the notice required under this regulation

ADMISSIBILITY OF MOTION :-

- 34. The President shall disallow any motion:
 - (n) if the matter to which it relates is not within the scope of the Central Councils functions; or
 - (b) if it raises substantially the same question as a motion or amendment which has been moved or withdrawn with the leave of the Central Council within one year of the date of the meeting at which it is designed to move:

Provided that such a motion be admitted at a special meeting of the Central Council convened for the purpose on the requisition of not less than 2/3 of the members of the Central Council:

Provided further that nothing in these regulations shall operate to prohibit the further discussion of any matter referred to the Central Council by the Government of India in the exercise of any of its functions under the Act:

- (c) if it is not clearly and precisely expressed and does not raise substantially one definite issue; or
- (d) if it contains arguments; inferences, ironical expres-

Provided that if a motion can be rendered admissible amendment, the President may, in lieu of disallowing the motion, admit it in an amended

35. When the President disallows or amends a motion, the Registrar shall inform the member who gave notice of the motion of the order of disallowance or, as the case may be, of the form in which the motion has been admitted.

PART V

CONDUCT OF BUSINESS OF MEETINGS OF THE CENTRAL COUNCIL

36. Every meeting of the Central Council shall be presided over by the President or if he is absent, by one of the Vice-

President in the order given in subspecialitien (1) freque lation 5 or if the President and the Vice-Presidents are absent, by a Chairman to be elected by the members present from among themselves.

Note:

All references in this part to the President shall be read as reference to the person for the time being presiding over a meeting.

- 37. If at any time appointed for a meeting or during the course of a meeting quorum is not present, the meeting shall be adjourned and if a quorum is not present on the expiration of thirty minutes for the time appointed for the meeting or during the course of any meeting, the meeting shall stand adjourned to such future time as the President may appoint.
 - 38. (1) Every matter to be determined by the Central Council shall be determined on a motion moved by a member.
 - (2) Every motion or amendment shall be seconded and if not seconded shall be deemed to have been withdrawn.
 - (3) When a motion has been seconded, it shall be stated from the Chair.
 - (4) When a motion has been thus stated, it may be discussed as a question to be resolved either in the affirmative or in the negative or any member may subject to regulation 40 move an amendment to the motion:

Provided that the President shall not allow an amendment to be moved which if it had been a substantive motion would have been inadmissible under regulation 34.

- 39. When motions identical in purport stand in the names of two or more members, the President shall decide whose motion shall be moved and the other motions shall thereupon he deemed to be withdrawn.
 - 40. (1) An amendment shall be relevant to and within the scope of the motion to which it is proposed.
 - (2) An amendment may not be moved which has merely the effect of a negative vote.
 - (3) The President may refuse to put to the Central Council, an amendment, which, in his opinion, is frivolous.
 - 41. A motion may be amended by :-
 - (a) the omission, insertion or addition of words, or
 - (b) the substitution of words for any of the original words.
- 42. When a motion or amendment is under debate, no proposal with reference thereto shall be made other than-
 - (a) an amendment of the motion or of the amendment, as the case may be, as proposed in regulation 38;
 - (b) a motion for the adjournment of the debate on the motion or amendment either to a specified date and hour or sine-dic;
 - (c) a motion for the closure, namely, a motion that the question be now put:
 - (d) a motion that the Central Council instead of procerding to deal with the motion, do pass to the next item on the agenda;

Provided that no motion of the nature referred to in clause (b), (c) or (d) shall be moved or seconded by a member who has already spoken on that matter.

- 43. It shall be in the discretion of the President to put or refuse to put to the Central Council a preposal of the nature referred to in clause (b) of regulation 42
- 44. Unless the President is of the opinion that a motion for closure is an abuse of the right of reasonable debate, he shall forth-with put a motion that the question be now put and if that motion is carried, the substantive motion or amendment under debate shall be put forthwith.

Provided that the President may allow the mover of the substantive motion to exercise his right of reply before the substantive motion under debate is put.

- 45. A motion or an amendment which has been moved and seconded shall not be withdrawn save with leave of the Central Council which shall not be deemed to be graned if any member dissents from granting of the leave.
- 46. When a motion has been moved and seconded, members other than the mover and the seconder may speak on the motion in such order as the President may direct;

Provided that the seconder of a motion or an amendment may with the parmission of the President confine himself to seconding the motion or amendment as the case may be and speak thereon at any subsequent stage of the debate.

- 47. During the meeting the President may at any time make any objection or suggestion to a point to the member in discussion.
 - 48. (1) The mover of a motion, and if permitted by the President, the mover of any amendment shall be entitled to right to final reply; no other member shall speak more than once to any debate except with the permission of the President for the purpose to make a personal explanation or of putting a question to the member then addressing the Council:

Provided that any member at any stage of the debate may rise to a point of order but no speech shall be allowed on that point:

Provided further that a member who has spoken on a motion may speak again on an amendment subsequently moved to the motion.

(2) No member shall, save with the permission of the President, speak for me.c than five minutes:

Provided that the mover of a motion when bringing the same may speak for ten minutes.

- (3) The speech shall be strictly confined to the subject matter of the motion of an amendment, which is under discussion.
- (4) Any motion or amendment standing in the name of a member who is absent from the meeting or unwilling to move it, may be brought forward by the other member with the permission of the President.
- 49. (1) A member desiring to make any suggestion on the matter before the Central Council shall speak from his place, shall rise in his seat, and shall address the President.
 - (2) If at any time the President speaks, any member speaking shall immediately resume his seat.
- 50. (1) When an amendment to any motion is moved and seconded or when two or more such amendments are moved and seconded, the President shall before taking the sense of the Central Council thereon state to the Council the terms of the original motion and of the amendment or amendment proposed.
 - (2) An amendment to a motion shall be put to the vote
 - (3) If there be more than one amendment to a motion, the President shall decide in what order they shall be taken.
- 51. When any motion involving several points has been discussed, it shall be in the discretion of the President to divide the motion and put each or any point separately to vote as he may think it.
 - 52 (1) Vote shall be taken by show of hands or by division or by ballot as the President may direct:

Provided that votes shall be taken by ballot if three members so desire or ask for it.

Provided further that if voting has been by show of hands, division shall be taken if any member asks for it

(2) The President shall determine the method of taking votes by division.

- (3) The result of the votes shall be announced by the President and shall not be challenged.
- (4) In the event of equality of votes, the President shall have a second or easting vote.
- 53. (1) The President may, if deems necessary due to exigencies, at any time, adjourn any meeting to any future date or to any hour of the same date.
 - (2) Whenever a meeting is adjourned to a future date, the Registrar shall, if possible, send notice of the adjournment to every member, who was not present at such meeting.
 - (3) When a meeting has been adjourned to a future date, the President may change such date to any other date and the Registrar shall send written notice of the change to each member, and atleast 7 days before such meeting.
 - (4) At a meeting adjourned to a future date any motion standing over from the previous date, shall unless the President, otherwise directs, takes precedence over other matters on the agenda.
 - (5) Either at the beginning of the meeting or after the conclusion of the debate on a motion during the meeting, the President or a member may suggest a change in the order of business on the agenda and if the Central Council agrees such a change shall take place.
 - (6) No matter which had not been on the agenda of the original meeting shall be discussed at an adjourned meeting.
- 54. (1) The President shall decide all points of order which may arise and his decision shall be final.
 - (2) If any question arises with reference to procedure in respect of a matter for which these regulations make no provision, the President shall decide the same and his decision shall be final.
- 55. (1) Five representatives of the Press, at the discretion of the President, and other visitors not exceeding five at a time may be admitted to the meeting on the production of permits from the Registrar.
 - (2) A Press representative shall be required to obtain previous approval of the Registrar to the publication of any report of the proceeding.
 - (3) The President may at any time hold the meeting in Camera in which case all the Visitors shall be required to withdraw.

PART VI

MINUTES OF THE CENTRAL COUNCIL

- 56. The proceedings of the meetings of the Central Council shall be preserved in the form of minutes which shall be authenticated after confirmation by the signature of the President.
- 57. A copy of the minutes of each meeting shall be submitted to the President within 10 days of the meeting and attested by him and than it is to be sent to each member within 30 days of the meeting.
- 58. The minutes of each meeting shall contain such motion and amendments as have been moved and adopted or negatived with the names of the mover and the seconder but without any comment and without any record of observations made by any member in the meeting.
 - 59. (1) If any objection regarding the correctness of the minutes is received within 30 days of the despatch of the minutes, such objection together with the minutes as recorded and decided shall be put before the next meeting of the Central Council for confirmation by the Registrar. At this meeting the question shall be confined only to the correctness of records of the meeting.
 - (2) Every decision of the Central Council shall be given effect to after the period of thirty days of the despatch of the minutes:—
 - (i) If no objection as to its correctness is received from any member, or

- (ii) in case objections are not received from majority of the members present in the meeting, is in the opinion of the President necessary or expedient so to do.
- 60. The minutes of the Central Council shall, as soon as is practicable after their confirmation, be made up in sheets and consecutively paged for insertion in a volume which shall be permanently preserved.
 - 6¹ (1) A copy of such volume shall be supplied free to each member of the Central Council.
 - Such copies may be sold to the public at a price to be fixed by the Central Council.
 - 62. (1) A report shall be kept of the observations and of the discussions at the meetings of the Central Council in as accurate a manner as possible for the use of the members of the Council.
 - A detailed verbatim proceedings of the meetings shall be treated as confidential and shall be kept in the Office and shall be open to members for inspection.
 - (3) A copy of the proceedings in whole or in part shall be supplied to any member who may apply for it but every such copy shall be marked confidential and be supplied on payment of a sum to be fixed by the President which shall not exceed the cost of copying.
- 63. No copy of proceedings held in camera shall be supplied but such proceedings may be open to inspection by the members.

PAR l' VII

REGISTRATION AND FILLING OF CASUAL VACANCIES

- 64. A member desiring to resign his seat on the Central Council shall send his resignation in writing to the President and every such resignation shall take effect from the date mentioned by him in this behalf or in case no such date is mentioned, from the date of the receipt of his letter by the President after confirmation from the member concerned about his resignation.
- 65. When a casual vacancy occurs by reason of the death, resignation or otherwise of a member, a report shall be made forthwith by the President to the Central Government which shall take steps to have the vacancies filled by nomination or election. as the case may be.

PART VIII

TENURE OF OFFICE AND POWERS AND DUTIES OF REGISTRAR AND OTHER EMPLOYEES OF THE CENTRAL COUNCIL

66. The term of office of the Registrar shall be fixed by the Central Council at the time of appointment but he shall normally retire on attaining the age of 58 years:

Provided that extension may be given by the Central Council in exceptional circumsances and with the prior approval of the Central Government.

- 67 (1) The Registrar shall be the executive officer of the Central Council.
 - (2) The Registrar shall be responsible for the safety of the property of the Central Council and the control and management of the office/accounts/correspondence and shall allot and supervise the work of other employees of the Council and perform such other duties as may be required of him by the Council for the purposes of the Act. He shall attend the proceedings of meetings of the Council and Executive Committee and all other committees/subcommittees constituted by the Council.
- 68. The Registrar shall, not less than 90 days before the expiration of the term of any member, draw the attention of the President to the approaching vacancy and the latter shall forthwith report it to the Central Government for further necessary action.

69. Other employees of the Central Council shall be required to retire on attaining the age of 58 years.

Provided that extension may be given in exceptional cucumstances upto two years.

70. The powers and duties of the other employees shall be such as may be laid down from time to time in the standing orders as may be framed for the purposes by the Central Council.

PART IX

FINANCE AND ACCOUNTS

- 71. The Central Council is authorised to receive for the purposes of its expenses, benefactions and contributions from private persons and bodies and the trustees and proceeds of the sale of all reports and other publications.
 - (1) "The bankers of the Central Council shall be Bank of India body corporate constituted under Banking Company (acquisition and transfer of undertaking) Act, 1970.
 - (2) All funds of the Council shall be paid into the Council's accounts with the Bank of India and shall be withdrawn by means of cheques jointly signed by the President or in his absence Vice-President and the Registrar. The cheque books shall remain in the Personal custody of the Registrar."
- 73. The funds of the Central Council, surplus to current requirements, may on a recommendation by the Treasurer and with the sanction of the Executive Committee be invested in the following manner, namely:—
 - (a) In National Saving Certificates, units issued by the Unit Trust of India or other securities of any State Government or of the Government of India.
 - (b) In debentures or other securities for money issued under the authority of an Act of the legislature, established in India or on behalf of any municipal body, Port Trust or City Improvement Trust.
 - (c) In fixed deposits with the Bank of India or any other bank specified in column 2 of the First Schedule to the Banking companies (Acquisition and Transfer of undertakings) Act, 1970 (5 of 1970).
 - 74. (1) Any investment of the funds of the Central Council shall be made in the name of the Central Council.
 - (2) The receipts shall remain in the personal charge of the Registrar and shall be verified once in six months, with register of securities maintained under regulation 84 and certificate of verification shall be recorded by the Registrar on the register and countersigned by the President.
- 75. Registrar shall prepare detailed estimates of the receipts and expenditure for the next financial year and shall submit the same for the sanction of the Executive Committee at the meetings to be held for the purpose before the first November every year.
- 76. One copy of the finally sanctioned estimates shall be supplied by the first November to the Secretary, Department of Health, Ministry of Health and Family Welfare, New Delhi.
- 77. The funds of the Central Council shall not be appropriated for expenditure or any item which has not been duly sanctioned by the Council or by the President or by the Registrar, as the case may be.
- 78. The primary units of the appropriation shall be pay and allowances staff, contigencies, travelling allowances, honoraria, leave pension and Provident Fund contributions.
- 79. The President shall have power to appropriate funds from the one unit of appropriation to another within the total, sanctioned estimates.
- 80. Copies of orders on such re-appropriation shall be communicated to the Executive Committee.
- 81. The Registrar shall have power to sanction expenditure of miscellaneous and contingent nature upot an amount not

exceeding Rs. 500/- in each case and expenditure in excess of this amount shall require the sanction of the President.

- 82. A period next advance of Rs. 500/- shall be made to the Registrer.
- 83. The Registrar shall be the certifying officer for travelling, halting and other allowances to members, inspectors, visitors and environces of the Central Council.
- 84. The following account registers of the Central Council shall be maintained, namely :-
 - 1. Cash Boso
 - 2 The Classified Abstract
 - 3. The Regator of Securities.
 - 4. The Register of stock and furniture.
 - 5. The Regimen of stock of cheque books.
 - 6 The Register of leave and pension contributions.
 - 7. The Register of permanent advances.
 - 8. Annual accounts.
- 85. Monthly accounts shall be compiled in the classified abstracts according to the primary units of appropriation. Suitable secondary units may be opened at the discretion of the Registrar who shall be responsible for the due preparation and maintenance of all accounts.

- 86. (1) The Accounts of the Council shall be audited annually by the Comptroller and Auditor General of India or his nominee. If the Comptroller and Auditor General of India declines to undertake the auditing of the accounts of the Council, the Council may appoint a Chartered Accountant with the prior approval of the Central Government. Any expenditure incurred in connection with such audit shall be payable by the Council.
- (2) The Comptroller and Auditor General of India and any person appointed by him in connection with the audit of the accounts of the Council shall have the right, privileges and authority in connection with such audit as the Comptroller and Auditor General has in connection with the audit of Government accounts and in particular shall have the right to demand the production of books, accounts, connected vouchers and other necessary documents and papers.
- (3) The result of the audit shall be communicated by the Auditor to the Council and after the Executive Committee has considered the same, the audit report and the audited statement of accounts shall be forwarded to the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India. Copies of the Audit Report shall at the same time be circulated to all the members of the Council, for information.

Provided, however, if release of Government grant is held up for want of audited accounts. President may forward the audited accounts to the Central Government immediately on receipt of the same from the Auditor.